



केन्द्रीय विद्यालय संगठन



राँची संभाग

अध्ययन सामग्री

वर्ग XII

विषय – अर्थशास्त्र

सत्र – २०२३-२४

मुख्य संरक्षक



श्री डी. पी. पटेल
उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
राँची संभाग

संरक्षक	
श्री सुरेश सिंह	सहायक आयुक्त
श्रीमती सुजाता मिश्र	केन्द्रीय विद्यालय संगठन
श्री बलेन्द्र कुमार	राँची संभाग
विषय संयोजक	
श्री नवेंदु पराशर प्राचार्य के. वि. मैथन डैम धनबाद	
विषय सह-संयोजक	
● श्रीमती अर्चना प्रसाद स्नातोकोत्तर शिक्षक, के. वि. गोमो	

ACKNOWLEDGEMENT

We are happy to provide the study material in the subject economics keeping in view the academic development of the student.

Firstly, we would like to thank SHRI DP PATEL honourable deputy commissioner, KVS RO Ranchi and Assistant Commissioner MRS SUJATA MISHRA for showing their concern for the students there by conceptualizing the preparation of the material.

We would also like to thank SHRI NAVENDU PARASHAR , principal KV MAITHON DAM , who has guided us through out to prepare the material.

This study material is a ready reckoner for the students of Economics it will help the student in conceptual clarity. The effort has been made to instill confidence in the student and help the child score good marks.

We, the editorial team feel proud to contribute for the academic development of the children and enhance the qualitative and quantitative result of KVS RO Ranchi.

With Best Wishes,

Regards'

Editorial Team.

Compiled By:

Sl. No	Name of the Teachers	Name of the KV
1.	MR. Abhay Kumar	K.V Bokaro No:1
2.	MR. Rahul	K.V Patratu
3.	MR. Vikash Kumar Gupta	K.V Maithon Dam

Prepared BY

Sl. No.	Content	Name of Teacher
1.	National Income And Related Aggregates	MR. RAHUL MR. V. KUJUR
2.	Money And Banking	MR. RAHUL MRS. SEEMA NAG
3.	Determination Of Income And Employment	MR. PRAMOD KR. GAUTAM MRS. S. BARA
4.	Government Budget And Economy	DR. ASHISH KUMAR
5.	Balance Of Payments	MR. RAHUL MRS. F. TUDU
6.	Development Experience (1947-90) And Economic Reforms Since 1991	MR. ABHAY KUMAR MR. U. C. SURYAVANSHI
7.	Current Challenges Facing Indian Economy	MR. V. K. GUPTA MR. H.S. RAM MR. T. N. TIWARI MRS. ARCHANA PRASAD
8.	Development Experience Of India – A Comparison With Neighbours	MRS. RAKHEE SINGH
9.	Sample Paper	MR. ABHAY KUMAR MRS. ARCHANA PRASAD

INDEX

Sl. No.	Content	MARKS	Page No.
1.	National Income And Related Aggregates	10	6-13
2.	Money And Banking	6	13-16
3.	Determination Of Income And Employment	12	16-26
4.	Government Budget And Economy	6	26-32
5.	Balance Of Payments	6	32-39
6.	Development Experience (1947-90) And Economic Reforms Since 1991	12	39-50
7.	Current Challenges Facing Indian Economy	20	50-65
8.	Development Experience Of India – A Comparison With Neighbours	8	56-72
9.	Sample Paper	N.A.	72-87

इकाई I: राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय

समष्टि अर्थशास्त्र :- समष्टि अर्थशास्त्र किसी अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन है।

उपभोग वस्तुएँ :- वे हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतिम वस्तु के रूप में खरीदी जाती हैं।

उदाहरण : टिकाऊ माल, जैसे- कार, टेलीविजन, रेडियो आदि।

गैर-टिकाऊ सामान, और सेवाएँ जैसे- फल, तेल, दूध, सब्जी आदि।

अर्ध टिकाऊ सामान, जैसे- क्रॉकरी आदि।

पूँजीगत वस्तुएँ- पूँजीगत वस्तुएँ वे अंतिम वस्तुएँ हैं, जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है। जैसे: संयंत्र, मशीनरी आदि।

अंतिम वस्तुएँ : वे वस्तुएँ हैं जिनका उपयोग या तो अंतिम उपभोग के लिए या निवेश के लिए किया जाता है। इसमें अंतिम उपभोक्ता वस्तुएँ और अंतिम उत्पादन वस्तुएँ शामिल हैं। वे पुनर्विक्रय के लिए नहीं हैं। इसलिए, इन वस्तुओं में कोई मूल्य नहीं जोड़ा जाता है। इनका मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है।

मध्यवर्ती वस्तुएँ: वे वस्तुएँ हैं, जिनका उपयोग या तो पुनर्विक्रय के लिए या आगे के उत्पादन के लिए किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण है- एक चाय की दुकान द्वारा चाय बेचने के लिए उपयोग किया जाने वाला दूध।

स्टॉक :- एक आर्थिक चर की मात्रा जो किसी विशेष समय पर मापी जाती है। स्टॉक का कोई समय आयाम नहीं है। स्टॉक स्थिर अवधारणा है।

जैसे: धन, टंकी में पानी।

प्रवाह : प्रवाह किसी आर्थिक चर की वह मात्रा है, जिसे समयावधि के दौरान मापा जाता है। प्रवाह का समय आयाम होता है - जैसे प्रति घंटा, प्रति दिन आदि। प्रवाह एक गतिशील अवधारणा है।

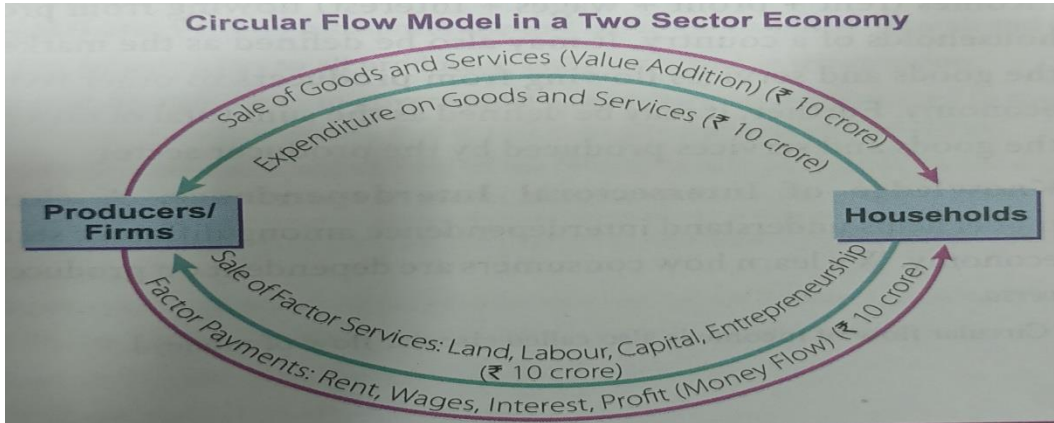
जैसे: निवेश, एक धारा में पानी।

निवेश : निवेश पूँजी के मौजूदा स्टॉक में की गई शुद्ध वृद्धि है।

शुद्ध निवेश = सकल निवेश - मूल्यहास।

मूल्यहास :- मूल्यहास का तात्पर्य सामान्य टूट-फूट, समय बीतने और अपेक्षित अप्रचलन के कारण अचल संपत्तियों के मूल्य में गिरावट से है।

दो क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह।



दो क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में निर्माता (फर्म) और परिवार घटक होते हैं।

परिवार फर्मों को उत्पादन के कारक देते हैं और फर्म बदले में घरों को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करती हैं। इसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। फर्म परिवारों को कारक भुगतान देती हैं और परिवार वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं। इसे मनी प्रवाह कहा जाता है।

संबंधित समुच्चय

1. **बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद** : यह एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, जिसमें मूल्यहास भी शामिल है।

2. **बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद** : यह एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, मूल्यहास को छोड़कर।

$GDP_{mp} = NDP_{mp} + \text{मूल्यहास}$

और, $NDP_{mp} = GDP_{mp} - \text{मूल्यहास}$

3. **बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद** : यह बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद और विदेश से शुद्ध कारक आय का कुल योग है।

$$\text{GNPmp} = \text{GDPmp} + \text{विदेशों से शुद्ध कारक आय}$$

4. **बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद** : यह बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेश से शुद्ध कारक आय का कुल योग है।

$$\text{NNPmp} = \text{NDPmp} + \text{विदेश से शुद्ध कारक आय}$$

5. **कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद** : यह किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर मूल्यहास सहित बीमाकृत कारक लागत का कुल योग है।

6. **कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद** : यह एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर बीमाकृत कारक आय का कुल योग है।

7. **साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद** : यह साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद और विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय का कुल योग है।

$$\text{GNPfc} = \text{GDPfc} + \text{विदेश से शुद्ध कारक आय}$$

8. **साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद** : यह सदिश लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय का कुछ योग है।

$$\text{NNPfc} = \text{NDPfc} + \text{विदेश से शुद्ध कारक आय}$$

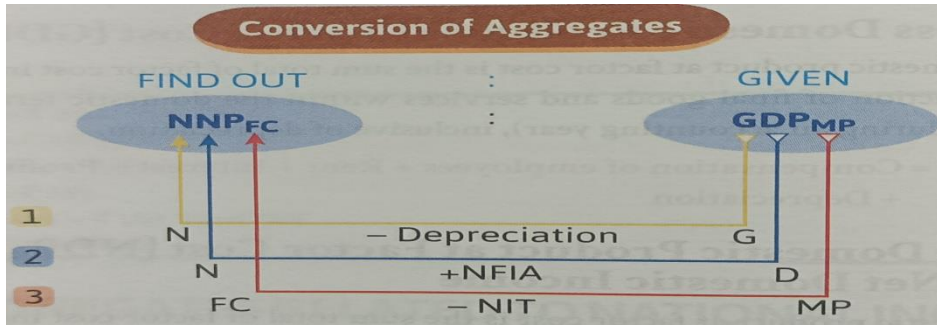
विदेश से शुद्ध कारक आय :

हमारे निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित कारक आय और हमारे देश में गैर-निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के बीच अंतर।

विदेश से शुद्ध कारक आय के घटक

- कर्मचारियों का शुद्ध मुआवजा
- संपत्ति और उद्यमिता से शुद्ध आय (विदेश की निवासी कंपनियों की प्रतिधारित आय के अलावा)
- विदेश में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय

Conversion rules:



घरेलू (आर्थिक) सीमा की अवधारणा

घरेलू सीमा सरकार द्वारा प्रशासित एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसके भीतर व्यक्ति, सामान और पूंजी स्वतंत्र रूप से प्रसारित होती है।

* प्रादेशिक जल और वायु क्षेत्र सहित राजनीतिक सीमाएँ।

* दूतावास, वाणिज्य दूतावास, सैन्य अड्डे आदि विदेश में स्थित हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक सीमाओं के भीतर स्थित स्थान भी शामिल हैं।

* दो या दो से अधिक देशों के बीच निवासियों द्वारा संचालित जहाज, विमान आदि।

* मछली पकड़ने के जहाज, तेल और प्राकृतिक गैस रिग आदि अंतर-राष्ट्रीय जल या अन्य क्षेत्रों में निवासियों द्वारा संचालित होते हैं जिन पर देश को विशेष अधिकार या क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

सामान्य निवासी :-

सामान्य निवासी वह व्यक्ति या संस्था है जो सामान्यतः उस देश में रहता है और जिसके आर्थिक हित का केंद्र उस देश में है।

आर्थिक हित के केन्द्र का तात्पर्य है :-

1. निवासी आर्थिक क्षेत्र में रहता है या स्थित है।
2. निवासी उस स्थान से कमाई, खर्च और संचय की बुनियादी आर्थिक गतिविधियाँ करता है।
3. उनकी रुचि का केंद्र वह देश है।

राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ

I - उत्पाद विधि (मूल्य वर्धित विधि) :

- उत्पादन का मूल्य = बिक्री + स्टॉक में बदलाव
- स्टॉक में परिवर्तन = अंतिमस्टॉक - आरंभिकस्टॉक
- सकल मूल्यवर्धित (GDPmp) = उत्पादन का मूल्य - मध्यवर्तीउपभोग
- $NNPfc = GDPmp (-)$ निश्चित पूंजी की खपत (मूल्यहास) (+) विदेश से शुद्ध कारक आय (-) शुद्ध अप्रत्यक्ष कर।

II. आय विधि :

1. कर्मचारियों का मुआवजा.
2. परिचालन अधिशेष: किराया + ब्याज + लाभ + रॉयल्टी
यदि लाभ नहीं दिया गया है तो उपयोग करें (लाभांश + कॉर्पोरेट टैक्स + अवितरित लाभ)
3. स्व-रोज़गार की मिश्रित आय।
 - $NDPfc = (1) + (2) + (3)$
 - $NNPfc = NDPfc (+)$ विदेश से शुद्ध कारक आय
 - $NDPmp = NDPfc +$ स्थिर पूंजी की खपत + शुद्ध अप्रत्यक्ष कर

III. व्यय विधि :

1. सरकारी अंतिम उपभोग व्यय।
2. निजी अंतिम उपभोग व्यय।
3. शुद्ध निर्यात।
4. सकल घरेलू पूंजी निर्माण।

$$GDPmp = (1) + (2) + (3) + (4)$$

$$NNPfc = GDPmp - \text{स्थिर पूंजी की खपत} + NFIA - \text{शुद्ध अप्रत्यक्ष कर}$$

सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण :

वास्तविक जीडीपी को लोगों के कल्याण का सूचकांक माना जाता है। लोगों का कल्याण प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की क्षमता के आधार पर मापा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अर्थ है अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में वृद्धि। अन्य चीजें स्थिर रहती हैं, इसका अर्थ है प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की अधिक उपलब्धता, जिसका अर्थ है उच्च स्तर का कल्याण।

सीमाएँ :

जीडीपी और कल्याण पूर्ण विराम के बीच सकारात्मक संबंध से संबंधित कुछ सीमाएँ हैं :

1. **आय का वितरण :** यदि आय का वितरण असमान होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि सामाजिक कल्याण में प्रतिबिंबित नहीं हो पाती है। भारत इस समय इसी स्थिति का सामना कर रहा है। जबकि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, भूख से मौतें पहले से कहीं अधिक बार सुर्खियों में आ रही हैं। क्योंकि आय का वितरण लगातार असमान होता जा रहा है।
2. **जीडीपी का वितरण :** जीडीपी की संरचना कल्याण उन्मुख नहीं हो सकती है। रक्षा वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि से लोगों के कल्याण में कोई प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं होती है। बेशक मजबूत रक्षा देश में शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करती है लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक कल्याण में योगदान देती है।
3. **गैर-मौद्रिक विनिमय :** ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विनिमय की बेहतर प्रणालियाँ अभी भी कुछ हद तक प्रचलित हैं। खेतिहर मजदूरों को भुगतान अक्सर नकद के बजाय वस्तु के रूप में किया जाता है। ऐसे सभी लेन-देन रिकार्ड नहीं किये जाते। जीडीपी के आकलन के तहत ये हैं कारण जिस हद तक जीडीपी अनुमान से कम रहता है, वह कल्याण का एक अनुचित सूचकांक बना रहता है।
4. **बाह्यताएँ :** यह किसी आर्थिक गतिविधि के अच्छे और बुरे प्रभाव को उसके लिए कीमत या जुर्माना चुकाए बिना संदर्भित करता है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की बाह्यताएँ हैं। नकारात्मक बाह्यताएँ तब घटित होती हैं जब उदाहरण के लिए कारखानों से निकलने वाला धुआँ वायु प्रदूषण का कारण बनता है या औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में प्रवाहित किया जाता है जिससे जल प्रदूषण होता है। इससे सामाजिक कल्याण की हानि होती है। लेकिन ज्यादातर समय हम जीडीपी की गणना के दौरान इसे शामिल नहीं करते हैं। इसलिए, यह कल्याण का एक अनुचित सूचकांक है।

(MCQ)

1. सकल और शुद्ध के बीच अंतर है:

(ए) मूल्यहास (बी) एनएफआईए (सी) शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (डी) सव्सिडी

2. घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के बीच अंतर ____ है।

(ए) एनएफआईए (बी) शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (सी) मूल्यहास (डी) उपरोक्त सभी

3. यदि एनएफआईए नकारात्मक है,

(ए) विदेश से प्राप्त कारक आय विदेश से प्राप्त कारक आय से कम होगी
(बी) विदेश से प्राप्त कारक आय विदेश से प्राप्त कारक आय के बराबर होगी
(सी) विदेश से प्राप्त कारक आय विदेश से प्राप्त कारक आय से अधिक होगी
(डी) उपरोक्त में से कोई नहीं

4. यदि एनएफआईए सकारात्मक है,

(ए) एनडीपीएफसी = एनएनपीएफसी (बी) एनडीपीएफसी > एनएनपीएफसी
(सी) एनडीपीएफसी < एनएनपीएफसी (डी) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(ए) जीडीपीएमपी = आउटपुट का मूल्य- मध्यवर्ती खपत
(बी) एनडीपीएफसी = आउटपुट का मूल्य- मध्यवर्ती खपत
(सी) जीडीपीएफसी = बिक्री+स्टॉक में परिवर्तन
(डी) एनडीपीएमपी = बिक्री + स्टॉक में परिवर्तन

6. निम्नलिखित में से कौन कारक आय का घटक नहीं है?

(ए) कर्मचारियों का मुआवजा (बी) परिचालन अधिशेष
(सी) वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री (डी) स्व-रोज़गार की मिश्रित आय

7. निम्नलिखित में से कौन लाभ का घटक है?

(ए) कॉर्पोरेट टैक्स (बी) लाभांश
(सी) बरकरार रखी गई कमाई (डी) उपरोक्त सभी

8. निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू पूंजी निर्माण का हिस्सा है?

(ए) सकल निश्चित पूंजी निर्माण (बी) इन्वेंटरी निवेश
(सी) दोनों (ए) और (बी) (डी) उपरोक्त में से कोई नहीं

9. चालू वर्ष की कीमत पर उत्पादन कहलाता है:

(ए) नाममात्र जीडीपी (बी) वास्तविक जीडीपी (सी) राष्ट्रीय जीडीपी (डी) उपरोक्त में से कोई नहीं

10. यदि जनसंख्या बढ़ती है, तो:

(ए) सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि (बी) कल्याण में वृद्धि (सी) कल्याण में कमी (डी) दोनों (ए) और (सी)

Q. 1 स्टॉक और फ्लो के बीच अंतर

स्टॉक	प्रवाह
1. इसका अर्थ है किसी आर्थिक चर की वह मात्रा जिसे किसी विशेष समय पर मापा जाता है।	1. यह किसी आर्थिक चर की वह मात्रा है जिसे एक निश्चित समयावधि के दौरान मापा जाता है।
2. इसका कोई समय आयाम नहीं है।	2. इसका समय आयाम है।
3. यह एक स्थिर अवधारणा है।	3. यह एक गतिशील अवधारणा है।
4. उदाहरण: धन, टंकी पर पानी, बैंक जमा आदि।	4. उदाहरण: आय, निवेश, पूंजी निर्माण, चीनी की खपत आदि।

Q.2 घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर बताइये।

उत्तर: - घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर

घरेलू उत्पाद	राष्ट्रीय उत्पाद
घरेलू उत्पाद एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।	राष्ट्रीय उत्पाद एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।
इसमें देश के सभी निवासियों की आय शामिल है।	इसमें केवल देश के सामान्य निवासियों की आय शामिल है।
विदेश से शुद्ध कारक आय (एनएफआईएफए) इसमें शामिल नहीं है।	विदेश से शुद्ध कारक आय (एनएफआईएफए) इसमें शामिल है।

प्रश्न 3. मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु के बीच अंतर स्पष्ट करें।

मध्यवर्ती वस्तु	अंतिम वस्तु
वे वस्तुएँ जो पुनर्विक्रय या आगे के उत्पादन के लिए खरीदी जाती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएँ कहलाती हैं।	वे वस्तुएँ जो अंतिम उपभोग और निवेश के लिए होती हैं, अंतिम वस्तुएँ कहलाती हैं।
ये वस्तुएँ उत्पादन सीमा के भीतर हैं इसलिए इन वस्तुओं में और अधिक मूल्य जोड़ा जा सकता है।	ये वस्तुएँ उत्पादन सीमा से बाहर होती हैं इसलिए इन वस्तुओं में और मूल्य नहीं जोड़ा जा सकता।
इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है।	इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किया जाता है।

प्रश्न 4. मोद्रिक NNP और वास्तविक NNP के बीच अंतर बताएं

मोद्रिक NNP/वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय	वास्तविक NNP/स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय
यह एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसे चालू वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है।	यह एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसे आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है।
भौतिक उत्पादन में वृद्धि के बिना नाममात्र राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है	यह तभी बढ़ सकता है जब भौतिक उत्पादन में वृद्धि हो।
नाममात्र राष्ट्रीय आय कीमत में परिवर्तन के प्रभाव को समाप्त नहीं करती है।	यह कीमत में परिवर्तन के प्रभाव को समाप्त कर देता है

Q.5 जीडीपी डिफ्लेटर/अपस्फितिकारक (मूल्य सूचकांक) का अर्थ बताएं?

उत्तर: जीडीपी डिफ्लेटर/अपस्फितिकारक का उपयोग मूल्य परिवर्तन के प्रभाव को खत्म करने और चालू वर्ष के भौतिक उत्पादन में वास्तविक परिवर्तन निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह अंतिम सकल घरेलू उत्पाद में ली गई सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के औसत स्तर को मापता है।

मूल्य सूचकांक या जीडीपी डिफ्लेटर = (वास्तविक जीडीपी) / (नाममात्र जीडीपी) x 100

Q. 6 दोहरी गणना क्या है? इससे कैसे बचा जा सकता है?

उत्तर: उत्पादन के प्रत्येक चरण पर वस्तुओं के मूल्य की एक से अधिक बार गणना करना दोहरी गणना कहलाती है।

इससे बचा जा सकता है

- राष्ट्रीय आय की गणना में मूल्यवर्धित पद्धति अपनाना।
- राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तु का मूल्य लेने से

Q. 7 भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन में इन्हें किस प्रकार देखा जाता है। कारण दे।

ए) स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षकों को दिए जाने वाले मकान किराया भत्ते को कर्मचारियों के मुआवजे के रूप में माना जाता है, और इसे राष्ट्रीय आय के आकलन की आय पद्धति में शामिल किया जाता है।

बी) छात्रों द्वारा भुगतान की जाने वाली स्कूल फीस परिवारों का अंतिम उपभोग व्यय है क्योंकि यह स्कूल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में किया जाने वाला भुगतान है जिसे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की व्यय विधि में शामिल किया जाता है।

ग) डिबेंचर एक उत्पादन इकाई द्वारा ऋण का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, डिबेंचर पर दिया गया ब्याज एक कारक भुगतान है। इसे आय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है।

घ) नियोक्ताओं द्वारा वहन किया गया कर्मचारियों का चिकित्सा व्यय कर्मचारियों का मुआवजा है क्योंकि यह कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान है। इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है।

- ई) सार्वजनिक ऋण पर ब्याज सरकार के उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए लिए गए ऋण पर सामान्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान है। उपभोग ऋण पर ब्याज एक हस्तांतरण भुगतान है और राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है।
- च) किसी कारखाने द्वारा बिजली पर खर्च कारखाने की मध्यवर्ती लागत है और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की मूल्य वर्धित पद्धति के माध्यम से हिसाब लगाया जाता है।
- छ) किसी व्यापारी के पास पड़े स्टॉक की कीमत में वृद्धि एक पूंजीगत लाभ है और इससे कोई नया उत्पादन नहीं होता है। पूंजीगत लाभ हस्तांतरण आय है और इसमें राष्ट्रीय आय शामिल नहीं है।
- ज) विदेशी पर्यटकों द्वारा की गई खरीद को निर्यात के रूप में माना जाता है और व्यय विधि के माध्यम से शामिल किया जाता है।

Q. 8 गणना करें (i) कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद मर्दे

	रु. (करोड़ों में)
(i) शुद्ध अप्रत्यक्ष कर	130
(ii) सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	100
(iii) लाभ	90
(iv) शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण	120
(v) स्टॉक में परिवर्तन	(-) 10
(vi) निजी अंतिम उपभोग व्यय	500
(vii) शुद्ध आयात	20
(viii) विदेश में शुद्ध चालू स्थानान्तरण	10
(ix) विदेश में शुद्ध कारक आय	30
(x) सकल घरेलू पूंजी निर्माण	160

प्र. 9 निम्नलिखित आंकड़ों से एफसी पर जीएनपी की गणना (ए) आय विधि (बी) व्यय विधि द्वारा करें मर्दे रु. (करोड़ों में)

(i) शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण	500
(ii) कर्मचारियों का मुआवजा	1850
(iii) स्थिर पूंजी की खपत	100
(iv) सरकार। अंतिम उपभोग व्यय	1100
(v) प्राइवेट. अंतिम उपभोग व्यय	2600
(vi) किराया	200
(viii) ब्याज	500
(ix) शुद्ध निर्यात	(-) 100
(x) लाभ	1100
(xi) NFIA	(-) 50
(xi) शुद्ध अप्रत्यक्ष कर	250

Q. 10 एक अर्थव्यवस्था में केवल दो उत्पादक क्षेत्र A और B हैं। गणना करें: (ए) प्रत्येक क्षेत्र द्वारा बाजार मूल्य पर जोड़ा गया सकल मूल्य (बी) राष्ट्रीय आय।

मर्दे	रु. (करोड़ों में)
(i) विदेश से शुद्ध कारक आय	20
(ii) A द्वारा बिक्री	1000
(iii) B द्वारा बिक्री	2000
(iv) B के स्टॉक में बदलाव	(-) 200
(v) A का अंतिम स्टॉक	50
(vi) A का शुरुआती स्टॉक	100
(vii) A और बी द्वारा निश्चित पूंजी की खपत	180
(viii) A और बी द्वारा भुगतान किया गया अप्रत्यक्ष कर	120
(ix) A द्वारा कच्चे माल की खरीद	500
(x) B द्वारा कच्चे माल की खरीद	600
(xi) B द्वारा निर्यात	70

Q. 11 निम्नलिखित आंकड़ों से, गणना करें (A) कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपीएफसी) और (B) विदेश में कारक आय।

मर्दे	रु. (करोड़ों में)
(i) सकल घरेलू पूंजी निर्माण	600
(ii) ब्याज	200
(iii) बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद	2800
(iv) किराया	300
(v) कर्मचारियों का मुआवजा	1600
(vi) लाभ	400
(vii) लाभांश	150
(viii) विदेश से कारक आय।	50
(ix) स्टॉक में बदलाव	100
(x) शुद्ध अप्रत्यक्ष कर	240
(xi) शुद्ध स्थिर पूंजी निर्माण	400
(xii) शुद्ध निर्यात	(-) 30

प्र. 12 गणना करें (ए) बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपीएमपी) (बी) विदेश से कारक आय।

मर्दे	रु. (करोड़ों में)
(i) लाभ	500
(ii) निर्यात	40
(iii) कर्मचारियों का मुआवजा	1500
(iv) शुद्ध वर्तमान स्थानांतरण	2800
(v) किराया	90
(vi) ब्याज	300
(vii) विदेश में कारक आय	400
(viii) शुद्ध अप्रत्यक्ष कर	120
(ix) सकल स्थिर पूंजी निर्माण	250
(x) शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण	650
(xi) सकल स्थिर पूंजी निर्माण	700
(xii) स्टॉक में परिवर्तन	50

मुद्रा और बैंकिंग

मुद्रा: मुद्रा वह चीज है जिसका उपयोग आम तौर पर विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप, मूल्य के भंडारण और मानक आस्थगित भुगतान के साधन के रूप में किया जाता है।

भारत में मौद्रिक प्रणाली

- भारत में मौद्रिक प्राधिकारी 'भारतीय रिजर्व बैंक' है।
- भारत में कागजी मुद्रामानक का पालन किया जाता है।
- सिक्कों को सीमित वैध मुद्रा माना जाता है।
- भारत में मुद्रा जारी करने का एक मात्र एकाधिकार RBI के पास है।
- भारत में वित्त मंत्रालय 1 रुपयेके सिक्के और नोट जारी करता है।
- भारत नोट जारी करने के लिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का पालन करता है। इसका मतलब है कि आरबीआई को न्यूनतमरु रिजर्व रखना होगा. सिक्के और नोट जारी करने के लिए विश्व बैंक के पास सोने और विदेशी मुद्रा के रूप में 200 करोड़ रुपये हैं।

वस्तु विनिमय प्रणाली: इसका तात्पर्य धन के उपयोग के बिना वस्तुओं के बदले वस्तुओं के सीधे आदान-प्रदान से है।

मुद्रा आपूर्ति: यह किसी अर्थव्यवस्था में किसी विशेष समय पर जनता द्वारा रखे गए धन के कुल भंडार को संदर्भित करता है। यह एक स्टॉक अवधारणा है क्योंकि इसे एक विशेष समय पर मापा जाता है।

मुद्रा आपूर्ति के माप

(i) M₁: यह मुद्रा आपूर्ति का पहला और बुनियादी माप है। इसमें जनता द्वारा रखी गई मुद्रा, वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमा और आरबीआई के पास अन्य जमा शामिल हैं।

$$M_1 = \text{जनता के पास मुद्रा और सिक्के} + \text{वाणिज्यिक बैंकों के पास मांग जमा} + \text{आरबीआई के पास अन्य जमा}$$

(ii) M₂: यह M₁ की तुलना में मुद्रा आपूर्ति की एक व्यापक अवधारणा है। इसमें डाकघर बचत बैंक में जमा राशि भी शामिल है।

$$M_2 = M_1 + \text{डाकघर बचत बैंक में बचत जमा}$$

(iii) M₃: इसमें मुद्रा आपूर्ति के M₁ माप के अलावा शुद्ध सावधि जमा भी शामिल है।

$$M_3 = M_1 + \text{बैंकों में शुद्ध सावधि जमा}$$

(iv) M₄: इसमें मुद्रा आपूर्ति के M₃ माप के अलावा डाकघर बचत बैंक में कुल जमा शामिल है।

$$M_4 = M_3 + \text{डाकघर बचत बैंक में कुल जमा}$$

● M₁ मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक तरल रूप है जबकि M₄ सबसे कम तरल है।

● M₁ और M₂ को धन आपूर्ति की संकीर्ण अवधारणा माना जाता है जबकि M₃ और M₄ धन आपूर्ति की व्यापक अवधारणा है।

उच्च शक्ति मुद्रा (High Powered Money)

● उच्च शक्ति वाली मुद्रा आरबीआई और सरकार द्वारा उत्पादित धन है।

● इसमें जनता के पास मौजूद मुद्रा और बैंकों के पास मौजूद नकदी भंडार शामिल हैं।

● इसे चिन्ह (H) से दर्शाया जाता है।

● यह मुद्रा से भिन्न है क्योंकि धन में मांग जमा शामिल होती है जबकि इसमें नकद भंडार शामिल होता है जो मांग जमा उत्पन्न करने के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।

मुद्रा के कार्य: -

I. प्राथमिक कार्य: -

i. **विनिमय का माध्यम**: - यह व्यक्ति की क्रय शक्ति को दर्शाता है। यह सर्वत्र सहज स्वीकार्य है। पैसे से किसी भी समय किसी भी चीज़ का आदान-प्रदान किया जा सकता है। धन ने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल कर दिया है।

ii. **मूल्य का माप**: - यह एक मानक मूल्य के रूप में कार्य करता है। सभी वस्तुओं और सेवाओं को पैसे के रूप में मापा जाता है। प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्य उसकी कीमत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

II) माध्यमिक कार्य: -

i. **मूल्य का भंडार**: - धन को बैंक खातों के साथ-साथ लॉकर में भी संग्रहीत किया जा सकता है। यह हमें भविष्य में उपयोग के लिए पैसे बचाने में सक्षम बनाता है। सामान की तुलना में पैसा भंडारण के लिए कम जगह घेरता है।

ii. **मूल्य का स्थानांतरण**: - चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यह क्रय शक्ति को वर्तमान उपयोग से भविष्य के उपयोग में स्थानांतरित करने में मदद करता है।

iii. **स्थगित भुगतान का मानक**: - इसका अर्थ है "अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें"। पैसे की मदद से कोई भविष्य के भुगतान का विकल्प चुन सकता है। पैसा क्रेडिट लेनदेन को संभव बनाता है जब भुगतान तुरंत नहीं किया जाना हो।

बैंक: - इसे जनता से जमा स्वीकार करना और ऋण के रूप में जनता को धन उधार देना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

साख सृजन/ मुद्रा निर्माण: -

● वाणिज्यिक बैंकों की ऋण सृजन करने की क्षमता दो कारकों पर निर्भर करती है: - प्राथमिक जमा और LRR।

● बैंक द्वारा धारित घरों और फर्मों की जमा राशि को प्राथमिक जमा कहा जाता है।

● LRR- वैधानिक आरक्षित अनुपात यह वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि का अंश है जिसे वाणिज्यिक बैंक के लिए नकदी (CRR) और तरल संपत्ति (SLR) के रूप में आरक्षित रखना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

● साख गुणक = 1/वैधानिक आरक्षित अनुपात।

● साख निर्माण की प्रक्रिया: - मान लें कि प्राथमिक जमा 1000 के बराबर है और LRR 10% है।

बैंक अपने अनुभव से जानते हैं कि सभी जमाकर्ता एक ही समय में सारा पैसा नहीं मांगते हैं, किसी भी समय इसके कुछ हिस्से की ही मांग की जा सकती है। मान लीजिए कि बैंक अपनी जमा राशि का 10% नकद आरक्षित रखने का निर्णय लेता है। फिर शेष राशि ऋण के रूप में दी जा सकती है।

तो अब बैंक बाकी 900 रुपये जनता को लोन के रूप में दे सकता है. बैंक कभी भी नकद में ऋण नहीं देता है, बल्कि बैंक ऋण लेने वाले का खाता खोलते हैं और ऋण का यह पैसा उनके खाते में जमा कर दिया जाता है। जो राशि ऋण के रूप में दी जाती है उसे द्वितीयक जमा कहा जाता है। आगे फिर से बैंक 900 का 10% अपने पास रखेगा और अतिरिक्त राशि ऋण के रूप में दी जा सकती है और यह प्रक्रिया चलती रहेगी।

$$\text{कुल ऋण निर्माण} = 1 \times \frac{1}{LRR}$$

केन्द्रीय बैंक:- केन्द्रीय बैंक को बैंकिंग प्रणाली में एक शीर्ष वित्तीय संस्थान माना जाता है। इसे किसी राष्ट्र की आर्थिक और वित्तीय प्रणाली का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

केंद्रीय बैंक के कार्य:-

- 1. बैंक ऑफ इश्यू (नोट जारी करना) :-** आरबीआई के पास मुद्रा जारी करने का कानूनी और एकमात्र अधिकार है। यह RBI का प्राथमिक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आरबीआई 200 करोड़ रिज़र्व रखकर मुद्रा जारी करता है, जिसमें से 115 करोड़ सोना और 85 करोड़ विदेशी प्रतिभूतियां हैं। इससे नोट प्रचलन में एकरूपता आती है और मुद्रा प्रणाली में विश्वास पैदा होता है।
- 2. सरकार का बैंकर:-** केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से भुगतान करता है और प्राप्त करता है और सरकार के सभी बैंकिंग व्यवसाय करता है। केंद्रीय बैंक सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है क्योंकि वे सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद करते हैं और राष्ट्रीय ऋण और विदेशी ऋण का प्रबंधन भी करते हैं। केंद्रीय बैंक विशेष रूप से वित्त के मामलों पर सरकार के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।
- 3. बैंकर्स बैंक और पर्यवेक्षी भूमिका:-** केंद्रीय बैंक बैंकों के नकदी भंडार का एक हिस्सा रखता है क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ सीआरआर जमा करना होता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के साथ निपटान के कारण किसी भी समाशोधन ग्रह को पूरा करने के लिए बैंकों का अतिरिक्त भंडार रखता है। एक बैंक के दूसरे बैंक के विरुद्ध दावों का निपटान इन नकदी भंडारों से उनके खातों में सरल अंतरण द्वारा आसानी से किया जाता है। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षण, विनियमन और नियंत्रण करता है।
- 4. अंतिम उपाय के ऋणदाता:-** जिस प्रकार वाणिज्यिक बैंक व्यक्तियों को पैसा उधार देते हैं, उसी प्रकार केंद्रीय बैंक संकट के समय वाणिज्यिक बैंक को ऋण देते हैं। जब वाणिज्यिक बैंक का नकदी भंडार समाप्त हो जाता है तो केंद्रीय बैंक उन्हें अनुमोदित प्रतिभूतियों के बदले अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराता है।
- 5. विदेशी मुद्रा का संरक्षक:-** केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है। विदेशी मुद्रा में सभी प्राप्तियां और भुगतान आरबीआई द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा के लिए विनिमय दर की स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री करता है।
- 6. साख नियंत्रक:-** साख नियंत्रक के रूप में, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों की तरलता बनाए रखने और धन आपूर्ति को विनियमित करने के लिए कई उपकरणों का उपयोग करता है। साख नियंत्रक के रूप में केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है और अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति बढ़ाने के लिए ब्याज दरें घटाता है।

विकल्प:

- अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है
- अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है
- अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत है।
- अभिकथन गलत है लेकिन कारण सत्य है।

Q.1 अभिकथन: वाणिज्यिक बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है

कारण: रिज़र्व बैंक एकमात्र संस्था है जो मुद्रा जारी कर सकती है

Q.2 अभिकथन (ए): धन आपूर्ति एक प्रवाह अवधारणा है।

कारण (आर): धन आपूर्ति हमेशा एक विशेष समय पर मापी जाती है।

Q.3 **अभिकथन** (ए) : अर्थव्यवस्था में गिरती मांग को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट और बैंक रेट में कटौती की है।

कारण (आर) : रेपो दर और बैंक दर में कमी से ब्याज दर में कमी आती है जिससे ऋण की मांग बढ़ती है जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अधिक धन प्रवाहित होता है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार, कुल मांग बढ़ जाती है और कमी वाली मांग ठीक हो जाती है।

Q.4 **अभिकथन** (ए) : जनता द्वारा रखी गई मुद्रा केंद्रीय बैंक की मौद्रिक देनदारी है।

कारण (आर) : केंद्रीय बैंक ऋण को नियंत्रित करता है, जबकि वाणिज्यिक बैंक जनता द्वारा रखी गई मुद्रा से ऋण बनाते हैं।

Q.5 **अभिकथन** - क्रेडिट गुणक सीआरआर से विपरीत रूप से संबंधित है और सीआरआर का व्युत्क्रम है।

कारण - मुद्रास्फीति के समय में, आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए सीआरआर बढ़ाता है।

सही विकल्प का चयन करें

- दोनों कथन सत्य हैं
- दोनों कथन गलत हैं
- कथन 1 सत्य है और कथन 2 गलत है
- कथन 1 गलत है और कथन 2 सत्य है

Q.1 **कथन 1** केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और फ्लोटिंग का प्रबंधन करता है।

कथन 2 लचीली विनिमय दर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करती है।

Q.2 **कथन 1** $M1 = C + DD + \text{समय जमा}$

कथन 2 $M1$ में सबसे अधिक तरलता है।

Q.3 **कथन 1** एसएलआर घटने पर साख का विस्तार होगा।

कथन 2 वाणिज्यिक बैंक सिक्के जारी करते हैं।

Q.4. **कथन 1** सभी वित्तीय संस्थान बैंकिंग संस्थान नहीं हैं।

कथन 2: सभी वित्तीय संस्थानों को बैंकिंग संस्थान माना जाता है।

Q.5. **कथन 1** आरबीआई द्वारा बनाई गई मुद्रा को उच्च शक्ति वाली मुद्रा कहा जाता है।

कथन 2 मुद्रा नोट और सिक्के वैध मुद्रा कहलाते हैं।

केस आधारित प्रश्न

Q. 1 वाणिज्यिक बैंकों की वह शक्ति जो उन्हें ऋण के माध्यम से अपनी जमा राशियों का विस्तार करने में सक्षम बनाती है, साख निर्माण कहलाती है। कानूनी आरक्षित अनुपात वह न्यूनतम आरक्षित निधि है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंकों के निर्देशों के अनुसार तरल रूप में बनाए रखना चाहिए। एलआरआर के दो घटक हैं (i) नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) - यह शुद्ध कुल मांग और सावधि जमा का अंश है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास नकद भंडार के रूप में रखना चाहिए। (ii) वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) - यह शुद्ध कुल मांग और सावधि जमा का अंश है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को निर्दिष्ट तरल संपत्ति के रूप में रखना चाहिए। साख निर्माण की मान्यताएँ- (i) अर्थव्यवस्था में एकल बैंकिंग प्रणाली है। (ii) सभी लेनदेन बैंकों के माध्यम से होते हैं वाणिज्यिक बैंकों को ऋण के कारखाने कहा जाता है। वे लोगों से जमा राशि के रूप में जो इकट्ठा करते हैं, उससे कहीं अधिक अग्रिम कर लेते हैं। ऋण निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से, वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को वित्त प्रदान करते हैं।

1. किस बैंक को साख सृजन का कारखाना कहा जाता है?

a सरकार b वाणिज्यिक बैंक c एलआईसी d इनमें से कोई नहीं

2. यदि $CRR=5\%$ और $LRR=20\%$ है तो SLR क्या है?

a. 5% b. 10% c. 15% d. इनमें से कोई नहीं

3. निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट निर्माण प्रक्रिया की धारणाएं हैं?

a. अर्थव्यवस्था में एकल बैंकिंग प्रणाली है। b. सभी लेन-देन बैंकों के माध्यम से होते हैं।

c. a और b दोनों d इनमें से कोई नहीं.

महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:

1. यदि प्रारंभिक जमा राशि रु. है तो मूल्य धन गुणक और बनाई गई कुल जमा की गणना करें। 500 करोड़ और LRR 10% है।
2. मुद्रा आपूर्ति या ऋण के नियंत्रक के रूप में केंद्रीय बैंक की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
3. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित कार्यों की व्याख्या करें।
 - बैंक ऑफ इश्यू
 - बैंकर का बैंक
 - अंतिम उपाय तक ऋण देने वाला
 - सरकार का बैंकर
4. मुद्रा के कार्य बताइये।
5. मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याओं को कैसे दूर करती है?
6. जमा का केवल एक अंश ही नकद आरक्षित के रूप में क्यों रखा जाता है?
7. निम्नलिखित की अवधारणाएँ स्पष्ट करें: -
 - वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित मांग जमाएँ
 - जनता के पास मुद्रा और सिक्के

आय और रोजगार का निर्धारण

समग्र मांग: समग्र मांग (AD) अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करती है जिसे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक लेखांकन वर्ष की अवधि के दौरान आय के एक निश्चित स्तर पर खरीदने की योजना बना रहे हैं।

समग्र मांग के घटक:

- (i) निजी (घरेलू) उपभोग व्यय (C)
- (ii) निवेश व्यय (I)
- (iii) सरकारी व्यय (G)
- (iv) शुद्ध निर्यात (X-M)

औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC) - उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति आय के संगत स्तर के लिए उपभोग व्यय के अनुपात को संदर्भित करती है।

$$APC = \frac{\text{Consumption (C)}}{\text{Income (Y)}}$$

Income (Y)	Consumption (C)	APC = C/Y
0	40	-
100	120	1.20
200	200	1
300	280	0.933
400	360	0.90

सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) - सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कुल आय में परिवर्तन के लिए उपभोग व्यय में परिवर्तन के अनुपात को संदर्भित करती है।

$$MPC = \frac{\text{Change in Consumption}(\Delta C)}{\text{change in Income}(\Delta Y)}$$

Income (Y)	Consumption (C)	Change in consumption ΔC	Change in Income ΔY	MPC = $\Delta C / \Delta Y$
0	40	-	-	-
100	120	80	100	0.80
200	200	80	100	0.80
300	280	80	100	0.80
400	360	80	100	0.80

औसत बचत प्रवृत्ति (APS) - बचत करने की औसत प्रवृत्ति आय के संगत स्तर पर बचत के अनुपात को संदर्भित करती है।

$$APS = \frac{Saving(S)}{Income(Y)}$$

Income(Y)	Saving (S)	APS = S/Y
0	-40	-
100	-20	-0.20
200	0	0
300	20	0.067
400	40	0.10

सीमांत बचत प्रवृत्ति (MPS) - सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कुल आय में परिवर्तन के लिए उपभोग व्यय में परिवर्तन के अनुपात को संदर्भित करती है।

$$MPS = \frac{Change\ in\ Saving\ (\Delta S)}{Change\ in\ Income\ (\Delta Y)}$$

Income (Y)	Saving (S)	Change in saving ΔS	Change in Income ΔI	MPS
0	-40	-	-	-
100	-20	20	100	0.20
200	0	20	100	0.20
300	20	20	100	0.20
400	40	20	100	0.20

आय निर्धारण और गुणक

एक अर्थव्यवस्था तब संतुलन में होती है जब किसी समयावधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग कुल आपूर्ति के बराबर होती है।

तो संतुलन तब प्राप्त होता है जब

$$AD = AS$$

हम जानते हैं, AD उपभोग (C) और निवेश (I) का कुल योग है

$$AD = C + I$$

इसके अलावा AS उपभोग (C) और बचत (S) का कुल योग है

$$AS = C + S$$

हमें $C + S = C + I$ प्राप्त होता है

$$\text{या } S = I$$

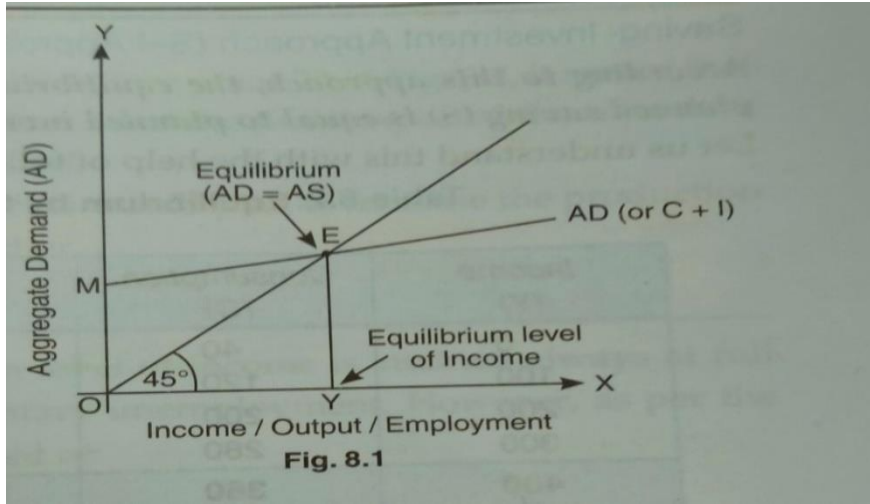
संतुलन स्तर के निर्धारण के लिए दो दृष्टिकोण

- समग्र मांग - समग्र आपूर्ति दृष्टिकोण (AD-AS दृष्टिकोण)
- बचत-निवेश दृष्टिकोण (S-I दृष्टिकोण)

1. समग्र मांग - समग्र आपूर्ति दृष्टिकोण (AD-AS दृष्टिकोण)

आय का संतुलन स्तर निर्धारित किया जाता है जहां कुल मांग का नियोजित स्तर (AD) कुल आपूर्ति के नियोजित स्तर (AS) के बराबर होता है।

Income (y)	Consumption(c)	Saving (S)	Investment(I)	AD= C+ I	AS = C+S	Remark
0	50	-50	100	150	0	AD>AS
100	100	0	100	200	100	AD=AS
200	150	50	100	250	200	AD>AS
300	200	100	100	300	300	AD=AS
400	250	150	100	350	400	AD<AS
500	300	200	100	400	500	AD<AS



अवलोकन-

$AD=C+I$ वक्र है क्योंकि मांग दो सेक्टर वाली अर्थव्यवस्था में उपभोग और निवेश के लिए है।
 AS वस्तुओं और सेवाओं या राष्ट्रीय आय की कुल राशि है। वह 45 लाइन है।
 E संतुलन बिंदु है जहाँ $AD = AS$ है

जब $AD > AS$ = इसका मतलब है कि उपभोक्ता और कंपनियां उत्पादकों द्वारा उत्पादित की जाने वाली योजना से अधिक सामान और सेवाएं खरीदने की योजना बना रहे हैं। इस स्थिति में, इन्वेंट्री स्तर (वस्तु का स्टॉक) गिरने लगता है और पूर्ण रोजगार संतुलन बनाए रखने के लिए वांछित स्तर से नीचे आ जाता है।

इन्वेंट्री को वांछित स्तर पर वापस लाने के लिए, फर्म रोजगार और आउटपुट में वृद्धि का सहारा लेगी जब तक कि अर्थव्यवस्था आउटपुट स्तर ओए पर वापस न आ जाए, जहां एडी. एएस. के बराबर हो जाती है और आगे बदलाव की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है।

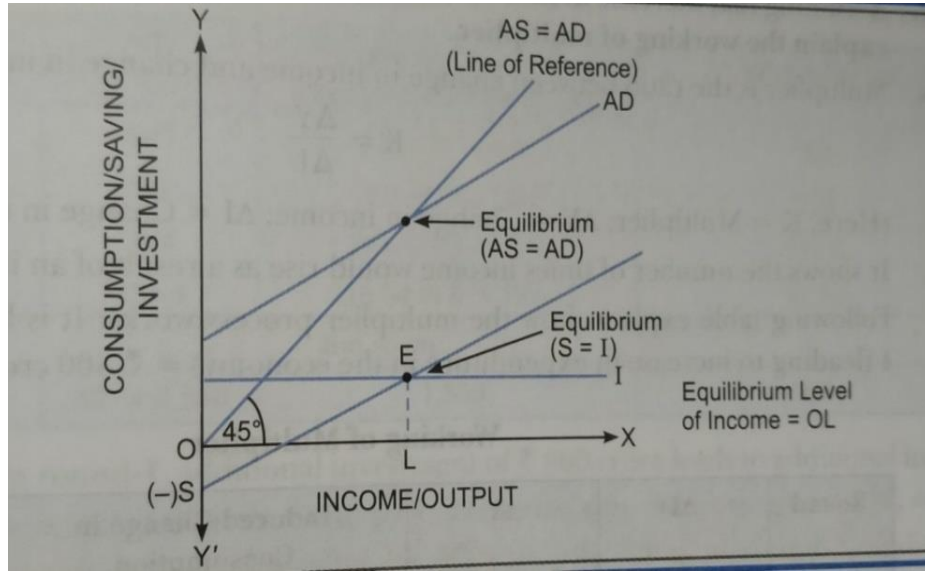
जब $AD < AS$ = इसका मतलब है कि उपभोक्ता और कंपनियां उत्पादकों द्वारा उत्पादित की जाने वाली योजना से कम सामान और सेवाएं खरीदने की योजना बना रही हैं। इस स्थिति में, इन्वेंट्री स्तर (वस्तु का स्टॉक) बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्ण रोजगार संतुलन बनाए रखने के लिए वांछित स्तर पर आ जाता है।

इन्वेंट्री में अवांछित वृद्धि को दूर करने के लिए, कंपनियां रोजगार और आउटपुट को कम करने की योजना बना रही हैं जब तक कि अर्थव्यवस्था आउटपुट स्तर ओए पर वापस न आ जाए, जहां एडी. एएस. के बराबर हो जाती है और आगे बदलाव की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है।

2. बचत-निवेश दृष्टिकोण (S-I दृष्टिकोण) - इस दृष्टिकोण के अनुसार आय का संतुलन स्तर एक स्तर पर निर्धारित किया जाता है, जब नियोजित बचत (S) नियोजित निवेश (I) के बराबर होती है।

$$S = I$$

Income (y)	Consumption(c)	Saving (S)	Investment	AD= C+ I	AS = C+S
0	50	-50	100	150	0
100	100	0	100	200	100
200	150	50	100	250	200
300	200	100	100	300	300
400	250	150	100	350	400
500	300	200	100	400	500



अवलोकन -

अर्थव्यवस्था बिंदु E पर संतुलन में है जहां बचत और निवेश वक्र एक दूसरे को काटते हैं।

बचत वक्र ऊपर की ओर झुकता है जो बचत और आय के बीच सकारात्मक संबंध दर्शाता है।

जब $S > I$ - यदि योजनाबद्ध बचत योजनाबद्ध निवेश से अधिक है, अर्थात बिंदु E के बाद इसका मतलब है कि परिवार उतनी खपत नहीं कर रहे हैं जितनी फर्मों ने उनसे अपेक्षा की थी। परिणामस्वरूप, इन्वेंट्री (वस्तु का स्टॉक) वांछित स्तर से ऊपर बढ़ जाती है।

इन्वेंट्री में अवांछित वृद्धि को दूर करने के लिए, फर्म तब तक उत्पादन कम करने की योजना बनाएगी जब तक कि बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर न हो जाएं।

जब $S < I$ - यदि नियोजित बचत नियोजित निवेश से कम है, अर्थात बिंदु E से पहले, तो इसका मतलब है कि परिवार अधिक उपभोग कर रहे हैं और फर्मों की अपेक्षा से कम बचत कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, इन्वेंट्री (वस्तु का स्टॉक) वांछित स्तर से नीचे गिर जाएगी।

इन्वेंट्री को वांछित स्तर पर वापस लाने के लिए, फर्म तब तक उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाएगी जब तक कि बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर न हो जाएं।

निवेश गुणक की अवधारणा - गुणक (K) निवेश (I) में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय (Y) में वृद्धि का अनुपात है।

गुणक का कार्य -

निवेश गुणक आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के बीच का अनुपात है।

$$K = \Delta Y / \Delta I$$

यह दर्शाता है कि निवेश में प्रारंभिक वृद्धि के परिणामस्वरूप आय कितनी गुना बढ़ जाएगी।

MPC (उपभोग करने की सीमांत प्रवृत्ति) K का प्रमुख निर्धारक है MPC का मूल्य जितना अधिक होगा, K का मूल्य उतना अधिक होना चाहिए।

निम्नलिखित तालिका बताती है कि गुणक प्रक्रिया कैसे काम करती है। यह इस धारणा पर आधारित है कि I (अर्थव्यवस्था में व्यय में वृद्धि के कारण) = 100 करोड़ और MPC = 0.5

Round	Change in investment (ΔI)	Change in income (ΔY)	Change in consumption (ΔC)	Leakage/ saving
1	100	100	50	50
2	-	50	25	25
3	-	25	12.5	12.5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

And so on

Total	100	200	100	100
-------	-----	-----	-----	-----

पूर्ण रोजगार: पूर्ण रोजगार से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें वे सभी लोग, जो मौजूदा मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक और सक्षम हैं, उन्हें बिना किसी अनुचित कठिनाई के काम मिलता है।

अनैच्छिक बेरोजगारी: अनैच्छिक बेरोजगारी से तात्पर्य उस बेरोजगारी से है जिसमें वे सभी लोग जो मौजूदा मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक और सक्षम हैं, उन्हें काम नहीं मिलता है।

अधिमांग: अतिरिक्त मांग उस स्थिति को संदर्भित करती है जब अर्थव्यवस्था में $AD > AS$ पूर्ण रोजगार के अनुरूप होता है। यह मुद्रास्फीति की खाई का कारण बनता है।

अभावी मांग: कमी की मांग उस स्थिति को संदर्भित करती है जब $AD < AS$ अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के अनुरूप होता है। यह अपस्फीति अंतराल का कारण बनता है।

1 अंक वाले प्रश्न

1. आय निर्धारण विश्लेषण में AD वक्र को _____ वक्र द्वारा दर्शाया जाता है

a) उपभोग=बचत+निवेश b) उपभोग+बचत c) बचत+निवेश d) उपभोग+निवेश

2. रोजगार का कीनेसियन सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है?

(ए) अल्पकालिक (बी) दीर्घकालिक (सी) पूर्ण रोजगार (डी) इनमें से कोई नहीं

3. यदि किसी अर्थव्यवस्था का एपीसी 0.6 है, तो आय स्तर पर बचत रु. 1,000 करोड़ होगा

(ए) रु. 100 करोड़ (बी) रु. 300 करोड़ (सी) रु. 400 करोड़ (डी) रु. 600 करोड़

4. संतुलन आय के संदर्भ में 45° रेखा एक है:

(ए) संदर्भ रेखा। (बी) पहचान की रेखा.

(सी) एडी और एएस के बीच समानता की रेखा। (डी) दोनों (ए) और (सी)।

5. सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर है:

A. $\Delta Y / \Delta C$ B. Y / C C. $\Delta C / \Delta Y$ D. C / Y

सही विकल्प चुनें:

a) दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण, दावे की सही व्याख्या है।

b) दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण नहीं है

c) दावा (ए) सत्य है लेकिन कारण (आर) गलत है।

d) दावा (ए) गलत है लेकिन कारण (आर) सच है।

6. दावा (ए): एपीएस कभी भी एक या एक से अधिक नहीं हो सकता।

तर्क (आर): आय में वृद्धि के साथ एपीसी बढ़ता है।

7. दावा (ए): गरीबों की एमपीसी अमीरों की तुलना में अधिक है।

तर्क (आर): आय में लगातार वृद्धि के साथ एमपीसी गिरती है।

8. अभिकथन (ए): गुणक बताता है कि निवेश में वृद्धि के परिणामस्वरूप आय कितनी गुना बढ़ जाती है।

तर्क (आर): बचत की सीमांत प्रवृत्ति और निवेश गुणक के बीच एक विपरीत संबंध है।

9. दावा (ए): पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में वह स्थिति है जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ $AS = AD$ होता है। लेकिन इसका मतलब अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं है।

तर्क (आर): पूर्ण रोजगार का अर्थ है अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का अभाव।

10. दावा (ए): अर्थव्यवस्था में बचत और वस्तुओं और सेवाओं की मांग के बीच सीधा संबंध है।

कारण (आर): जैसे-जैसे लोग अधिक से अधिक बचत करते हैं, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग गिरती है।

सही विकल्प चुनें:

ए। दोनों कथन सत्य हैं

बी। दोनों कथन गलत हैं

सी। कथन 1 सत्य है और कथन 2 गलत है

डी। कथन 1 गलत है और कथन 2 सत्य है

11. कथन 1: सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य एक से अधिक हो सकता है।

कथन 2: व्यय का न्यूनतम स्तर अर्थव्यवस्था में आय के स्तर पर निर्भर है।

12. कथन 1: जब औसत बचत प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान भी ऋणात्मक होगा।

कथन 2: MPC का मान हमेशा 1 के बराबर होता है।

13. कथन 1: उपभोग करने की उच्च प्रवृत्ति एक गुण है, जबकि बचत करने की उच्च प्रवृत्ति नहीं है।

कथन 2: दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में, यदि आय शून्य है, तो एपीसी भी शून्य होगी।

14. कथन 1: रोजगार के कीनेसियन सिद्धांत के अनुसार, किसी अर्थव्यवस्था में अल्परोजगार की स्थिति कभी नहीं हो सकती।

कथन 2 : जब नियोजित निवेश नियोजित बचत से कम होता है तो अनियोजित सूची जमा हो जाती है।

केस आधारित प्रश्न

भारतीय स्टेट बैंक के ECOWRAP के नवीनतम संस्करण में नोट किया गया है कि कई घरों में कम उपभोग करने की सीमांत प्रवृत्ति हो सकती है क्योंकि सामाजिक दूरी की बाधाओं के बीच कई प्रकार के खर्च आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। 25 मई को पहली बार लॉकडाउन लागू होने के बाद से जमा के रुझान का विश्लेषण करते हुए, बैंक ने कहा कि डेटा से पता चला है कि

लॉकडाउन-1 के दौरान जमा (बचत, चालू और सावधि) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई

शुरुआत में लोग खर्च को लेकर आशंकित थे और मितव्ययी हो गए। दौरान

लॉकडाउन-2 में बैंक डिपॉजिट में 25% की गिरावट आई, लेकिन टर्म डिपॉजिट एकदम था

बहुत स्वस्थ।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड; 2 जून 2020

प्रश्न :

1. _____ उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात है। (एपीसी / एमपीसी)

2. दिए गए लेख के अनुसार, कई परिवारों में सीमांत प्रवृत्ति हो सकती है उपभोग करें क्योंकि सोशल मीडिया के बीच कई तरह के खर्च आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं दूरी की बाधाएं।

(ए) कोई बदलाव नहीं (बी) अधिक (सी) कम (डी) इनमें से कोई नहीं

3. बैंक जमा में 25% _____ था, लेकिन सावधि जमा संचय बहुत था

लॉकडाउन 2 के दौरान स्वस्थ।

4. APC और MPC का योग _____ है।

(ए) एक (बी) शून्य (सी) दोनों (ए) और (बी) (डी) इनमें से कोई नहीं

3 अंक वाले प्रश्न

1. समग्र माँग क्या है? एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र माँग के प्रमुख घटकों का नाम बताइये।

उत्तर. समग्र माँग किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल माँग है, जिसे कुल व्यय के रूप में मापा जाता है।

कुल माँग के प्रमुख घटक हैं:

(i) निजी उपभोग व्यय (C)

(ii) निजी निवेश व्यय (I)

(iii) सरकारी व्यय (G)

(iv) शुद्ध निर्यात (X-M)

2. दो क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में समग्र माँग के घटकों को बताएं और चर्चा करें।

उत्तर. दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कुल माँग के घटक इस प्रकार हैं:

(i) उपभोग व्यय (C): इसे घरेलू उपभोग व्यय भी कहा जाता है। इसमें एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश के परिवारों द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं की माँग शामिल होती है। आम तौर पर, यह व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के स्तर पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का स्तर जितना अधिक होगा, निजी उपभोग व्यय उतना ही अधिक होगा, और इसके विपरीत।

(ii) निजी निवेश व्यय: यह निजी निवेशकों द्वारा ऐसी वस्तुओं की खरीद पर किए गए व्यय को संदर्भित करता है जो उनकी पूँजी के स्टॉक में इजाफा करता है। पूँजी के भण्डार में वृद्धि को पूँजी निर्माण भी कहा जाता है। ब्याज दर निजी निवेश का प्रमुख निर्धारक है। ब्याज की उच्च दर आम तौर पर कम निवेश व्यय का तात्पर्य है।

3. "अर्थशास्त्री आम तौर पर अर्थव्यवस्था में बढ़ती सीमांत बचत प्रवृत्ति (एमपीएस) के बारे में चिंतित हैं"। समझाइए क्यों?

उत्तर. चूंकि MPC और MPS का योग इकाई है, सीमांत बचत प्रवृत्ति (एमपीएस) में किसी भी वृद्धि से सीधे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (एमपीसी) में कमी आएगी। इसका मतलब यह है कि अतिरिक्त आय का कम हिस्सा उपभोग में जा रहा है, जो कुल माँग/व्यय का एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे अर्थव्यवस्था में आय के संतुलन स्तर में और गिरावट आ सकती है।

4. किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग के मूल्य का अनुमान लगाएं यदि:

(ए) स्वायत्त निवेश (I) = रु. 100 करोड़

(बी) सीमांत बचत प्रवृत्ति (एमपीएस) = 0.2

(सी) आय का स्तर (Y) = रु. 4000 करोड़

(द) स्वायत्त उपभोग व्यय (C) = रु. 50 करोड़

समाधान

दिया गया स्वायत्त निवेश (I) = रु. 100 करोड़

सीमांत बचत प्रवृत्ति (एमपीएस) = 0.2

आय का स्तर (Y) = रु. 4000 करोड़

स्वायत्त उपभोग व्यय (सी) = रु. 50 करोड़

सीमांत बचत प्रवृत्ति (एमपीएस) = 1 - एमपीएस
= 1 - 0.2 = 0.8

हम वह जानते हैं,

$$AD = C + I$$

$$AD = a + bY + I$$

$$= 50 + 0.8 (4000) + 100$$

$$= 50 + 3200 + 100$$

$$= 3350$$

कुल मांग = रु. 3350 करोड़

5. (i) अनैच्छिक बेरोजगारी (ii) पूर्ण रोजगार का अर्थ बताइए

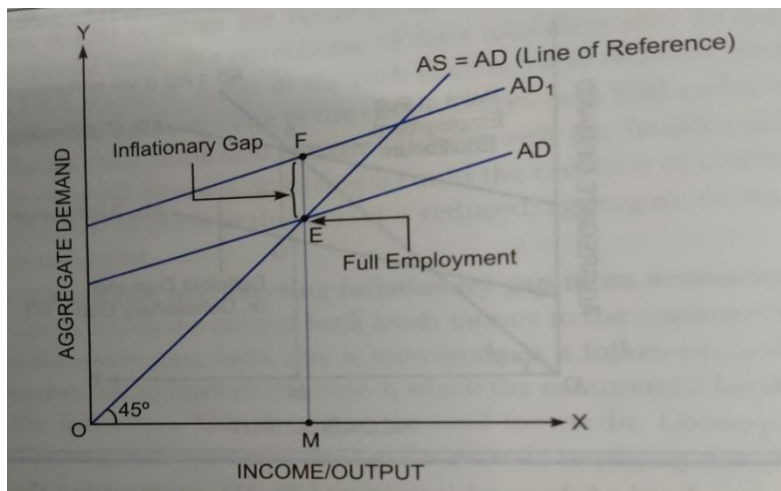
उत्तर. पूर्ण रोजगार: पूर्ण रोजगार से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें वे सभी लोग, जो मौजूदा मज़दूरी दर पर काम करने के इच्छुक और सक्षम हैं, उन्हें बिना किसी अनुचित कठिनाई के काम मिलता है।

अनैच्छिक बेरोजगारी: अनैच्छिक बेरोजगारी से तात्पर्य उस बेरोजगारी से है जिसमें वे सभी लोग जो मौजूदा मज़दूरी दर पर काम करने के इच्छुक और सक्षम हैं, उन्हें काम नहीं मिलता है।

6. एक चित्र की सहायता से मुद्रास्फीति अंतर की अवधारणा को स्पष्ट करें?

उत्तर. मुद्रास्फीति अंतर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक स्तर से अधिक कुल मांग की अधिकता है।

बिंदु E पर पूर्ण रोजगार संतुलन प्रभावित होता है। यदि मांग का स्तर AD_1 तक बढ़ जाता है, तो यह पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक है। इससे महंगाई बढ़ती है। इसलिए, AD_1 और AD (EF) के बीच के अंतर को मुद्रास्फीति अंतर कहा जाता है।



7. किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के अंतर को ठीक करने में बैंक दर की भूमिका पर चर्चा करें।

उत्तर. बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। मुद्रास्फीति के अंतर की स्थिति को ठीक करने के लिए बैंक दर में वृद्धि की गई है। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, वाणिज्यिक बैंक ब्याज की बाजार दर बढ़ाते हैं। इससे ऋण की मांग में कमी आई है। परिणामस्वरूप, उपभोग व्यय और निवेश व्यय में कमी आती है, जिसका अर्थ मुद्रास्फीति के अंतर को ठीक करने के लिए आवश्यक कुल मांग में कमी है।

8. किसी अर्थव्यवस्था में कमी की मांग को ठीक करने में मार्जिन आवश्यकताओं की भूमिका पर चर्चा करें।
उत्तर. मार्जिन आवश्यकताएं न्यूनतम अग्रिम भुगतान को संदर्भित करती हैं जो उधारकर्ताओं को वाणिज्यिक बैंकों से अपने कुल उधार के प्रतिशत के रूप में करना होता है। मांग में कमी की स्थिति को ठीक करने के लिए मार्जिन की आवश्यकता कम कर दी गई है। कम मार्जिन आवश्यकता उधार लेने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। यह उधारकर्ताओं को अधिक ऋण जुटाने के लिए प्रेरित करता है। कमी वाली मांग को ठीक करने के लिए वांछित कुल मांग में वृद्धि का तात्पर्य।

9. "अर्थव्यवस्था में गिरती मांग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नकद आरक्षित अनुपात को कम कर दिया है।" सेंट्रल बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के पीछे के तर्क को विस्तार से बताएं।
उत्तर. नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) के लिए वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा के प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुछ न्यूनतम नकद भंडार बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अर्थव्यवस्था में गिरती मांग को बढ़ावा देने के लिए सीआरआर कम किया गया है। आरबीआई के पास नकदी भंडार में कटौती से वाणिज्यिक बैंकों के पास नकदी शेष बढ़ जाती है। और बैंकों के पास नकदी शेष में वृद्धि से उनकी मांग जमा में कई गुना वृद्धि होती है। तदनुसार, बाजार में ऋण का प्रवाह बढ़ जाता है, गिरती मांग को बढ़ावा देने के लिए कुल मांग बढ़ जाती है।

10. "भारत की जीडीपी 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में 23.9% घट गई, यह दर्शाता है कि लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है।"

- द हिंदुस्तान टाइम्स, 1 सितंबर 2020

उपरोक्त समाचार रिपोर्ट में बताई गई स्थिति को ठीक करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले किन्हीं दो वित्तीय उपायों को बताएं और उन पर चर्चा करें।

उत्तर. स्थिति से पता चलता है कि लॉकडाउन के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधि धीमी हो गई है। अर्थव्यवस्था में रोजगार की हानि देखी गई है और इसके परिणामस्वरूप आय और व्यय में गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए निम्नलिखित दो वित्तीय उपाय किए जा सकते हैं:

(i) सरकारी व्यय में वृद्धि: सरकार को अपना व्यय बढ़ाना चाहिए। इसमें उपभोग व्यय और निवेश व्यय दोनों शामिल हैं। सरकारी व्यय में वृद्धि से एडी में वृद्धि होती है जो अर्थव्यवस्था में मंदी से निपटने के लिए आवश्यक है।

(ii) कर संरचना को संशोधित करें: निजी निवेश को प्रेरित करने के लिए कर संरचना को संशोधित किया जाना चाहिए। फोकस उत्पादन गतिविधि के ऐसे क्षेत्रों पर होना चाहिए जो रोजगार पैदा करते हैं, जैसे रियल एस्टेट।

6. प्रश्न:

1. आय का संतुलन स्तर निर्धारित करने के दो वैकल्पिक तरीके क्या हैं? ये कैसे संबंधित हैं?

उत्तर. आय का संतुलन स्तर निर्धारित करने के दो वैकल्पिक तरीके इस प्रकार हैं:

(i) संतुलन तब बनता है जब: $AD = AS$ और

(ii) संतुलन तब बनता है जब: $S = I$

ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं:

$$AD = AS$$

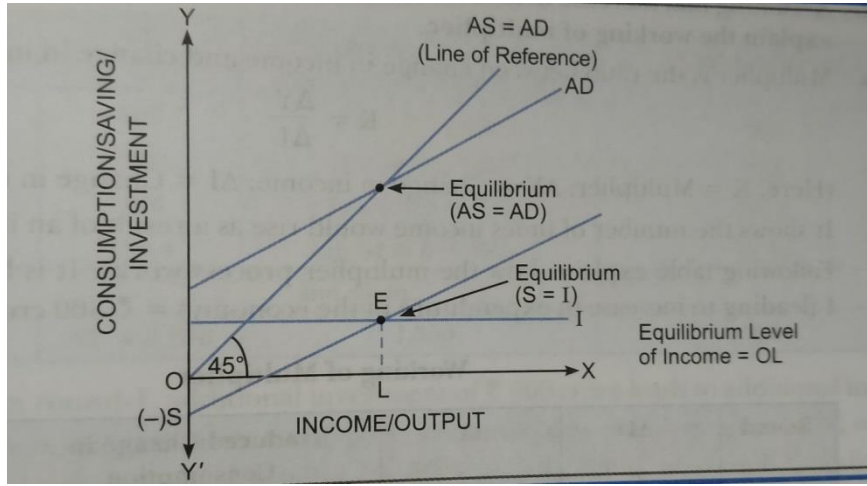
या

$$C + I = C + S$$

या

$$S = I$$

पहला दृष्टिकोण कहता है कि संतुलन तब बनता है जब अर्थव्यवस्था में नियोजित मांग नियोजित आपूर्ति के बराबर होती है। दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि संतुलन तब बनता है जब व्यय की निकासी (बचत के रूप में) व्यय के इंजेक्शन (निवेश के रूप में) के बराबर होती है।



प्रश्न 2. यह मानते हुए कि निवेश में वृद्धि 1000 करोड़ रुपये है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.9 है, गुणक की कार्यप्रणाली समझाइए।

उत्तर. मल्टीप्लायर आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के बीच का अनुपात है।

$$K = \Delta Y / \Delta I$$

निम्नलिखित तालिका बताती है कि गुणक प्रक्रिया कैसे काम करती है। यह दिए गए मूल्य पर आधारित है कि I (अर्थव्यवस्था में व्यय में वृद्धि के कारण) = 1000 रुपये, करोड़ और एमपीसी = 0.9

गुणक का कार्य (करोड़ रुपये में)

Round	ΔI	ΔY	Induced change in consumption MPC (ΔY)	Leakage/saving
1	1,000	1,000	900 (= 0.9 x 1,000)	100
2	-	900	810 (= 0.9 x 900)	90
3	-	810	729 (= 0.9 x 810)	81
4	-	729	656.1 (= 0.9 x 729)	72.9
And so on...				
	$\Delta I = 1,000$	$\Delta Y = 10,000$	9,000	1,000

तालिका से पता चलता है कि राउंड-1 में, रुपये का अतिरिक्त निवेश। 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होती है। 1000 करोड़. लेकिन प्रत्येक अगले दौर में अतिरिक्त आय का 90% खर्च किया जाता है (MPC = 0.9 के रूप में। शेष 10% रिसाव/बचत की ओर जाता है (MPC = 0.1 के रूप में)। इस प्रकार दौर -2 में, अतिरिक्त आय = 900 करोड़ रुपये (0.9 x 1000), राउंड-3 में यह = 810 करोड़ रुपये (0.9 x 900) है, अगले राउंड में यह = 729 करोड़ रुपये (0.9 x 810, और इसी तरह जब तक अतिरिक्त आय का कुल योग = 10,000 करोड़ रुपये) हो जाता है।

$$K = 1 / 1 - MPC$$

$$= 1 / 1 - 0.9 = 1 / 0.1 = 10$$

यह देखते हुए कि $\Delta I = 1000$, और $K = 10$,

$$\Delta Y = 10 \times 1,000$$

$$= 10,000 \text{ करोड़ रुपये}$$

इकाई - 4: सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था

सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण है। सरकारी बजट के उद्देश्य:

1. पुनःआवंटन उद्देश्य

● बजटीय प्रावधानों के माध्यम से सरकार सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों को पुनः आवंटित करती है।

यह दो तरह से किया जाता है.

● आर्थिक उद्देश्य (लाभ अधिकतमीकरण)

अधिकतम लाभ के माध्यम से आर्थिक विकास लाने के लिए सरकार उन क्षेत्रों में अधिक निवेश करती है जो अधिक लाभ कमाते हैं और उन क्षेत्रों में विनिवेश करती है जो नुकसान पहुंचाते हैं।

● सामाजिक उद्देश्य (समाज कल्याण)

सामाजिक कल्याण लाने के लिए सरकार उन वस्तुओं का उत्पादन करती है जिनमें निजी क्षेत्र उत्पादन करने में विफल रहते हैं

कभी-कभी यह निजी क्षेत्रों को उन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कर रियायत और सब्सिडी देता है जो सामाजिक रूप से वांछित हैं और जनता के कल्याण को बढ़ाती हैं।

2. आय व संपत्ति का पुनः वितरण उद्देश्य

● बजटीय प्रावधानों के माध्यम से सरकार असमानता को कम करके समानता लाने के लिए लोगों के बीच आय का पुनर्वितरण करती है। यह निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है.

- यह अमीर लोगों पर अधिक कर लगाता है
- टैक्स के माध्यम से एकत्रित राशि गरीबों को सब्सिडी के रूप में दी जाती है
- इस तरह से गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाट दिया जाता है

3. स्थिरीकरण उद्देश्य:

● बजटीय प्रावधानों के माध्यम से सरकार मुद्रास्फीति और अपस्फीति के कारण उत्पन्न उतार-चढ़ाव को रोककर आर्थिक स्थिरता लाती है

- यह उसके राजकोषीय नीति उपकरणों की सहायता से किया जाता है। यानी सरकारी खर्च और कराधान
- मुद्रास्फीति के दौरान सरकार अपने खर्चों में कटौती करती है और मुद्रास्फीति के दौरान कर में रियायत देती है
- संक्षेप में इसने मुद्रास्फीति और अपस्फीति से निपटने के लिए क्रमशः अधिशेष बजट और घाटे के बजट की नीति का पालन किया

4. प्रबंधन के उद्देश्य

● बजटीय प्रावधानों के माध्यम से सरकार। सार्वजनिक क्षेत्रों को एकाधिकार की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए उन्हें नियंत्रित करता है

● सरकार राजकोषीय अनुशासन लाने और सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता बढ़ाने के लिए। लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश करें और घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश करें

5. आर्थिक विकास

● आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य देश की अधिक उत्पादन करने की क्षमता से है। इसका संकेत जीडीपी में बढ़ोतरी से मिलता है

● किसी भी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक विकास को निम्न प्रकार से सुनिश्चित करने के लिए बजट एक अनिवार्य उपकरण है

● बजट के माध्यम से सरकार उत्पादक इकाइयों को इनपुट सब्सिडी, कर रियायत और कर अवकाश के रूप में विभिन्न प्रोत्साहन देती है, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा मिलता है।

● बजट के माध्यम से सरकार ने ढांचागत विकास के रूप में व्यय किया जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधियों में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन और जीडीपी में वृद्धि हुई।

बजट की संरचना या घटक

(ए) बजट प्राप्तियाँ

बजट प्राप्तियाँ एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को संदर्भित करती हैं। यह दो प्रकार का होता है।

राजस्व प्राप्तियाँ:

● राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो न तो कोई देनदारी पैदा करती हैं और न ही किसी संपत्ति को कम करती हैं

● उदाहरण: कर रसीदें, शुल्क, जुर्माना आदि।

● राजस्व प्राप्तियाँ मूलतः दो प्रकार की होती हैं

(ए) कर राजस्व

(बी) गैर कर राजस्व

(ए) कर राजस्व

कर किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा सरकार को किया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है, जिसमें किसी भी प्रत्यक्ष प्रति-समर्थक संबंध को शामिल नहीं किया जाता है

प्रकार: भार स्थानांतरण के आधार पर यह दो प्रकार का होता है

- (i) प्रत्यक्ष कर
- (ii) अप्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर

आधार	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
अर्थ	वे कर जिनमें प्रारंभिक धन भार (प्रभाव) और अंतिम धन भार (घटना) एक ही व्यक्ति/संस्था पर पड़ता है	वे कर जिनमें प्रारंभिक धन भार (प्रभाव) और अंतिम धन भार (घटना) अलग-अलग व्यक्ति/संस्था पर पड़ता है
बोझ का स्थानांतरण	संभव नहीं	संभव
प्रकृति	नियमित	अनियमित
लगाया गया	आय और संपत्ति	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद
उदाहरण	आयकर, धन कर, संपत्ति कर, निगम कर	बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, सेवा कर

(बी) गैर कर राजस्व

कर को छोड़कर सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियाँ गैर-कर राजस्व कहलाती हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं।

(i) वाणिज्यिक राजस्व

वह राजस्व जो सरकार को सरकार के लिए भुगतान की गई कीमतों के रूप में प्राप्त होता है। आपूर्ति की गई वस्तुएँ और सेवाएँ उदाहरण: डाक शुल्क, टोल, रेलवे सेवाएँ आदि।

(ii) प्रशासनिक राजस्व

वह राजस्व जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों के कारण उत्पन्न होता है। उदाहरण: शुल्क, जुर्माना, ज़ब्ती, राजहस्त आदि।

पूंजीगत प्राप्तिः

पूंजीगत प्राप्तिः वे प्राप्तिः होती हैं जो या तो कोई देनदारी बनाती हैं या किसी संपत्ति को कम करती हैं।

उदाहरण: उधार प्राप्ति, विनिवेश, ऋण की वसूली आदि।

राजस्व प्राप्तिः और पूंजीगत प्राप्तिः के बीच अंतर

आधार	राजस्व प्राप्तिः	पूंजीगत प्राप्तिः
अर्थ	वे प्राप्तिः जो न तो कोई दायित्व उत्पन्न करती हैं और न ही किसी संपत्ति को कम करती हैं	वे प्राप्तिः जो न तो कोई दायित्व उत्पन्न करती हैं और न ही किसी सम्पत्ति को कम करती हैं
उदाहरण	आयकर, शुल्क, जुर्माना	उधार, विनिवेश
प्रकृति	नियमित एवं आवर्ती	अनियमित एवं अनावर्ती
भविष्य का दायित्व	कोई भविष्य की बाध्यता नहीं	भविष्य का दायित्व

(बी) बजट व्यय

यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के अनुमानित व्यय को संदर्भित करता है। यह 2 प्रकार का होता है।

- (i) राजस्व व्यय
- (ii) पूंजीगत व्यय

● राजस्व व्यय:

वे व्यय जिनसे न तो कोई संपत्ति बनती है और न ही कोई देनदारी कम होती है। उदाहरण: छात्रवृत्ति, सरकार द्वारा वेतन, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। राज्य सरकार को, ऋण पर ब्याज का भुगतान, रखरखाव आदि पर खर्च।

● पूंजीगत व्यय

वे व्यय जो या तो किसी परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं या किसी देनदारी को कम करते हैं। उदाहरण: ऋणों का पुनर्भुगतान, स्कूल भवनों, अस्पतालों आदि का निर्माण।

राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच अंतर

आधार	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय
अर्थ	वे व्यय जिनसे न तो कोई संपत्ति बनती है और न ही कोई देनदारी कम होती है	वे व्यय जो न तो कोई संपत्ति बनाते हैं और न ही कोई देनदारी कम करते हैं
उदाहरण	ऋण, छात्रवृत्ति पर ब्याज का भुगतान	ऋणों का पुनर्भुगतान, स्कूलों, अस्पताल भवनों का निर्माण
प्रकृति	नियमित एवं आवर्ती	अनियमित एवं अनावर्ती

बजट घाटे और उन्हें दूर करने के उपाय

(ए) राजस्व घाटा:

● राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता है

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ

आशय:

- यह जानकारी देता है कि सरकार किसलिए उधार ले रही है
- घरेलू सादृश्य में राजस्व घाटा यह बताता है कि गृहस्वामी घर में छत जोड़ने के बजाय किराना दुकानदार को भुगतान करने के लिए कितनी राशि उधार ले रहा है।
- भविष्य में पुनर्भुगतान का बोझ निवेश के माध्यम से किसी भी लाभ से मेल नहीं खाएगा
- उधार ली गई धनराशि का उपयोग सरकार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है

(बी) राजकोषीय घाटा:

● राजकोषीय घाटा कुल गैर-उधार प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता है। दूसरे शब्दों में यह उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय का आधिक्य है

राजकोषीय घाटा = (राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय) - (राजस्व प्राप्तियाँ + पूंजीगत प्राप्तियाँ - उधार)

नोट: राजकोषीय घाटा = उधार

आशय:

- राजकोषीय घाटे की सीमा इस बात का संकेत है कि राजकोष अपनी क्षमता से कितना अधिक खर्च कर रहा है
- यह इंगित करता है कि सरकार को कितना उधार लेना है
- बड़े राजकोषीय घाटे का तात्पर्य बड़ी मात्रा में उधार लेना है
- यह भविष्य में ब्याज भुगतान के अनुरूप बड़ा बोझ पैदा करता है
- बड़ा राजकोषीय घाटा भी मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा सकता है

(सी) प्राथमिक घाटा:

● यह राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

आशय:

- प्राथमिक घाटा का तात्पर्य यह है कि ब्याज भुगतान के अलावा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए सरकारी उधारी कितनी होगी
- यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकार की नीति किस हद तक पिछली नीति से उत्पन्न भविष्य के बोझ को बढ़ा रही है
- इसे अक्सर राजकोषीय गैरजिम्मेदारी के बुनियादी उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह इस बात का माप है कि सरकार अपने फिजूलखर्चों के तरीकों को जारी रखते हुए कितना उधार ले रही है
- कम या शून्य प्राथमिक घाटे का मतलब है कि हालांकि पहले के ऋणों पर ब्याज प्रतिबद्धताओं ने सरकार को उधार लेने के लिए मजबूर किया है, लेकिन वह अपनी कमर कसने की जरूरत से अवगत है।

(MCQs)

1. भारत में वित्तीय वर्ष _____ से चलता है

(ए) 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक

(बी) 1 मार्च से 28 फरवरी तक

(सी) 1 अप्रैल से 31 मार्च तक

(डी) 1 जुलाई से 30 जून तक

2. बजट दस्तावेज़ में केवल चालू वित्तीय वर्ष में सरकार की प्राप्तियों और व्यय को शामिल किया जाता है
 (ए) वित्तीय बजट (बी) राजस्व बजट
 (सी) पूंजीगत बजट (डी) प्राथमिक बजट
3. बजट दस्तावेज़ सरकार की प्राप्तियों और व्यय से संबंधित होता है, जिसमें सरकार की संपत्ति और देनदारियों को शामिल किया जाता है।
 (ए) वित्तीय बजट (बी) राजस्व बजट
 (सी) पूंजीगत बजट (डी) प्राथमिक बजट
4. सरकारी बजट आईडी के अनुसार ब्याज भुगतान रु. 1,40,000 करोड़. यदि सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं का अनुमान रुपये है। 2,70,000 करोड़. प्राथमिक घाटा कितना है?
 (ए) रु. 1,40,000 करोड़ (बी) रु. 2,70,000 करोड़
 (सी) रु. 4,10,000 करोड़ (डी) रु. 1,30,000 करोड़
5. निम्नलिखित जानकारी से राजस्व प्राप्तियों की गणना करें। गैर ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्तियाँ = 25000, राजस्व घाटा = 12000, ब्याज भुगतान = 7000, राजस्व व्यय = 20000, पूंजीगत व्यय = 35000 (सभी आंकड़े करोड़ रुपये में हैं)।
 (ए) रु. 8000 करोड़ (बी) रु. 43000 करोड़
 (सी) रु. 15000 करोड़ (डी) रु. 25000 करोड़

सही विकल्प चुनें:

- (ए) कथन 1 सत्य है और कथन-2 गलत है
 (बी) कथन 1 गलत है और कथन 2 सत्य है
 (सी) कथन 1 और कथन-2 दोनों सत्य हैं
 (डी) कथन 1 और कथन-2 दोनों गलत हैं
6. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
कथन-1: राजस्व प्राप्तियाँ प्रतिदेय नहीं हैं।
कथन-2: सरकारी बजट का पुनर्वितरण उद्देश्य आनुपातिक आय कराधान के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।
7. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
कथन-1: सरकार की वे सभी प्राप्तियाँ जो संपत्ति बनाती हैं या देनदारियाँ कम करती हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ कहलाती हैं।
कथन-2 :: सरकार की वे सभी प्राप्तियाँ जो देनदारियाँ पैदा करती हैं या संपत्ति कम करती हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ कहलाती हैं।
8. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
कथन-1: ऋणों की अदायगी को राजस्व व्यय कहा जाता है
कथन-2 :: ऋण पर ब्याज का भुगतान राजस्व व्यय कहलाता है
9. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
कथन-1: राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है
कथन-2 :: राजकोषीय घाटा, पूंजीगत प्राप्तियों पर सरकार के पूंजीगत व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है।
10. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
कथन-1: सकल राजकोषीय घाटा सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की स्थिरता को आंकने में एक महत्वपूर्ण चर है।
कथन-2 :: राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का बड़ा हिस्सा यह दर्शाता है कि उधार का एक बड़ा हिस्सा निवेश के बजाय अपनी उपभोग व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

सही विकल्प चुनें

11. **दावा (ए)** : ऋण पर ब्याज का भुगतान एक राजस्व व्यय है

कारण (आर) : वे व्यय जो न तो कोई संपत्ति बनाते हैं और न ही कोई देनदारी कम करते हैं, राजस्व व्यय कहलाते हैं

12. **दावा (ए)** : जब कोई सरकार राजस्व के माध्यम से एकत्र की गई राशि से अधिक खर्च करती है, तो उसे बजट घाटा होता है

कारण (आर) : राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर इसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है

13. **दावा (ए)** : प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा + ब्याज भुगतान

कारण (आर) : राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर इसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है

14. **दावा (ए)** : विभिन्न सरकारी योजनाओं में जनता द्वारा की गई छोटी बचत पूंजीगत प्राप्तियों का एक उदाहरण है

कारण (आर) : छोटी बचत से सरकार की संपत्ति कम हो जाती है

15. **दावा (ए)** : सार्वजनिक वस्तुओं को गैर-बहिष्कृत कहा जाता है

कारण (आर) : भले ही कुछ उपयोगकर्ता भुगतान न करें, जनता की भलाई के लिए शुल्क एकत्र करना मुश्किल और कभी-कभी असंभव होता है

केस आधारित प्रश्न

राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएमए)

बहुदलीय संसदीय प्रणाली में, चुनावी चिंताएँ व्यय नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह तर्क दिया जाता है कि एक विधायी प्रावधान, जो वर्तमान और भविष्य की सभी सरकारों पर लागू होता है, घाटे को नियंत्रण में रखने में प्रभावी होने की संभावना है। अगस्त 2003 में एफआरबीएमए का अधिनियमन, राजकोषीय सुधारों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने सरकार को एक विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्थागत ढांचे के माध्यम से बाध्य किया। केंद्र सरकार को पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त करके, मौद्रिक नीति में राजकोषीय बाधाओं को दूर करके और घाटे और उधार को सीमित करके प्रभावी ऋण प्रबंधन द्वारा अंतर-पीढ़ीगत इकटिटी और दीर्घकालिक मैक्रो-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए। अधिनियम के तहत नियमों को जुलाई, 2004 से अधिसूचित किया गया था।

मुख्य विशेषताएं

1. अधिनियम केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं करने और 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को खत्म करने और उसके बाद पर्याप्त राजस्व अधिशेष बनाने के लिए उचित उपाय करने का आदेश देता है।
2. इसके लिए राजकोषीय घाटे में प्रत्येक वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत और राजस्व घाटे में 0.5 प्रतिशत की कमी करना आवश्यक है। यदि यह कर राजस्व के माध्यम से हासिल नहीं किया जाता है, तो आवश्यक समायोजन व्यय में कमी से आना होगा।
3. वास्तविक घाटा केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राकृतिक आपदा या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य असाधारण आधारों पर निर्दिष्ट लक्ष्यों से अधिक हो सकता है।
4. केंद्र सरकार नकद प्राप्तियों पर नकद संवितरण की अस्थायी अधिकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार नहीं लेगी।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक को वर्ष 2006-07 से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए।
6. राजकोषीय परिचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये जायेंगे।
7. केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों के समक्ष तीन वक्तव्य रखेगी - मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य, राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य, वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क वक्तव्य।

8. बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुझानों की त्रैमासिक समीक्षा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

1. FRBMA 2003 के अनुसार केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए

- (ए) राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं कम करना
- (बी) 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटा समाप्त करना
- (सी) पर्याप्त राजस्व अधिशेष का निर्माण करना।
- (D) उपरोक्त सभी

2. FRBMA 2003 के अनुसार केंद्र सरकार सुनिश्चित करे

- (ए) दीर्घकालिक सूक्ष्म आर्थिक स्थिरता
- (बी) घाटे और उधार को सीमित करके प्रभावी ऋण प्रबंधन
- (सी) पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त करके अल्पकालिक मैक्रो-आर्थिक स्थिरता
- (D) उपरोक्त सभी

3. यदि केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष कर राजस्व के माध्यम से राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करने में सक्षम नहीं है, तो उसे कौन सी नीति अपनानी होगी?

- (ए) गैर-कर राजस्व में वृद्धि से आवश्यक समायोजन होना चाहिए
- (बी) आवश्यक समायोजन व्यय में कमी से आना होगा
- (सी) आवश्यक समायोजन बढ़ती उधारी से आना होगा
- (D) उपरोक्त सभी

4. निम्नलिखित में से किस मामले में वास्तविक घाटा निर्दिष्ट लक्ष्य से अधिक हो सकता है?

- (ए) केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर
- (बी) प्राकृतिक आपदा
- (सी) दोनों (ए) और (बी)
- (डी) किसी भी स्थिति में वास्तविक घाटा निर्दिष्ट लक्ष्य से अधिक नहीं होना चाहिए

5. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

(ए) केंद्र सरकार नकद प्राप्तियों पर नकद संवितरण की अस्थायी अधिकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेगी।

(बी) केंद्र सरकार नकद प्राप्तियों पर नकद संवितरण की अस्थायी अधिकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार नहीं लेगी।

(सी) बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुझान की त्रैमासिक समीक्षा संसद के निचले सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

(डी) भारतीय रिज़र्व बैंक को वर्ष 2006-07 से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक मुद्दों की सदस्यता लेनी होगी।

3/4 अंक

1. गैर-कर राजस्व प्राप्तियों के कोई दो स्रोत बताइये।

2. कर को परिभाषित करें। विभिन्न प्रकार के कर बताइये।

3. प्राथमिक घाटे की गणना कैसे की जाती है?

उत्तर: यह राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

4. सरकारी बजट के कोई तीन उद्देश्य बताइये।

उत्तर: सरकार के तीन उद्देश्य. बजट हैं

- संसाधनों का पुनः आवंटन
- आय का पुनर्वितरण
- आर्थिक विकास

5. आय की असमानताओं को कम करने में बजटीय नीति का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: बजटीय प्रावधानों के माध्यम से सरकार असमानता को कम करके समानता लाने के लिए लोगों के बीच आय का पुनर्वितरण करती है। यह निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है.

- यह अमीर लोगों पर अधिक कर लगाता है
- टैक्स के माध्यम से एकत्रित राशि गरीबों को सब्सिडी के रूप में दी जाती है
- इस तरह से गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाट दिया जाता है

6. सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों के बीच अंतर स्पष्ट करें। प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए।

7. सरकारी बजट में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच अंतर बताएं। प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए।

8. सरकारी बजट में राजकोषीय घाटे की अवधारणा को समझाइये। यह क्या दर्शाता है?

उत्तर: राजकोषीय घाटा कुल गैर-उधार प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता है। दूसरे शब्दों में यह उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय का आधिक्य है

राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (कुल प्राप्तियाँ - उधार)

= कुल व्यय - कुल प्राप्तियाँ + उधार

= (राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय) - (राजस्व प्राप्तियाँ + पूंजीगत प्राप्तियाँ - उधार)

नोट: राजकोषीय घाटा उधार के बराबर है क्योंकि सरकार को उधार के माध्यम से राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करना होगा

राजकोषीय घाटा = उधार

आशय:

- राजकोषीय घाटे की सीमा इस बात का संकेत है कि राजकोष अपनी क्षमता से कितना अधिक खर्च कर रहा है
- यह इंगित करता है कि सरकार को कितना उधार लेना है
- बड़े राजकोषीय घाटे का तात्पर्य बड़ी मात्रा में उधार लेना है
- यह भविष्य में ब्याज भुगतान के अनुरूप बड़ा बोझ पैदा करता है
- बड़ा राजकोषीय घाटा भी मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा सकता है

9. प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर बताइये।

10. सरकारी बजट के बारे में निम्नलिखित आंकड़ों से निम्नलिखित का पता लगाएं:

(i) राजस्व घाटा (ii) राजकोषीय घाटा (iii) प्राथमिक घाटा

क्र.सं.	आइटम	रु. (करोड़ में)
(ए)	उधारों को घटाकर पूंजीगत प्राप्तियाँ	95
(बी)	राजस्व व्यय	100
(सी)	ब्याज भुगतान	10
(डी)	राजस्व प्राप्तियाँ	80
(ई)	पूंजीगत व्यय	110

उत्तर:

राजस्व घाटा = 100 - 80 = 20 करोड़ रु

राजकोषीय घाटा = (100 + 110) - 95 = 210 - 95 = रु. 115 करोड़

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान = 115 - 10 = रु. 105 करोड़

भुगतान शेष (BOP)

BOP एक वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग देश के निवासियों और विदेशी देशों के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेनदेन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है।

- बीओपी दृश्य और अदृश्य दोनों वस्तुओं के आदान-प्रदान को ध्यान में रखता है
- इसलिए **BOP** देश के आर्थिक लेनदेन की पूरी तस्वीर का प्रतिनिधित्व करता है
- लेखांकन अर्थ में बीओपी हमेशा संतुलित रहता है लेकिन परिचालन अर्थ में यह अधिशेष या घाटा हो सकता है

व्यापार संतुलन (BOT)

BOT एक वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग देश के निवासियों और विदेशी देशों के निवासियों के बीच केवल दृश्यमान आर्थिक लेनदेन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है।

- **BOT** केवल दृश्य वस्तुओं के आदान-प्रदान यानी केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात को ध्यान में रखता है
- इसलिए **BOT** देश के आर्थिक लेनदेन की आंशिक तस्वीर का प्रतिनिधित्व करता है
- वस्तुओं के निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है

व्यापार संतुलन = निर्यात-आयात

● यह अधिशेष, संतुलन की कमी हो सकती है
बीओपी में प्रविष्टियाँ

- **BOP** विवरण में दो प्रविष्टियाँ हैं। यानी क्रेडिट प्रविष्टि (+) और डेबिट प्रविष्टि (-)
 - जिन लेनदेन से विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है उनका मूल्य क्रेडिट (+) पक्ष में दर्ज किया जाएगा तथा जिन लेनदेन से विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह होता है उनका मूल्य डेबिट (-) पक्ष में दर्ज किया जाएगा।
- नोट: यह लेनदेन की प्रकृति नहीं है बल्कि विदेशी मुद्रा का प्रवाह या बहिर्वाह है जो बीओपी में प्रविष्टियों को निर्धारित करता है

BOP और BOT के बीच अंतर

आधार	भुगतान संतुलन (बीओपी)	व्यापार संतुलन (बीओटी)
अर्थ	बीओपी एक वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग देश के निवासियों और विदेशी देशों के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेनदेन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है	बीओटी एक वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग देश के निवासियों और विदेशी देशों के निवासियों के बीच केवल दृश्यमान आर्थिक लेनदेन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है।
अवयव	दृश्यमान और अदृश्य वस्तुएँ भी	
दायरा	व्यापक, क्योंकि यह आर्थिक लेनदेन की पूरी तस्वीर का प्रतिनिधित्व करता है	केवल दृश्यमान वस्तुएँ
लेन-देन की प्रकृति	इसमें वर्तमान के साथ-साथ पूंजीगत लेनदेन भी शामिल है	संकीर्ण, क्योंकि यह बीओपी का एक हिस्सा है और आर्थिक लेनदेन की आंशिक तस्वीर का प्रतिनिधित्व करता है
स्थिति	लेखांकन अर्थ में यह हमेशा संतुलन होता है, परिचालन अर्थ में नहीं हो सकता है	इसमें केवल वर्तमान लेनदेन शामिल हैं

BOP की संरचना/घटक

- एक BOP के दो घटक होते हैं
चालू खाता और पूंजी खाता
- एक BOP में दो प्रविष्टियाँ (डबल एंट्री) होती हैं
क्रेडिट प्रविष्टियाँ (+) और डेबिट प्रविष्टियाँ (-)

(ए) चालू खाता

- एक चालू खाता उन सभी लेनदेन को रिकॉर्ड करता है जो किसी देश की संपत्ति और देनदारियों को प्रभावित नहीं करते हैं
- ये लेनदेन केवल वर्तमान प्रकृति के हैं

चालू खाता के घटक

- माल का आयात और निर्यात (पण्य व्यापार)
 - सेवाओं का आयात और निर्यात (अदृश्य व्यापार)
 - एकतरफ़ा स्थानान्तरण (अप्रत्याशित स्थानान्तरण)
- (बी) पूंजी खाता

- एक Capital A/c उन सभी लेनदेन को रिकॉर्ड करता है जो किसी देश की संपत्ति या देनदारियों को प्रभावित करते हैं
- पूंजी खाते का संबंध वित्तीय लेनदेन से है
- इसका देश की आय, रोजगार और उत्पादन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है
- पूंजी खाता चालू खाते में उत्पन्न होने वाली कमजोरी को दूर करने के लिए तैयार किया जाता है अर्थात् चालू खाते में उत्पन्न अधिशेष/घाटे को ठीक करने के लिए तैयार किया जाता है।

पूंजी खाते के घटक

- उधार लेना और उधार देना
- निजी लेनदेन:
- आधिकारिक लेनदेन
- प्रत्यक्ष निवेश:
- पोर्टफोलियो निवेश:
- आधिकारिक रिजर्व लेनदेन

भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है:

BOP सदैव संतुलित रहता है। इस कथन को निम्नलिखित तर्कों से सिद्ध किया जा सकता है

- BOP डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के सिद्धांतों पर आधारित है
- तदनुसार प्रत्येक लेनदेन में दोहरी प्रविष्टियाँ होती हैं (कॉन्ट्रा प्रविष्टियाँ)
- प्रत्येक क्रेडिट/डेबिट प्रविष्टि में डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टि का आकार समान होता है
- अतः कुल शेष शून्य है
- इसलिए बीओपी हमेशा लेखांकन अर्थों में संतुलित रहता है
- परिचालन अर्थ में यह नहीं हो सकता है। यह अधिशेष या घाटा हो सकता है।

स्वायत्त मदें और समायोजन मदें।

(ए) स्वायत्त आइटम

- यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेनदेन को संदर्भित करता है जो कुछ स्वतंत्र उद्देश्यों के कारण होता है, यह आर्थिक उद्देश्य हो सकता है जैसे लाभ अधिकतमकरण
- ये लेनदेन काउंटी के बीओपी राज्य से स्वतंत्र हैं
- ये आइटम बीओपी के वर्तमान खाते और पूंजी खाते दोनों में दर्ज किए जाते हैं
- चूंकि ये बीओपी के कथन से ऊपर हैं, इन्हें "लाइन आइटम से ऊपर" भी कहा जाता है।

(बी) समायोजन मदें:

- यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेनदेन को संदर्भित करता है जो बीओपी में सरकारी वित्तपोषण जैसी अन्य गतिविधियां करता है
- ये लेनदेन बीओपी में उत्पन्न असंतुलन को ठीक करने के लिए किए जाते हैं
- उदाहरण के लिए: बीओपी पहचान बनाए रखने के लिए आधिकारिक बस्तियों को एक समायोजनकारी वस्तु के रूप में देखा जाता है
- इन्हें केवल BOP के Capital A/c में दर्ज किया जाता है
- चूंकि ये बीओपी के भीतर हैं, इसलिए इन्हें "लाइन आइटम के नीचे" भी कहा जाता है।

BOP में असंतुलन

- BOP में असंतुलन BOP में अधिशेष या कमी के रूप में उत्पन्न होता है।
- BOP असंतुलन नीति निर्माताओं के लिए एक गंभीर मुद्दा है
- दीर्घकालिक बीओपी घाटे के कारण विश्व समुदाय में अर्थव्यवस्था का स्तर नीचे गिर जाता है

BOP में असंतुलन निम्नलिखित कारणों से होते हैं

(ए) आर्थिक कारक

- बड़े पैमाने पर विकासात्मक व्यय
- सामान्य व्यावसायिक गतिविधि में चक्रीय उतार-चढ़ाव
- घरेलू देश में मुद्रास्फीति की उच्च दर
- लोगों की मांग के पैटर्न में बदलाव

(बी) राजनीतिक कारक

- राजनीतिक अस्थिरता के कारण बड़े पैमाने पर पूंजी का बहिर्प्रवाह हो सकता है
- राजनीतिक गड़बड़ी के कारण सरकारी नीतियों को बदलने से निवेशकों का विश्वास खत्म हो जाता है

(ए) सामाजिक कारक

- स्वाद, पसंद और फैशन में बदलाव से आयात और निर्यात प्रभावित हो सकता है
- प्रदर्शन प्रभाव से आयात में वृद्धि होती है

विदेशी विनिमय दर को किसी अन्य मुद्रा के संबंध में घरेलू मुद्रा की कीमत के रूप में परिभाषित किया गया है।

विनिमय दर प्रणालियों के प्रकार

1. **स्थिर विनिमय दर प्रणाली या निर्धारित विनिमय दर प्रणाली:** स्थिर विनिमय दर देश की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है और यह बाजार की शक्तियों पर निर्भर नहीं होती है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के लाभ

स्थिर विनिमय दर प्रणाली के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं

1. यह विदेशी मुद्रा में स्थिरता सुनिश्चित करता है जो विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करता है।
2. मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होती है जो उसे बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाती है।
3. यह देश के लिए विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है।
4. यह किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दर को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है।

स्थिर विनिमय दर प्रणाली के नुकसान

1. अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए विदेशी भंडार बनाए रखने की निरंतर आवश्यकता है।
2. सरकार के पास उस लचीलेपन की कमी हो सकती है जो अर्थव्यवस्था को आर्थिक झटका लगने की स्थिति में वापस लौटने के लिए आवश्यक है।

2. लचीली विनिमय दर प्रणाली: लचीली विनिमय दर प्रणाली को फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह आपूर्ति और मांग की बाजार शक्तियों पर निर्भर है। फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली में केंद्रीय बैंकों या सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली के लाभ निम्नलिखित हैं

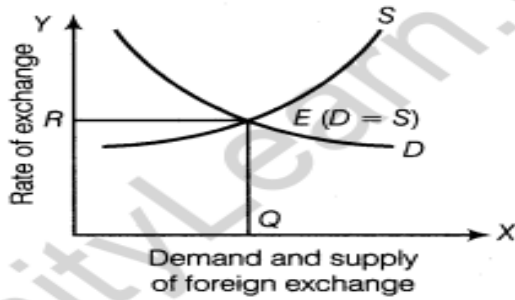
1. इस विनिमय प्रणाली में विदेशी भंडार बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
2. भुगतान संतुलन में कोई भी कमी या अधिशेष इस प्रणाली में स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है।

फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली के कुछ नुकसान निम्नलिखित हैं

1. यह सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है जिससे बाजार में मुद्राओं की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
2. यदि विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव बहुत अधिक है तो इससे देशों के बीच पूंजी की आवाजाही में समस्या हो सकती है और विदेशी व्यापार पर भी असर पड़ सकता है।
3. यह किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश को हतोत्साहित करेगा।

विनिमय दर का निर्धारण विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति शक्तियों द्वारा किया जाता है।

विनिमय की संतुलन दर का निर्धारण संतुलन विनिमय दर उस बिंदु पर प्राप्त की जाती है जहां विदेशी मुद्रा की आपूर्ति विदेशी मुद्रा की मांग के बराबर होती है।



3. प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली: प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली स्थिर (प्रबंधित) और लचीली विनिमय दर प्रणालियों का संयोजन है। इस प्रणाली के तहत केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं की खरीद या बिक्री में हस्तक्षेप करते हैं या भाग लेते हैं।

1 अंक वाले प्रश्न

1. बीओपी (भुगतान संतुलन) को इस प्रकार मापा जाता है:
(ए) निर्यात और आयात की दृश्यमान वस्तुओं के बीच अंतर
(बी) निर्यात और आयात की अदृश्य वस्तुओं के बीच अंतर
(सी) सोने के बाहरी और आंतरिक प्रवाह के बीच अंतर
(डी) विदेशी मुद्रा की सभी प्राप्तियों और विदेशी मुद्रा के भुगतान के बीच अंतर

2. व्यापार संतुलन के लेन-देन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में दर्ज किए जाते हैं?

- (ए) दृश्यमान वस्तुएं (बी) अदृश्य वस्तुएं
(सी) पूंजी हस्तांतरण (डी) ये सभी

3. अदृश्य संतुलन से तात्पर्य है:

- (ए) निर्यात - आयात
(बी) व्यापार संतुलन + गैर-कारक सेवाओं का संतुलन
(सी) गैर-कारक सेवाओं का संतुलन + हस्तांतरण का संतुलन
(डी) निर्यात - आयात + कारक सेवाओं का संतुलन

4. निर्यात = 1,000 लाख रुपये, आयात = 1,650 लाख रुपये, व्यापार संतुलन दर्शाता है:

- (ए) 650 लाख रुपये का अधिशेष (बी) 650 लाख रुपये का घाटा
(सी) 2,650 लाख रुपये का शेष (डी) इनमें से कोई नहीं

5. जब अमेरिकी डॉलर रुपये के लिए एक्सचेंज होता है। रुपये की जगह 40 रुपये 50 पहले, घरेलू मुद्रा से पता चलता है:

- (ए) मुद्रा मूल्यहास। (बी) मुद्रा प्रशंसा।
(सी) मुद्रा अवमूल्यन। (डी) इनमें से कोई नहीं

6. निम्नलिखित में से किसके कारण विदेशी मुद्रा की हानि होती है?

- (ए) शेष विश्व से अनुदान (बी) निर्यात
(सी) आयात (डी) उपरोक्त सभी

7. निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी मुद्रा बाजार का कार्य है?

- (ए) क्रेडिट फ़ंक्शन (बी) ट्रांसफर फ़ंक्शन
(सी) हेजिंग फ़ंक्शन (डी) ये सभी

सही विकल्प चुनें:

- (ए) दावा और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, दावे की सही व्याख्या है।
(बी) दावा और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, दावे की सही व्याख्या नहीं है।
(सी) दावा सत्य है, कारण गलत है।
(डी) दावा गलत है, कारण सत्य है।

8. **दावा (ए)** : एक देश हमेशा बीओपी को संतुलित करने की कोशिश करता है यानी, चालू खाते में शेष पूंजी खाते में शेष के बराबर होता है।

कारण (आर) : संतुलित बीओपी शेष विश्व के साथ स्थिर आर्थिक संबंध को इंगित करता है।

9. **दावा (ए)** : बीओपी खाते में संतुलन बनाए रखने के लिए व्यापार की वस्तुओं को समायोजित किया जाता है।

कारण (आर) : समायोजित वस्तुएं स्वायत्त लेनदेन के शुद्ध परिणाम हैं जो बीओपी की स्वायत्त वस्तुओं में असंतुलन को ठीक करने के लिए किए जाते हैं।

10. **दावा (ए)** : विदेश से सेकेंड-हैंड मशीनरी की खरीद भुगतान संतुलन में दर्ज नहीं की जाती है।

कारण (आर) : विदेशों से सेकेंड-हैंड सामानों की बिक्री और खरीद को राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता है।

11. **दावा (ए)** : बाजार में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि को घरेलू मुद्रा की सराहना कहा जाता है।

कारण (आर) : जब घरेलू मुद्रा की सराहना होती है, तो घरेलू देश का निर्यात बढ़ जाता है।

12. **दावा (ए)** : यदि अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा बाजार में पहले के 64 रुपये के बजाय 70 रुपये पर विनिमय करता है, तो इसे रुपये का मूल्यहास कहा जाता है।

कारण (आर) : यदि अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा बाजार में पहले 60 रुपये के बजाय 45 रुपये पर विनिमय करता है, तो इसे रुपये की सराहना कहा जाता है।

5. बीओपी में शामिल स्वायत्त और समायोजनीय वस्तुओं के बीच अंतर बताएं।
6. भुगतान संतुलन खाते में स्वायत्त और समायोजनकारी लेनदेन के बीच अंतर स्पष्ट करें। प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दीजिए।
7. तीन कारण बताइए कि लोग विदेशी मुद्रा की इच्छा क्यों रखते हैं?
8. विदेशी मुद्रा की आपूर्ति के कोई तीन/चार स्रोत बताइये।
9. विदेशी विनिमय दर और इसकी मांग के बीच संबंध स्पष्ट करें।
10. विदेशी विनिमय दर और विदेशी मुद्रा की आपूर्ति के बीच संबंध स्पष्ट करें।

अध्याय 1: स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था।

औपनिवेशिक शासन के परिणामस्वरूप निम्न स्तर का आर्थिक विकास (जीडीपी) हुआ

- ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी।
- कृषि, हस्तशिल्प उद्योग जैसे रेशम, कपास, पत्थर का काम आदि और अन्य गतिविधियों ने कई लोगों को जीविकोपार्जन में मदद की।
- भारतीय उत्पादों में उनकी उच्च गुणवत्ता और शानदार शिल्प कौशल के कारण वैश्विक बाजार में बड़ी संभावनाएं थीं।
- औपनिवेशिक अर्थशास्त्रियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उच्च हित हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया और भारतीय जनता के कल्याण पर कोई ध्यान नहीं दिया।
- भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने के लिए अपर्याप्त प्रयास किए गए।
- दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फाइंडले शिरर्स, वी.के.आर.वी. राव और आर.सी. देसाई जैसे कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुमान उल्लेखनीय माने गए।

स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियाँ

कृषि क्षेत्र

- उस समय कृषि लाभ पर निर्भरता प्रमुख थी, लगभग 85% भारतीय आबादी का मुख्य व्यवसाय खेती थी।
- कम कृषि उत्पादकता देखी गई, जिसके कारण भूमि निपटान नीतियों में कई नए परिचय और संशोधन हुए, जिससे कुछ वृद्धि हुई।
- कृषि का व्यावसायीकरण कई क्षेत्रों में नकदी फसलें बोने का कारण था।
- सीढ़ीदार निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और मिट्टी के अलवणीकरण में निवेश की कमी के कारण कृषि का धीमा विकास हुआ।

औद्योगिक क्षेत्र

- अंग्रेजों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए बड़े औद्योगिक विकास को रोका।
- ब्रिटेन में आधुनिक उद्योगों के विकास के लिए भारत केवल कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया।
- ब्रिटेन से तैयार माल को भारतीय बाजारों में लाभदायक उत्पादों में बदलने के लिए वापस भारत लाया गया।
- स्थानीय उद्योगों में गिरावट के कारण कारीगर और शिल्पकार बेरोजगार हो गए।
- 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योग की प्रगति धीरे-धीरे हुई।
- अधिकांश सूती कपड़ा मिलें महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में स्थित थीं, जबकि अधिकांश जूट मिलें बंगाल में स्थित थीं।

विदेश व्यापार

- सरकार ने अन्य देशों में भारत के निर्यात पर मात्रा, संरचना और संरचना के संदर्भ में कई प्रतिबंध लगाए, जिसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- रेशम, कपास, ऊन, जूट और नील जैसे कच्चे माल को प्राथमिक उत्पादों के रूप में भारत से निर्यात किया जाता था।
- ब्रिटेन विदेशी व्यापार का प्रमुख अंग था। चीन, श्रीलंका और फारस (ईरान) जैसे कुछ अन्य देशों को भी अनुमति दी गई थी।
- अंग्रेजों के शोषण के कारण भारतीय धन का बड़े पैमाने पर निष्कासन हुआ।

जनसांख्यिकीय स्थिति

- भारत में अनियमित जनसंख्या वृद्धि हुई।
- दस वर्षों में, नियमित जनगणना कार्य आयोजित किए गए।

- समग्र और महिला साक्षरता दोनों में कम साक्षरता दर ने देश को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में चिह्नित किया।
- चूंकि अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ थीं, बीमारियाँ व्यापक रूप से फैल गईं और मृत्यु दर बढ़ गई।
- शिशु मृत्यु दर खतरनाक रूप से अधिक थी, जिससे नवजात आबादी के भीतर कम जीवन प्रत्याशा का अनुमान लगाया गया था।

व्यावसायिक संरचना

- कार्यबल के भीतर रोजगार सृजन के मामले में कृषि क्षेत्र (70-75%) और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र (15-20%) शीर्ष पर रहे।
- लगभग 17.2% ने अर्थव्यवस्था के सेवा या तृतीयक क्षेत्रों में योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद यह क्षेत्र लोकप्रिय हो गया और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि प्रदान की।
- स्वतंत्रता से ठीक पहले अर्थव्यवस्था के अनियंत्रित स्थिति में चले जाने के कारण धन का असमान वितरण देखा गया।

आधारभूत संरचना

- ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे, बंदरगाह और जल परिवहन का बड़े स्तर पर विकास हुआ। ये प्रणालियाँ भारतीय कच्चे माल के विदेशी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थीं।
- ब्रिटिश तैयार माल की सफलता हासिल करने के लिए व्यापार में औपनिवेशिक हितों को हमेशा प्राथमिकता दी गई।
- रेलवे परिवहन प्रणाली शुरू होने के बाद भारत के कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि हुई। इससे दक्षता में वृद्धि हुई और ब्रिटिश बहीखाता पद्धति के लिए व्यापार के तरीकों को व्यवस्थित किया गया।
- ब्रिटिशों द्वारा अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास को हमेशा दरकिनार कर दिया गया।
- वस्तु विनिमय प्रणाली को नए तरीकों से बदल दिया गया, जिसने दिन-प्रतिदिन के लेनदेन में पैसे का उपयोग शुरू किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रम विभाजन और बड़े पैमाने पर उत्पादन में मदद मिली।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र ब्रिटिश नीतियों और नियमों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित था। भारत जैसी पंगु अर्थव्यवस्था को उज्वल और सुरक्षित भविष्य के लिए गहन ध्यान और अच्छी तरह से क्रियान्वित योजनाओं की आवश्यकता थी।

बहुविकल्पीय प्रश्न(MCQs)

1. निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम दिखाते हुए सही विकल्प चुनें:

- महान विभाजन का वर्ष
- बंगाल में भीषण अकाल पड़ा जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई
- बॉम्बे (मुंबई) से ठाणे तक चलने वाली पहली ट्रेन
- स्वेज़कैनाल का उद्घाटन

विकल्प:

- (iv),(ii),(i),(iii)
- (i),(iv),(iii),(ii)
- (ii) (iii) (iv) (i)
- (iii),(i),(iv),(ii).

2. दावा (ए): ब्रिटिश शासन के दौरान भारत ने व्यापार अधिशेष का अनुभव किया।

कारण (आर): अंग्रेजों ने भारत में अपने प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए व्यापार अधिशेष का इस्तेमाल किया।

विकल्प:

- दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) की सही व्याख्या है
- दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावा (ए) की सही व्याख्या नहीं है
- दावा (ए) सच है लेकिन कारण (आर) गलत है
- दावा (ए) गलत है लेकिन कारण (आर) सच है

3. **दावा (ए)** : भारत प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक और ब्रिटेन में उत्पादित उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं का आयातक बन गया।

कारण (आर): औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और टैरिफ की प्रतिबंधात्मक नीतियों ने भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, संरचना और मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

विकल्प:

- (a) **दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) की सही व्याख्या है**
(b) दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावा (ए) की सही व्याख्या नहीं है
(c) दावा (ए) सच है लेकिन कारण (आर) गलत है
(d) दावा (ए) गलत है लेकिन कारण (आर) सच है।

4. **दावा (ए)** : कृषि क्षेत्र में कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा है

लगभग 75% के साथ।

कारण (आर): सभी राज्यों में कार्यबल की निर्भरता में वृद्धि देखी गई
कृषि क्षेत्र।

विकल्प:

- (a) दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) की सही व्याख्या है
(b) **दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) सही नहीं है**
अभिकथन(ए) की व्याख्या
(c) दावा (ए) सच है लेकिन कारण (आर) गलत है
(d) दावा (ए) गलत है लेकिन कारण (आर) सच है

केस स्टडी-1

पूर्व-उपनिवेश युग में, भारत उन निर्मित वस्तुओं का निर्यात करता था जिनकी मांग दुनिया भर में अधिक थी। औपनिवेशिक प्राधिकरण काल के दौरान भारत का दर्जा कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में सीमित रह गया था।

इस दौरान भारत जूट, कपास, नील, ऊन और चीनी, और पूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे रेशम और ऊनी कपड़े और ब्रिटिश कारखानों में बनी हल्की मशीनरी का आयातक हो गया। स्वेज़ नहर के उद्घाटन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव भी बढ़ गया था।

जिन राष्ट्रों को व्यापार की अनुमति थी, और वे राष्ट्र थे - चीन, सीलोन (श्रीलंका), और फारस (ईरान)। यह देखना दिलचस्प है कि उपनिवेशवादियों ने इस व्यापार पर भी करीब से नजर रखी।

देश की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ा। खाद्यान्न, कपड़े, मिट्टी का तेल जैसी वस्तुएं अपनी कमी से देश को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। विडंबना यह थी कि यह निर्यात अधिशेष कभी भी भारत तक नहीं पहुंच पाया। इसका उपयोग ब्रिटेन में एक बार स्थापित की गई व्यवस्था, ब्रिटिशों के युद्ध व्यय और अदृश्य वस्तुओं के आयात के लिए भुगतान करने के लिए किया गया था। ऐसी क्रूरताओं के कारण अंततः भारत के विदेशी व्यापार के पहल में वृद्धि हुई।

प्रश्न:

1. स्वेज़ नहर के खुलने से ब्रिटिश लोगों को क्या लाभ हुआ?

उत्तर- परिवहन की लागत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंच आसान हो गई।

2. निर्यात अधिशेष का उपयोग भारतीय उद्योग के कल्याण के लिए किया गया। (सही/गलत)

उत्तर-गलत

3. उन देशों के नाम बताइए जिनके साथ भारत का विदेशी व्यापार था।

उत्तर- ब्रिटेन, चीन, सीलोन, फारस।

4. खाद्यान्न की कमी का कारण क्या है?

उत्तर- फसलों का व्यावसायीकरण.

6 अंक वाले प्रश्न

1. भारत में अंग्रेजों द्वारा किये गये सकारात्मक योगदान की चर्चा कीजिये।

उत्तर-भारत में अंग्रेजों द्वारा किये गये योगदान निम्नलिखित हैं:

1. भारतीय कृषि के इतिहास में कृषि का व्यावसायीकरण महत्वपूर्ण था। इससे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता मिली।
2. भारत को मुक्त व्यापार का पालन करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे निर्यात की संख्या में वृद्धि हुई।
3. व्यापार को बढ़ाने के लिए रेलवे और सड़क मार्गों का विकास।
4. अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ावा देकर भारत बाहरी दुनिया से संवाद करने में सक्षम हुआ।
5. कार्य विभाजन से मौद्रिक प्रणाली और उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

अध्याय दो

भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990

- भारत ने सोवियत संघ की योजना के असाधारण सफलता परिणामों से प्रेरित होकर समाजवाद को चुना।
- **पूंजीवादी अर्थव्यवस्था** एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें लाभ के उद्देश्य से उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, उदाहरण के लिए, औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में। आर्थिक निर्णय बाज़ार की शक्तियों - माँग और आपूर्ति - द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसे **बाज़ार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है**।
- **समाजवादी अर्थव्यवस्था** एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है, उदाहरण के लिए, यूएसएसआर। आर्थिक गतिविधियों को चलाने का मुख्य उद्देश्य कल्याण और सेवा उद्देश्य को बढ़ाना है।
- **मिश्रित अर्थव्यवस्था** एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के साथ-साथ निजी व्यक्तियों दोनों के पास होता है, उदाहरण के लिए, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
- एक आर्थिक **योजना** उन लक्ष्यों की एक प्रस्तावित सूची है जिन्हें एक अर्थव्यवस्था समय के एक विशिष्ट रिकॉर्ड के भीतर हासिल करना चाहती है। यह सूचीबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुर्लभ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के इष्टतम तरीके सुझाता है।
- भारत में योजना पाँच वर्ष की अवधि के लिए बनाई जाती है; इसलिए, इसे **पंचवर्षीय योजनाएँ कहा जाता है**।
- योजना **आयोग की** स्थापना वर्ष 1950 में पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन के लिए की गई थी, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे।
- **पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य**
 - **आर्थिक वृद्धि का** तात्पर्य एक निश्चित अवधि में देश की जीडीपी में वृद्धि से है।
 - **आधुनिकीकरण को** वस्तुओं और सेवाओं की समग्र उत्पादकता और उत्पादन की कुल मात्रा को बढ़ाने के लिए अधिक स्वीकार्यता और आधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकी को अपनाने के रूप में परिभाषित किया गया है।
 - **आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना-** इसका तात्पर्य देश के अपने संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इससे विदेशों पर आर्थिक निर्भरता कम होती है और देश आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनता है।
 - **इकित्ती का** तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद के समान वितरण से है ताकि उच्च आर्थिक विकास के कारण होने वाले लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों द्वारा साझा किए जा सकें। समता का तात्पर्य सामाजिक न्याय के साथ समतामूलक समाज से है।
- **भूमि सुधार की आवश्यकता**
 - स्वतंत्रता के समय, भारतीय कृषि क्षेत्र को बहुत कम उत्पादकता के साथ चित्रित किया गया था।
 - **जमींदारी** प्रणाली के प्रचलन के कारण था, जो उच्च करों के रूप में कृषकों पर अत्यधिक दबाव डालती थी।
 - इसके अलावा, भूमि जोत आकार में छोटी और बिखरी हुई थी। इससे आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग में बाधा उत्पन्न हुई।
 - भूमि जोत में भारी असमानताएँ थीं।
 - कृषि मूलतः निर्वाह प्रकृति की थी, अर्थात् मुख्य रूप से स्वयं उपभोग और आजीविका कमाने के लिए।

- **भूमि सीमा का** अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली भूमि की कानून द्वारा निर्धारित निश्चित (अधिकतम) मात्रा। भूमि सीमा निर्धारण के पीछे दो उद्देश्य थे:
 - भूमि जोत के स्वामित्व की समानता को बढ़ावा देना
 - कम हाथों में भूमि जोत की सघनता को कम करना।
- HYV बीजों, आधुनिक तकनीकों और इनपुट जैसे उर्वरक, सिंचाई सुविधाओं और सरकार द्वारा सब्सिडी वाले ऋण के उपयोग की शुरुआत के कारण, वर्ष 1967-68 में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 25% की वृद्धि हुई। खाद्यान्न की इस पर्याप्त वृद्धि को 'हरित क्रांति' के नाम से जाना जाता है।

- **विपणन योग्य अधिशेष का** तात्पर्य किसान द्वारा उत्पादित कुल उत्पादन और उसके अपने खेत की खपत के बीच के अंतर से है। अर्थात्, कृषि उत्पादन की वह मात्रा जिसे बाज़ार में बिक्री के लिए पेश किया जा सकता है।

विपणन योग्य अधिशेष = किसान द्वारा उत्पादित कुल कृषि उत्पादन - कृषि उत्पादन की अपनी खपत

- **सब्सिडी (सरकारी सहायता)** का अर्थ है किसानों को कुछ महत्वपूर्ण इनपुट रियायती दर पर उपलब्ध कराना जो इसकी वास्तविक बाजार दर से बहुत कम है।
- **सब्सिडी के पक्ष में तर्क**
 - सीमांत एवं भूमिहीन किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण
 - किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया
 - ग्रामीण असमानताओं को कम करने में मदद करता है
 - किसानों को जोखिम उठाने की सुविधा प्रदान करता है
- **सब्सिडी के विरुद्ध तर्क**
 - संभावित किसानों द्वारा इसका आनंद लिया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का गलत आवंटन होता है
 - बाजार मूल्य में हेरफेर करता है, उदाहरण के लिए, किसानों को रियायती दर पर बिजली की आपूर्ति की जाती है जिससे दुर्लभ संसाधनों की बर्बादी हो सकती है।
 - शुरुआत में प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन का आकलन करने के बाद बाद के चरण में इसे बंद कर देना चाहिए।
 - उर्वरक उद्योगों का पक्ष लिया जाता है, जिन्हें अपने बाजार हिस्सेदारी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए, उर्वरकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते हैं।
- **औद्योगिक नीति संकल्प 1956** सरकार की एक घोषणा थी जिसे सामाजिक न्याय के साथ उच्च आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए तेजी से औद्योगीकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह संकल्प दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार और समाज के समाजवादी पैटर्न को विकसित करने की आधारशिला बना।

आईपीआर 1956 के प्रमुख तत्व हैं:

- **तीन श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया :
 - **श्रेणी 1** : विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व में स्थापित और विकसित उद्योग।
 - **श्रेणी 2** : निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों द्वारा स्थापित उद्योग।
 - **श्रेणी 3**: शेष उद्योगों को निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया।
- निजी क्षेत्र में उद्योग सरकार से **लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही स्थापित किये जा सकते थे।**
- औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय असमानता को मिटाने के लिए सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की **औद्योगिक रियायतें प्रदान कीं।**
- **लघु उद्योग (एसएसआई)** छोटी औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनमें पाँच लाख रुपये तक का निवेश हो सकता है। एसएसआई की विशेषताएं हैं:
 - ये ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय असमानता को कम करने के साधन के रूप में काम करते हैं- जैसा कि *कर्वे समिति ने सिफारिश की थी।*
 - चूंकि एसएसआई श्रम गहन तकनीकों को नियोजित करते हैं, इसलिए वे रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं।
 - लघु उद्योग बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते; इसलिए उन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता है।
 - एसएसआई को कम उत्पाद शुल्क और आसान और सस्ते ऋण के रूप में रियायतें दी जाती हैं।

• व्यापार नीति: आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण

- यह एक अंतर्मुखी व्यापार रणनीति को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य आयात को उन वस्तुओं से प्रतिस्थापित करना है जिनका उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जा सकता है।

आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण का महत्व

- घरेलू उद्योगों को विदेशी उद्योगों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने से बचाया।
 - घरेलू उद्योगों को बढ़ने के लिए संरक्षित वातावरण प्रदान किया।
 - दुर्लभ विदेशी मुद्रा को संरक्षित करने में मदद मिली।
 - भारत में औद्योगीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान की गई।
 - भारत को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन प्राप्त करने में सुविधा हुई, जिससे विदेशी निर्भरता कम हुई।
- **टैरिफ का** तात्पर्य आयातित वस्तुओं पर लगाए गए करों से है। टैरिफ लगाने से आयात घरेलू वस्तुओं की तुलना में अपेक्षाकृत महंगा हो जाता है, जिससे *अप्रत्यक्ष रूप से आयात हतोत्साहित हो जाता है*। इसलिए, वे दुर्लभ विदेशी मुद्रा भंडार पर अत्यधिक बोझ को कम करने में मदद करते हैं।
 - **मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर)** उन वस्तुओं की मात्रा पर सीमा या कोटा के रूप में प्रतिबंध को संदर्भित करते हैं जिन्हें या तो आयात या निर्यात किया जा सकता है। क्यूआर आमतौर पर आयात पर (गैर-टैरिफ उपायों को संदर्भित करता है) जो विदेशी वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने और भुगतान संतुलन (बीओपी) घाटे को कम करने के लिए लगाए जाते हैं।
 - **कोटा को** माल की अधिकतम मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे घरेलू उत्पादकों द्वारा आयात या निर्यात किया जा सकता है।
 - **योजना के लक्ष्यों की उपलब्धियाँ**
 - योजना अवधि के दौरान **राष्ट्रीय आय में 4.1% प्रति वर्ष की वृद्धि** हुई है।
 - योजना प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रति व्यक्ति आय 2% प्रति वर्ष की दर से **बढ़ी है**।
 - **पूंजी निर्माण की दर** (जो बचत और निवेश की दर पर निर्भर करती है) में काफी **वृद्धि हुई है**।
 - भूमि सुधारों की शुरुआत और पर्याप्त तकनीकी सुधार **कृषि क्षेत्र में योजना की दो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं**।
 - **योजना की विफलता**
 - **गरीबी** - भारत की लगभग 21.8% जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।
 - **बेरोजगारी** - बेरोजगार आर्थिक विकास की उपलब्धि बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने की योजनाओं की विफलता की पुष्टि करती है।
 - **उच्च मुद्रास्फीति दरें** - मुद्रास्फीति की उच्च दरों ने अमीर और गरीबों के बीच आर्थिक और आय असमानता को बढ़ा दिया है।
 - **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा** - बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता के साथ-साथ इसकी अपर्याप्तता ने बहुसंख्यक आबादी तक आर्थिक विकास के लाभों को पहुँचाना मुश्किल बना दिया है।

प्रश्न-उत्तर :

प्रश्न 1:- नियोजन उद्देश्य के रूप में समानता के साथ विकास की व्याख्या करें।

प्रश्न 2:- योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका क्यों दी गई?

प्रश्न 3:- आई.पी.आर. 1956 के तहत निजी क्षेत्र को क्यों और कैसे विनियमित किया गया।

कॉलम - I कॉलम - II

- | | |
|------------------|--|
| A. भूमि सीमा | i. अधिक उपज देने वाली बीज किस्मों का उपयोग कर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि |
| B. भूमि सुधार | ii. बाज़ार में बेची जाने वाली कृषि उपज का हिस्सा |
| C. हरित क्रांति | iii. किसी व्यक्ति के लिए भूमि धारण की अधिकतम सीमा तय करना। |
| डी. विपणन अधिशेष | iv. भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन (जोतने वालों को भूमि) |

ए - III बी - IV सी - आईडी - II

कॉलम - I

- A. भारत का विभाजन
- B. योजना आयोग द्वितीय
- C. टिस्को का निगमन
- D. भारत की पहली आधिकारिक जनगणना

कॉलम - II

- I 1950
- II 1947 की स्थापना
- III 1881
- IV 1907

उत्तर:-ए - II बी - आईसी - IV डी - III

निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें

औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, औद्योगीकरण की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी भूमिका रखने का, सरकार की स्पष्ट घोषणा थी। 1956 का यह प्रस्ताव ही दूसरी पंचवर्षीय योजना का रोडमैप था। IPR-1956 में उद्योगों का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया गया। देश के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिक भूमिका दी गई थी। केवल सरकार से लाइसेंस के माध्यम से ही निजी क्षेत्र में ही उद्योग स्थापित किये जा सकते थे।

औद्योगिक लाइसेंसिंग का मुख्य विचार था- देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना। पिछड़े क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के माध्यम से उद्योग स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार की औद्योगिक रियायतें प्रदान की गयी थी। जैसे- कर माफ़ी और रियायती बिजली आपूर्ति आदि। कर्वे समिति (1955) ने भी लघु उद्योगों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। जहाँ तक संभव हो, घरेलू उद्योग विकास के लिए विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित रखने का लक्ष्य ही रखे गए थे। जिसके लिए भारी आयात शुल्क में कमी और आयात कोटा तय करके सुरक्षा प्रदान की गई।

प्रश्न:

1. तीव्र औद्योगीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था?
2. देश के औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में किस क्षेत्र को प्राथमिक भूमिका दी गई?
3. लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है?
4. घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से कैसे बचाया गया?

निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें

हरित क्रांति सरकार द्वारा की गई एक ऐसी पहल थी जिसने गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की है। हरित क्रांति HYV बीजों, सिंचाई सुविधाओं और उर्वरकों के उपयोग के कारण संभव हुई। इससे भारत न केवल आत्मनिर्भर बना बल्कि उसे खाद्यान्न का निर्यातक बनने में भी मदद मिली। लेकिन हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में अधिक प्रमुख था। इसने भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया।

1. उस तत्व की पहचान करें जो हरित क्रांति से संबंधित नहीं है।
क) उन्नत बीज ख) कृषि के लिए नई रणनीति ग) उर्वरक घ) जनसंख्या में वृद्धि

2. हरित क्रांति में (HYV/HVY/जैविक) बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया।
3. हरित क्रांति किन राज्यों में तुलनात्मक रूप से अधिक सफल रही?

4. भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति की ओर अग्रसर है लेकिन (प्राथमिक/माध्यमिक/तृतीयक) क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है।

अभिकथन कारण आधारित प्रश्न

1. दावा (ए) भूमि सुधार और हरित जैसी प्रमुख नीतिगत पहल क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद की कारण (आर) कृषि पर निर्भर लोगों के अनुपात में गिरावट नहीं आई आशा के अनुसार।

- a) दावा और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, दावे की सही व्याख्या है।
- बी) दावा और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, दावे की सही व्याख्या नहीं है।
- ग) दावा सत्य है लेकिन कारण गलत है।
- घ) दावा गलत है लेकिन कारण सत्य है।

2. दावा (ए): विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए, सरकार को टैरिफ दरों को कम करने, निर्यातकों को ऋण सुविधाएं देने और उन्हें बेहतर ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने का सहारा लेना चाहिए।

कारण (आर): विदेशी व्यापार देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।

a) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण इसकी सही व्याख्या है दावा.

b) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण इसकी सही व्याख्या नहीं है दावा.

ग) दावा सत्य है लेकिन कारण गलत है।

घ) दावा गलत है लेकिन कारण सत्य है

"आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति - 1991"

आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति का अर्थ:- जून 1991 में नरसिम्हाराव सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। इस दिशा को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है) के रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू किया गया था। इस नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने निजी कंपनियों को कई ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी जो पहले केवल सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। इस नई आर्थिक नीति के कार्यान्वयन के पीछे मुख्य कारण लगातार नकारात्मक भुगतान संतुलन (बीओपी) था। एक नई आर्थिक नीति अपनाई गई, जिसके तहत आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला प्रस्तावित की गई।

आर्थिक सुधार 'विकास और विकास' की गति को तेज करने के लिए निर्देशित आर्थिक नीतियों के एक समूह को संदर्भित करते हैं। नई आर्थिक नीति के तीन व्यापक घटक निम्नलिखित हैं:

- उद्योग और व्यापार के लिए 'लाइसेंसिंग (एल)' के स्थान पर 'उदारीकरण (एल)' की नीति।
- उद्योगपतियों के लिए 'कोटा (Q)' प्रणाली के स्थान पर 'निजीकरण (P)' की नीति। और
- आयात और निर्यात के लिए 'परमिट (पी)' के स्थान पर 'वैश्वीकरण (जी)' की नीति।

इस प्रकार, एलपीजी को 1991 में एलक्यूपी (LQP= License Quota Permit) को प्रतिस्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया था।

2. नई आर्थिक नीति के तत्व:- ये तीन हैं, (ए) उदारीकरण, (बी) निजीकरण और (सी) वैश्वीकरण

(ए) उदारीकरण का अर्थ:- अर्थव्यवस्था की मुक्ति का अर्थ है उत्पादक इकाइयों की सरकार के प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से मुक्ति। इसमें निम्नलिखित सुधार किये गये।

- औद्योगिक क्षेत्र में सुधार: ए) औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन, बी) सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी, सी) एसएसआई द्वारा उत्पादन का आरक्षण रद्द करना, डी) बाजार शक्तियों द्वारा मूल्य निर्धारण, ई) पूंजीगत वस्तुओं का आयात
- वित्तीय क्षेत्र में सुधार: ए) वित्त क्षेत्र के सुविधाप्रदाता के रूप में आरबीआई की भूमिका बी) निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना सी) विदेशी निवेश एफडीआई
- कर सुधार: ए) प्रत्यक्ष कर में कमी बी) अप्रत्यक्ष कर-जीएसटी में सुधार सी) कर भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाना
- विदेशी मुद्रा सुधार: ए) रुपये का अवमूल्यन बी) लचीली विदेशी विनिमय दर निर्धारण
- व्यापार और निवेश नीति सुधार: ए) आयात और निर्यात की मात्रा प्रतिबंध को हटाना बी) टैरिफ दर का प्रतिबंध सी) आयात के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को हटाना डी) आयात शुल्क को हटाना।

(बी) निजीकरण का अर्थ:- यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है या उसका प्रबंधन करता है

निजीकरण की आवश्यकता :- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के खराब प्रदर्शन के कारण निजीकरण की आवश्यकता को बहुत महत्व दिया गया। औद्योगिक नीति 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित की गई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1951-90 की अवधि के दौरान, भारत केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विस्तार के माध्यम से अपने औद्योगिक आधार में विविधता ला सका। इसके माध्यम से ही संरचनात्मक परिवर्तन हो सके और भारतीय किसान आजीविका के लिए उद्योगों की ओर बढ़ने लगे, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने लगी। आगे चलकर धीरे-धीरे इनमें से अधिकांश उद्योग सामाजिक बोझ बन गये। इन उद्योगों का लगातार बढ़ता घाटा सरकार के लिए सिरदर्द बन गया और इन उद्योगों में लीकेज, अक्षमता, चोरी और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि निजीकरण ही इनका एकमात्र समाधान बन गया।

निजीकरण के फायदे और नुकसान:-

निजीकरण के लाभ	निजीकरण के नुकसान
----------------	-------------------

> जीडीपी के आकार में सुधार	> सामाजिक हित के स्थान पर स्वहित को महत्व
> अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार	> सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कमी रहेगी
> बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या में वृद्धि	> वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ेगा
> उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि	> गरीब वर्ग को अधिक संघर्ष करना पड़ेगा
> निवेश में बढ़ोतरी	

(सी) वैश्वीकरण का अर्थ:- वैश्वीकरण का अर्थ है मुक्त व्यापार, पूंजी और श्रम की मुक्त गतिशीलता आदि के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना।

भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु प्रमुख नीति सूत्र:-

- > विदेशी निवेश सीमा में वृद्धि > आंशिक परिवर्तनीयता
- > दीर्घकालिक व्यापार नीति > टैरिफ में कमी
- > मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना

आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति का मूल्यांकन:- इसके मूल्यांकन से तात्पर्य है इसके अच्छे और बुरे प्रभाव-

नई आर्थिक नीति के अच्छे और बुरे प्रभाव	
एनईपी के अच्छे प्रभाव:-	एनईपी के बुरे प्रभाव:-
> भारत की उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान	> एकतरफ़ा समृद्धि प्रक्रिया
> राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण	> आर्थिक उपनिवेशवाद
> महंगाई पर लगाम	> उपभोक्तावाद फैला
> उपभोक्ता की सर्वोच्चता	> कृषि की उपेक्षा
> विदेशी मुद्रा में वृद्धि	> विकास प्रक्रिया का शहरी केंद्रीकरण
> एकाधिकार बाजार से प्रतिस्पर्धी बाजार में स्थानांतरण	> बेरोजगारी
> जीवंत अर्थव्यवस्था	> राजकोषीय नीति
> औद्योगिक उत्पादन का उद्देश्य	> औद्योगिक विकास में मंदी या मंदी
> निजी विदेशी निवेश का प्रभाव	

अभ्यास प्रश्न

A. बहुविकल्पीय प्रश्न:-

1. नई आर्थिक नीति अथवा आर्थिक सुधार कब अपनाये गये?

- (ए) वर्ष 1980 (बी) वर्ष 1991 (सी) वर्ष 1990 (डी) वर्ष 1995

2. भारतीय अनुभव के संदर्भ में, सरकार द्वारा नियंत्रण लगाए गए:

- (ए) निजी एकाधिकार फार्मों के विस्तार को रोकना
 (बी) देश के वित्तीय संसाधनों पर बड़े औद्योगिक घरानों के नियंत्रण को रोकना
 (सी) दोनों (ए) और (बी)
 से कोई नहीं

(डी) इनमें

3. निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्र का एक तत्व है?

- (ए) बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (बी) स्टॉक एक्सचेंज बाजार
 (सी) विदेशी मुद्रा बाजार (डी) उपरोक्त सभी

4. निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर विश्व व्यापार बैंक की स्थापना की गई है?

- (ए) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (बी) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
 (सी) व्यापार और सीमा शुल्क सम्मेलन (डी) पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक

5. निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है?

- (ए) वस्तु एवं सेवा कर (बी) संपत्ति कर (सी) आयकर (डी) इनमें से कोई नहीं

6. निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का घटक नहीं है?

- (ए) सरकार द्वारा क्षेत्र के शेयरों की खरीद (बी) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश

(सी) सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की बिक्री

(डी) सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन

7. वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियाँ हैं?

(ए) 5

(बी) 10

(सी) 12

(डी) 10

8. हाल ही में सितंबर 2022 में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है?

(ए) भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम

(बी) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

(सी) भारत संचार निगम लिमिटेड

(डी) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

उत्तर:-	1. बी	2. सी	3. डी	4. सी	5. ए	6. ए	7. सी	8. बी
----------------	-------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------

ख. रिक्त स्थान भरें:-

1. वर्तमान में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

(पांच /दस)

2. भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया?

(1.07.2017/1.01.2020)

3. विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी?

(1.01.1995/1.07.1980)

4. आउटसोर्सिंग _____ की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम है।

(उदारीकरण/वैश्वीकरण)

5. _____ का अर्थ है 'सामाजिक हित' पर 'स्वहित' को प्रधानता देना। (उदारीकरण/निजीकरण)

6. _____ ऐसे 9 लाभ कमाने वाले उद्यमों को संदर्भित करता है जिनकी तुलना महाराजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 दरबारियों से की जाती है जो प्रतिष्ठित और अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति थे। (नवरत्न/नौ रत्न)

7. _____ अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में भारतीय रुपये के मूल्य के मूल्यवर्ग को संदर्भित करता है।
(पुनर्मूल्यांकन/अवमूल्यन)

8. कर सुधार _____ सुधार का एक प्रमुख घटक है।

(मौद्रिक/राजकोषीय)

उत्तर :-	1. पाँच	2. 1.07.2017	3. 1.01.1995	4. वैश्वीकरण	5. निजीकरण	6.नवरत्न
7.अवमूल्यन	8. राजकोषीय	9.अलग				

C. सही या गलत कथन की पहचान करें:-

1. WTO की स्थापना GATT के स्थान पर 1 जनवरी, 1995 को हुई थी, लेकिन GATT 31 दिसंबर, 1995 को समाप्त हो गया।
(सही/गलत)

2. भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 जनवरी, 1935 को हुई थी और 1 जनवरी, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था।
(सही/गलत)

3. भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को प्रारम्भ किया गया था। (सत्य/असत्य)

3. नोटबंदी साल 2015 की एक बड़ी घटना थी. (सही/गलत)

5. वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की संख्या केवल तीन रह गई है जिनमें पहला परमाणु ऊर्जा, दूसरा रेलवे और तीसरा रक्षा उपकरण है। (सही गलत)

उत्तर:-	1. सत्य	2. सत्य	3. सत्य	4. मिथ्या	5.सच		
----------------	---------	---------	---------	-----------	------	--	--

अभिकथन और कारण

निम्नलिखित प्रश्नों में, कथन (ए) के बाद कारण (आर) का कथन आता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें:

- दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावा (ए) का सही स्पष्टीकरण है।
- दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- दावा (ए) सत्य है लेकिन कारण (आर) गलत है।
- दावा (ए) गलत है लेकिन कारण (आर) सच है।

1	दावा (ए)	नई आर्थिक नीति के तहत बाज़ार की शक्तियों पर अधिक निर्भरता रखी गई।
	कारण (आर)	अत्यधिक सरकारी नियंत्रण के कारण भ्रष्टाचार, अनुचित देरी और अक्षमता में वृद्धि हुई।
2	दावा (ए)	भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण बाह्य स्रोत के रूप में उभर रहा है।
	कारण (आर)	भारत कम मजदूरी दरों पर श्रम की प्रचुर आपूर्ति प्रदान करता है।
3	दावा (ए)	उदारीकरण के बाद कर दरों में कमी के कारण कर चोरी में कमी आई है।
	कारण (आर)	कम कर दर से कर-अनुपालन होता है और इसलिए सरकार के लिए अधिक कर राजस्व उत्पन्न होता है।
4	दावा (ए)	नई आर्थिक नीति के तहत आरबीआई की भूमिका एक सुविधा प्रदाता से बदलकर एक नियामक की हो गई है।
	कारण (आर)	अब ब्याज दर की संरचना, आकार और निवेश का पैटर्न बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
5	दावा (ए)	सरकार ने नवरत्नों को अपने-अपने औद्योगीकरण के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के उद्योगों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।
	कारण (आर)	नवरत्न अत्यधिक कुशल लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उद्यम और सरकार के लिए आय जनरेटर थे।

उत्तर:-

- दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण है।
- दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण है।
- दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण है।
- दावा (ए) गलत है लेकिन कारण (आर) सच है।
- दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण है।

मानव पूंजी निर्माण

मानव पूंजी से तात्पर्य एक श्रमिक द्वारा आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए शिक्षा और अनुभव के माध्यम से प्राप्त कौशल और ज्ञान के भंडार से है।

मानव पूंजी: स्रोत: i) स्वास्थ्य ii) शिक्षा iii) नौकरी पर प्रशिक्षण iv) प्रवासन आदि पर निवेश

मानव पूंजी और आर्थिक विकास

• मानव पूंजी की बढ़ी हुई उत्पादकता न केवल श्रम उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है बल्कि आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करती है। मानव पूंजी निर्माण और विकास सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं।

मानव पूंजी निर्माण की समस्याएँ:

- जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर ii) प्रवासन iii) उचित योजना का अभाव iv) शैक्षणिक मानक का निम्न स्तर v) अकुशल प्रणाली vi) गरीबी

शिक्षा का महत्व और उद्देश्य:

- शिक्षा अच्छे नागरिक पैदा करती है
- यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करता है
- यह देश में संसाधनों के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है
- यह लोगों के मानसिक क्षितिज का विस्तार करता है
- यह वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के माध्यम से आर्थिक विकास में मदद करता है।
- इससे मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है

भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित समस्याएं i) निरक्षरों की बड़ी संख्या, ii) अपर्याप्त व्यवसायीकरण, iii) लिंग पूर्वाग्रह, iv) निम्न ग्रामीण पहुंच स्तर, v) शिक्षा पर कम सरकारी व्यय।

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

शिक्षा आयोग ने शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% खर्च करने की सिफारिश की (1964-66)

1998 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति

भारत सरकार द्वारा 2009 में 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' लागू किया गया था।

27 मार्च 2014 को WHO द्वारा भारत को 'पोलियो मुक्त' देश घोषित किया गया था

नई शिक्षा नीति 2020 एक समग्र और एकीकृत शिक्षा दृष्टिकोण की परिकल्पना करती है, जो कौशल विकास, बहु-विषयक शिक्षा और रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू):

1. किसी देश में मानव पूंजी के स्रोत _____ और _____ में निवेश हैं
2. निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं है?
ए. शिक्षा बी. स्वास्थ्य सी. बचत डी. जानकारी
3. पहचानें, निम्नलिखित में से कौन भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या से संबंधित है?
i) प्रतिभा पलायन iii) निम्न शैक्षणिक मानक
ii) बढ़ती जनसंख्या iv) सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन

विकल्प:

4. भारत सरकार ने 6-14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए में , शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी
ए) 1991 बी) 2009 सी) 2014 डी) 2017
5. निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र को नियंत्रित करता है?
a) आईसीएमआर बी) यूजीसी सी) एआईसीटीई डी) आरबीआई
6. किस पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी के महत्व को पहचाना गया है:
a) तीसरा बी) छठा सी) सातवां डी) आठवां

दावा और कारण

7. निम्नलिखित कथन पढ़ें:- दावा (ए) और कारण (आर)
नीचे दिए गए सही विकल्पों में से एक चुनें:
कथन 1. शिक्षा की गुणवत्ता स्कूली शिक्षा के वर्ष और नामांकन दर के संदर्भ में मापी जाती है।
कथन 2. शिक्षा समाज में परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगति को समझने के लिए ज्ञान प्रदान करती है।

विकल्प:

- a) दोनों कथन सत्य हैं।
- b) दोनों ही बयान गलत हैं
- c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- d) कथन 2 सत्य है, परन्तु कथन 1 गलत है।
8. निम्नलिखित कथन पढ़ें:- दावा (ए) और कारण (आर)

नीचे दिए गए सही विकल्पों में से एक चुनें:

कथन 1. मानव पूंजी मनुष्य को अंत तक पहुंचने के साधन के रूप में मानती है।

कथन 2. मानव विकास परिप्रेक्ष्य में, मनुष्य स्वयं में एक साध्य है।

विकल्प:

e) दोनों कथन सत्य हैं।

f) दोनों ही बयान गलत हैं

g) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।

कथन 2 सत्य है, परन्तु कथन 1 गलत है।

9. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कारण सहित सत्य या असत्य।

सरकार द्वारा शुरू किया गया 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम मानव पूंजी निर्माण को बढ़ाने का एक प्रयास है।

10. भारत में तकनीकी जनशक्ति का भंडार बहुत कम है।

उत्तर (1) (स्वास्थ्य और शिक्षा), (2) सी, (3) सी, (4) बी, (5) ए, (6) सी, (7) डी, (8) ए

(9) सच है, क्योंकि 'कौशल मानव पूंजी का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

(10) असत्य, भारत के पास दुनिया में वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति का समृद्ध भंडार है। साथ ही भारत ने इसमें गुणात्मक सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि उनका इष्टतम उपयोग हो।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक:

1. मानव पूंजी को परिभाषित करें।

उत्तर: मानव पूंजी का तात्पर्य एक समय में किसी राष्ट्र के 'कौशल और विशेषज्ञता' के भंडार से है।

2. 'मानव पूंजी निर्माण' को परिभाषित करें।

उत्तर: मानव पूंजी निर्माण से तात्पर्य समय के साथ मानव पूंजी के भंडार में वृद्धि की प्रक्रिया से है।

3. मानव पूंजी निर्माण के संभावित स्रोत क्या हैं?

उत्तर: मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं: i) शिक्षा पर व्यय, ii) स्वास्थ्य पर व्यय, iii) नौकरी पर प्रशिक्षण, iv) वयस्कों के लिए अध्ययन कार्यक्रम,

v) प्रवासन और vi) सूचना पर व्यय।

4. हम भारत में शैक्षिक प्राप्ति में क्षेत्रीय अंतर क्यों देखते हैं?

उत्तर: भारत में शैक्षिक प्राप्ति में क्षेत्रीय अंतर निम्न कारणों से हो सकता है: (i) आय में क्षेत्रीय असमानता और (ii) शैक्षिक सुविधाओं के विकास पर सरकार द्वारा व्यय में असमानता।

3 अंकों के अति लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. मानव पूंजी निर्माण से भौतिक पूंजी की दक्षता बढ़ती है। कैसे?

उत्तर: मानव पूंजी निर्माण से भौतिक पूंजी की दक्षता बढ़ जाती है।

उत्तर: ए. मानव पूंजी निर्माण से उच्च स्तर का कौशल और विशेषज्ञता प्राप्त होती है। तदनुसार, श्रम शक्ति भौतिक पूंजी (संयंत्र और मशीनरी) को संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। यह प्रति यूनिट इनपुट उच्च आउटपुट के माध्यम से भौतिक पूंजी की दक्षता को बढ़ाता है। बी। मानव पूंजी निर्माण से नवप्रवर्तन होता है।

2. मानव पूंजी और मानव विकास के बीच अंतर बताइये

उत्तर: मानव पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता बढ़ाने का एक तरीका मानती है जबकि मानव विकास स्वास्थ्य और शिक्षा को मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानता है। मानव पूंजी मनुष्यों को उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में मानती है जबकि मानव विकास मनुष्यों को स्वयं में उद्देश्यों के रूप में मानता है।

3. भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बीच अंतर बताएं।

भौतिक पूंजी	मानव पूंजी
यह मूर्त है और इसे बाजार में आसानी से बेचा जा सकता है।	यह अमूर्त है और इसे बाजार में नहीं बेचा जा सकता।
समय बीतने के साथ इसका मूल्यहास होता जाता है	स्वास्थ्य एवं शिक्षा में निरंतर निवेश करके मानव पूंजी में गिरावट को कम किया जा सकता है
यह देशों के बीच अधिक मोबाइल है	यह देशों के बीच कम मोबाइल है
इसे इसके मालिक से अलग किया जा सकता है	इसे मालिक से अलग नहीं किया जा सकता

5. किसी राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण इनपुट माना जाता है। कैसे?

उत्तर: किसी राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण इनपुट माना जाता है क्योंकि:

- i) ज्ञान और कौशल: एक बेहतर शिक्षित व्यक्ति के पास अधिक कौशल और ज्ञान होता है जो उत्पादकता बढ़ाता है और इसलिए काम करने और उच्च आय अर्जित करने का अधिक अवसर प्रदान करता है।
- ii) आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना: शिक्षा आधुनिक प्रौद्योगिकी को समझने और अपनाने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करती है। इससे राष्ट्र के उत्पादन और विकास को बढ़ाने में मदद मिलती है।
- iii) जीवन स्तर: शिक्षा लोगों की कमाई की क्षमता को बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाती है।
- iv) आय असमानता में कमी: शिक्षा देश के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की आय अर्जित करने की क्षमता को बढ़ाती है और इस प्रकार आय के वितरण में असमानताओं को कम करती है।

6. क्या सरकार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में शुल्क संरचना को विनियमित करना आवश्यक है?

उत्तर: हाँ, सरकार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में शुल्क संरचना को विनियमित करना आवश्यक है क्योंकि: इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी फीस संरचना की लागत के बारे में पूरी जानकारी नहीं है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एकाधिकार शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अत्यधिक शुल्क वसूल कर शोषण में शामिल हो सकते हैं।

इसलिए, यह सुनिश्चित करने में सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है कि इन सेवाओं को प्रदान करने वाले निजी लोग सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करें और सही शुल्क लें।

7. भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा करें।

उत्तर: भारत में शिक्षा के मामले में महिलाओं की हमेशा उपेक्षा की गई है। हमारी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के कारण शिक्षा की पहुंच हमेशा पुरुष आबादी के प्रति पक्षपाती रही है।

निम्नलिखित कारणों से भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है।

- I) महिला शिक्षा उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने और उन्हें शोषण और घरेलू हिंसा से बचाने के लिए सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है।
- II) महिलाओं की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए महिला शिक्षा आवश्यक है। जिससे महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- III) एक महिला को शिक्षित करने का मतलब एक परिवार को शिक्षित करना है। एक शिक्षित महिला अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकती है और उनकी शिक्षा को सुविधाजनक बना सकती है।

8. किसी कर्मचारी के लिए नौकरी पर प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा करें।

उत्तर: नौकरी पर प्रशिक्षण की भूमिका

- a) प्रत्येक संगठन अक्सर अपने नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को नौकरी पर प्रशिक्षण देने पर व्यय करता है।
- b) ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ी हुई दक्षता, कार्य वातावरण से परिचित होना, व्यावहारिक स्थितियों में सैद्धांतिक अवधारणाओं के बेहतर अनुप्रयोग जैसे लाभ उत्पन्न करने की दृष्टि से प्रदान किए जाते हैं।

9. बताएं, 'मानव पूंजी में निवेश' किसी अर्थव्यवस्था के विकास में कैसे योगदान देता है।

उत्तर: मानव पूंजी निर्माण ('मानव पूंजी में निवेश') से संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है क्योंकि यह उनके कौशल, दक्षता और कार्य उत्पादकता को बढ़ाता है। इन कारकों में वृद्धि से भागीदारी की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन सुनिश्चित होता है। उत्पादन गतिविधि में वृद्धि में अर्थव्यवस्था की आय, रोजगार और उत्पादन में वृद्धि शामिल है। अर्थव्यवस्था में आय के बढ़े हुए स्तर का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक व्यय में किया जाएगा, जो बदले में मानव पूंजी निर्माण की ओर ले जाएगा।

10. "मानव पूंजी निर्माण नवाचार, आविष्कार और तकनीकी सुधार को जन्म देता है।" क्या आप दिए गए कथन से सहमत हैं? वैध तर्कों के साथ अपने उत्तर का समर्थन करें।

उत्तर: दिया गया कथन सही है। मानव पूंजी निर्माण न केवल उपलब्ध मानव संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि नवाचार को भी प्रोत्साहित करता है और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की क्षमता पैदा करता है। शिक्षा में निवेश नई प्रौद्योगिकियों, सुविधाओं के आविष्कार और नवाचार को अपनाने की क्षमता पैदा करता है क्योंकि शिक्षित कार्यबल आम तौर पर आधुनिक प्रौद्योगिकियों और नवाचार के अनुकूल होता है। (कोई अन्य वैध तर्क हो सकता है)

11. निम्नलिखित समाचार रिपोर्ट पढ़ें और उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

किसी देश की मानव पूंजी के निर्धारण में शिक्षा शायद सबसे बुनियादी तत्व है, नवीनतम जानकारी के अनुसार भारत की वयस्क साक्षरता दर 73.2 प्रतिशत है।

जबकि राष्ट्र ने साक्षरता में सुधार करने में भारी प्रगति हासिल की है, यह अभी भी 313 मिलियन अकुशल आबादी का घर है; उनमें से 59% महिलाएं हैं, मूल कारण को खत्म करने के उद्देश्य से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की साक्षरता 2030 तक 100% या कुल साक्षरता प्राप्त करने पर केंद्रित है और आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। एजेंडा प्रौद्योगिकी की मदद से आदिवासी और वन

क्षेत्रों, जेलों, मलिन बस्तियों आदि में बड़े पैमाने पर साक्षरता परियोजनाएं शुरू करना था। प्रौद्योगिकी को विकसित करके, ई-बुक, मोबाइल ऐप और बहुत कुछ की मदद से पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

स्रोत: फाइनेंस एक्सप्रेस, जुलाई 16, 2021

1. शिक्षा किसी देश की _____ राजधानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2. देश में _____ (साक्षरता, निरक्षरता) के स्तर को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर 'प्रधानलेखन अभियान' की सराहना की गई।
3. _____ क्षेत्रों में साक्षरता परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी को शामिल करके, अकुशल आबादी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकती है।
 - a) ट्राइबल बी) जंगल सी) जेल डी) ये सभी
4. शिक्षा और प्रशिक्षण से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभकारी रोजगार में लगाया जा सकता है और आय के वितरण में _____ (समानता/असमानता) को कम किया जा सकता है।

उत्तर: 1) मानव 2) अशिक्षा 3) ये सभी 4) असमानताएँ

ग्रामीण विकास:

भारत में अधिकांश गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुँच नहीं है। हमारी कुल आबादी का लगभग 22% अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहता है।

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाली कृषि पिछले पचास वर्षों में 2.7% की मामूली दर से बढ़ी है। 2007-12 के दौरान कृषि उत्पादन 3.2% की दर से बढ़ा है।
- सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घट रही थी और औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। हालाँकि, कृषि क्षेत्र पर निर्भर आबादी ने अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादक परिवर्तन नहीं दिखाया।
- इसके अलावा, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, 1991-2012 के दौरान कृषि क्षेत्र की विकास दर घटकर 3% प्रति वर्ष हो गई, जो कि पहले के वर्षों की तुलना में कम थी।

□ ग्रामीण विकास की प्रक्रिया:

ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में शामिल हैं -

- (i) मानव संसाधन का विकास
- (ii) बुनियादी ढांचे का विकास
- (iii) भूमि सुधार
- (iv) गरीबी उन्मूलन
- (v) उत्पादक संसाधनों का विकास

□ ग्रामीण ऋण:

- ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं ने कृषि उत्पादकता और गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार सुविधाओं में बड़ी वृद्धि में योगदान दिया है।
- सरकार ने भूमि के सुधार, ट्यूबवेल खोदने, ट्रैक्टर खरीदने आदि के लिए दीर्घकालिक ऋण भी प्रदान किए थे जिन्हें 15-20 वर्षों में चुकाया जा सकता था।
- कुछ ऋण ऐसे हैं जो किसानों को धार्मिक समारोहों, विवाहों का जश्र मनाने के लिए पुराने ऋणों का निपटान करने और फसल खराब होने की स्थिति में परिवार का समर्थन करने के लिए प्रदान किए जाते हैं।
- इन ऋणों को अनुत्पादक ऋण कहा जाता है।

□ ग्रामीण ऋण के स्रोत:

ग्रामीण ऋण उपलब्धता को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

1. गैर-संस्थागत स्रोत- ये भारत में कृषि ऋण के पारंपरिक स्रोत हैं। इनमें साहूकार, रिश्तेदार, व्यापारी, कमीशन एजेंट और जमींदार शामिल हैं।
2. संस्थागत स्रोत- वे सहकारी ऋण, भूमि विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एनबीएनआर) और स्वयं सहायता समूह भी हैं।
 - सूक्ष्म वित्त: स्वयं सहायता समूहों (एसजीएच) के माध्यम से गरीबों तक विस्तारित एक ऋण योजना है
 - प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में बचत को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह (एसजीएच) की स्थापना की गई है। एकत्रित धन से, जरूरतमंद लोगों को उचित ब्याज दरों पर छोटी किस्तों में चुकाने योग्य ऋण दिया जाता है।
 - कृषि विपणन प्रणाली: कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश भर में विभिन्न कृषि वस्तुओं का संयोजन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और वितरण शामिल है।

□ कृषि विपणन में सुधार के उपाय

- (i) विनियमित बाजार- व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन स्थिति बनाने के लिए पहला उपाय बाजारों का विनियमन था। इसका आयोजन किसानों को विक्रेताओं और दलालों के कदाचार से बचाने के लिए किया जाता है।
- (ii) सहकारी विपणन - किसानों द्वारा सामूहिक रूप से उत्पादन बेचने और बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी का लाभ उठाने के लिए विपणन समितियाँ बनाई जाती हैं।
- (iii) ढांचागत सुविधाएं- सरकार। सड़क, रेलवे, गोदाम, पुराने भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयों जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं भी प्रदान की थीं।
- (iv) मानकीकरण और ग्रेडिंग- ग्रेडिंग और गुणवत्ता नियंत्रण किसानों को उनके द्वारा उत्पादित गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए अच्छी कीमत पाने में मदद करता है।
- (v) न्यूनतम समर्थन मूल्य- किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार गेहूं, चावल, मक्का, कपास, गन्ना, दालें आदि कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है।

□ भारत में कृषि बाज़ार के दोष:

- कृषि विपणन की मौजूदा प्रणाली में कोई कमी नहीं है। दोषों में से निम्नलिखित कुछ दोष हैं जिनके कारण विपणन प्रणाली ठीक से व्यवस्थित नहीं है।
- (i) खाद्यान्न और फसलों के लिए भंडारण सुविधा की कमी के कारण चूहों या कीड़ों या बारिश के कारण उत्पादों को नुकसान हुआ है।
 - (ii) संकटकालीन बिक्री: अधिकांश भारतीय किसान गरीब हैं और उनके पास बेहतर कीमत की प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। वे तत्काल उपलब्ध कीमत पर वस्तुएँ बेचते हैं। परिणामस्वरूप, वे अपने उत्पाद को गाँव के साहूकारों या व्यापारियों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
 - (iii) परिवहन की कमी के परिणामस्वरूप किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेचने के लिए लगभग मंडियों तक नहीं पहुंच पाते हैं।
 - (iv) कृषक और उपभोक्ता के बीच बिचौलियों या मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला भी उत्पादक के लाभ को कम कर देगी।
 - (v) इसमें अन्य दोष भी हैं जैसे संस्थागत वित्त की कमी, मार्गदर्शन की कमी आदि। यह भारतीय विपणन प्रणाली को अव्यवस्थित बनाता है।

□ कृषि विपणन में सुधार हेतु उपचारात्मक उपाय

- (i) फार्म स्तर पर भंडारण सुविधाओं का विस्तार और बाजारों और उपभोग केंद्रों में भंडारण और गोदाम सुविधाओं का विस्तार।
- (ii) विनियमित बाजारों की स्थापना।
- (iii) गाँव और मंडियों के बीच परिवहन सुविधाओं में सुधार।
- (iv) सहयोग विपणन समितियों की स्थापना।
- (v) सस्ते ऋण का प्रावधान, विशेषकर संस्थागत स्रोतों से।
- (vi) उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता और उत्पादकों को बेहतर कीमत सुनिश्चित करने के लिए उपज की ग्रेडिंग का प्रावधान।
- (vii) विपणन सूचना की शीघ्र आपूर्ति।

□ कृषि गतिविधि का विविधीकरण:

इसका मतलब है कि कृषि में अतिरिक्त लोगों को कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों में कुछ अन्य संबद्ध गतिविधियों में लाभकारी रोजगार दिया जा सकता है। यह गरीबी को दूर करने, रोजगार में सुधार करने और ग्रामीण कृषि लोगों को पूरी तरह से रोजगार योग्य बनाने के लिए किया जाता है। विविधीकरण में 2 पहलू शामिल हैं:

- (i) फसल उत्पादन का विविधीकरण- इसमें एकल फसल प्रणाली से बहु फसल प्रणाली में बदलाव शामिल है। इसमें फसल पैटर्न को खाद्यान्न से नकदी फसलों की ओर स्थानांतरित करना भी शामिल है। मुख्य उद्देश्य निर्वाह खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बदलाव को बढ़ावा देना है।
- (ii) उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण- चूंकि कृषि पहले से ही अत्यधिक भीड़भाड़ वाली है, इसलिए बढ़ती श्रम शक्ति के बड़े हिस्से को अन्य गैर-कृषि क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर खोजने की जरूरत है। इससे वैकल्पिक स्थायी आजीविका मिलेगी और आय का स्तर बढ़ेगा। गैर-कृषि गतिविधियों में से कुछ हैं पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, मछुआरे, बागवानी, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चमड़ा उद्योग, पर्यटन आदि। इन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं लेकिन उनमें बुनियादी ढांचे और अन्य वित्तीय सहायता का अभाव है।

□ सर वर्गीस कुरियन द्वारा शुरू किया गया **ऑपरेशन फ्लड**, एक ऐसी प्रणाली है, जिसके तहत सभी किसान अलग-अलग ग्रेडिंग के अनुसार अपने दूध उत्पादन को पूल कर सकते हैं और इसे सहकारी समितियों के माध्यम से शहरी केंद्रों में संसाधित और विपणन किया जाता है।

□ 1991-2003 की अवधि को स्वर्णिम क्रांति के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस अवधि के दौरान, बागवानी में नियोजित निवेश अत्यधिक उत्पादक हो गया और यह क्षेत्र एक स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में उभरा।

□ कृषि के विकास में आईटी उद्योगों की भूमिका

- (i) सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। इस बात पर व्यापक सहमति है कि 20वीं सदी में सतत विकास और खाद्य सुरक्षा हासिल करने में आईटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
(ii) उचित जानकारी और सॉफ्टवेयर टूल के माध्यम से, सरकार किसी आपात स्थिति को रोकने या आजीविका को कम करने के लिए खाद्य असुरक्षा और संवेदनशीलता के क्षेत्र की भविष्यवाणी करने में सक्षम है।
(iii) इसका कृषि क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह विभिन्न फसलों को उगाने के लिए प्रौद्योगिकियों और इसके अनुप्रयोग की कीमतों, मौसम और मिट्टी की स्थिति के बारे में जानकारी प्रसारित करता है।
(iv) इससे कृषि के बारे में ज्ञान बढ़ा है।
(v) सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने का उद्देश्य हर गांव को एक ज्ञान केंद्र बनाना है, जहां आईटी रोजगार और आजीविका का एक स्थायी विकल्प प्रदान करता है।

□ **सतत विकास:** यह वह विकास है जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी का विकास करना है। सतत विकास किसी भी संसाधन के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, बल्कि इसका उद्देश्य उनके उपयोग को इस तरह से प्रतिबंधित करना है कि इसे भविष्य की पीढ़ी के लिए छोड़ दिया जाए।

□ जैविक खेती

- (i) जैविक खेती प्राकृतिक रूप से भोजन पैदा करने की प्रक्रिया है।
(ii) यह विधि सिंथेटिक रासायनिक उर्वरकों और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के उपयोग से बचती है। (iii) यह पर्यावरण के अनुकूल है और सतत विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसका पर्यावरण पर शून्य प्रभाव पड़ता है।

बहु विकल्पीय प्रश्न

1. ग्रामीण विकास का अर्थ है:

- A. ग्रामीण लोगों को शिक्षा प्रदान करना B. ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना
C. कृषि का विकास D. जो ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता या जीवन स्तर को बढ़ाता है
2. ग्रामीण लोगों को दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता होती है _____।

- A. कृषि मशीनरी खरीदने के लिए B. खाद और बीज खरीदने के लिए
C. भूमि को बेहतर बनाने के लिए D. उपरोक्त सभी

3. ग्रामीण लोगों को अल्पावधि ऋण की आवश्यकता होती है।

- A. कारकों और मवेशियों को खरीदने के लिए B. पुराने डेबिट का भुगतान करने के लिए
C. उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए D. उपरोक्त सभी

4. ग्रामीण विपणन _____ से संबंधित है।

- A. विनियमित बाजार B. भंडारण
C. परिवहन कीटनाशकों का कम उपयोग D. उपरोक्त सभी

5. जैविक खेती _____ के कारण बहुत उपयोगी है।

- A. कीटनाशकों का कम उपयोग B. कीटनाशकों का कम उपयोग
C. मिट्टी की उर्वरता में सुधार D. उपरोक्त सभी

6. गाय के गोबर, मूत्र, फलों के अवशेष, जैविक पोषक तत्वों की गतिशीलता पर किसान _____ के तहत भरोसा करता है।

- ए. जैविक खेती बी. खेती
सी. भूमि जोत डी. संकटग्रस्त खेती

7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संस्थागत ऋण में योगदान करते हैं _____।

- A. 32% B. 22%
सी. 12% डी. 60%

उत्तर :

1.(ए) 2.(ए) 3.(सी) 4.(डी) 5.(डी) 6.(डी) 7.(सी)

अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न

1. दावा (ए): ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्र के पूर्ण और व्यापक विकास के लिए एक कार्य योजना है।

तर्क (आर): भारतीयों के जीवन स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि भारत की दो तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है।

एक। दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावा (ए) का सही स्पष्टीकरण है
 बी। दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
 सी। दावा (ए) सत्य है लेकिन कारण (आर) गलत है।
 डी। दावा (ए) गलत है लेकिन कारण (आर) सच है।
 उत्तर: (ए) दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण है

केस आधारित प्रश्न

1. निम्नलिखित समाचार रिपोर्ट पढ़ें:

अगले पांच वर्षों में पशुधन विकास पर केंद्र सरकार लगभग 9800 करोड़ रुपये खर्च करेगी और पशुपालन क्षेत्र में 55000 करोड़ का बाहरी निवेश का लाभ उठाया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह पशुपालन और डेयरी विभाग की कई योजनाओं को तीन मुख्य कार्यक्रमों में विलय करके किया जाएगा, जो स्वदेशी गायों और डेयरी विकास, पशुधन स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने विकास को बढ़ावा देने और इसमें लगे 10 करोड़ किसानों के लिए पशुपालन को अधिक लाभकारी बनाने के लिए मौजूदा योजनाओं के विभिन्न घटकों को संशोधित और पुनः व्यवस्थित करके विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी।

उपरोक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1) पशुधन उत्पादन अन्य खाद्य उत्पादन गतिविधियों को बाधित किए बिना परिवार के लिए ----- प्रदान करता है

(ए) आय में स्थिरता में वृद्धि

(बी) खाद्य सुरक्षा

(सी) परिवहन और ईंधन

(डी) ये सभी

उत्तर: (डी) ये सभी

2) केंद्रीय बैंक ----- (बागवानी/पशुपालन) क्षेत्र में पशुधन विकास पर निवेश करने का कार्य करता है

उत्तर: पशुपालन

3) भारत में पशुधन क्षेत्र की एक सीमा बताएं

उत्तर: पशुधन उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में काफी कम है

प्रश्न एवं उत्तर :

1. ग्रामीण विकास में ऋण के महत्व पर चर्चा करें।

उत्तर: कृषि में फसल की बुआई और आय की प्राप्ति के बीच लंबे समय के अंतराल के कारण किसानों को ऋण की सख्त आवश्यकता होती है। किसानों को बीज, उर्वरक, उपकरण और विवाह, मृत्यु, धार्मिक समारोहों आदि के अन्य पारिवारिक खर्चों पर प्रारंभिक निवेश को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए, ऋण महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, जो कृषि उत्पादन में योगदान देता है। कृषि उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए एक कुशल और प्रभावी ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली महत्वपूर्ण है।

2. टिकाऊ आजीविका के लिए कृषि विविधीकरण क्यों आवश्यक है?

उत्तर: टिकाऊ आजीविका के लिए कृषि विविधीकरण आवश्यक है क्योंकि:

(i): आजीविका के लिए विशेष रूप से खेती पर निर्भर रहने में अधिक जोखिम है;

(ii): ग्रामीण लोगों को पूरक लाभकारी रोजगार प्रदान करना और उन्हें उच्च स्तर की आय अर्जित करके गरीबी पर काबू पाने में सक्षम बनाना।

3. कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश भर में विभिन्न कृषि वस्तुओं का संयोजन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और वितरण शामिल है।

4. 'स्वर्णिम क्रांति' शब्द की व्याख्या करें।

उत्तर: 1991-2003 की अवधि को 'स्वर्ण क्रांति' के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस अवधि के दौरान, बागवानी में नियोजित निवेश अत्यधिक उत्पादक हो गया और यह क्षेत्र एक स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में उभरा।

5. स्वयं सहायता समूह (एसजीएच) क्यों स्थापित किए गए हैं?

उत्तर: स्वयं सहायता समूहों (एसजीएच) की स्थापना प्रत्येक सदस्य के लिए न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में बचत को बढ़ावा देने के लिए की गई है। एकत्रित धन से, जरूरतमंद सदस्यों को उचित ब्याज दरों पर छोटी किस्तों में चुकाने योग्य ऋण दिया जाता है।

प्रश्न (6 अंक)

6. ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण विकास के प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर: ग्रामीण विकास का तात्पर्य सतत और व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया से है, जो ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं को बेहतर बनाने का प्रयास करती है।

- (i) मानव संसाधन का विकास: साक्षरता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर उचित ध्यान देकर मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है।
- (ii) बुनियादी ढांचे का विकास: इसमें बिजली, सिंचाई, ऋण, विपणन और परिवहन सुविधाओं में सुधार शामिल है।
- (iii) भूमि सुधार:
इसमें शामिल है:
- (ए) भूमि सुधार में शोषण का उन्मूलन;
- (बी) 'जोतने वाले के लिए भूमि' के लक्ष्य को साकार करना;
- (सी) ग्रामीण गरीबों का भूमि आधार बढ़ाकर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार;
- (डी) कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि।
- (iv) गरीबी उन्मूलन: इसमें गरीबी उन्मूलन के लिए गंभीर कदम उठाना और कमजोर वर्गों की जीवन स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाना शामिल है।
- (v) रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रत्येक इलाके के उत्पादक संसाधनों का विकास।

7. ग्रामीण बाजारों के विकास में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या करें।
उत्तर: ग्रामीण बाजारों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:
- (i) विनियमित बाजार: किसानों को विक्रेताओं और दलालों के कदाचार से बचाने के उद्देश्य से विनियमित बाजारों का आयोजन किया गया है। इस नीति से किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ हुआ।
- (ii) बुनियादी सुविधाएं: सरकार का लक्ष्य सड़क, रेलवे, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयों जैसी भौतिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।
- (iii) सहकारी विपणन: सहकारी विपणन का उद्देश्य किसानों के उत्पादों के लिए उचित मूल्य प्राप्त करना है। इसके तहत किसानों द्वारा सामूहिक रूप से उत्पादन बेचने और बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी का लाभ उठाने के लिए विपणन समितियों का गठन किया जाता है।
- (iv) विभिन्न नीतिगत साधन: किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार ने निम्नलिखित नीतियां शुरू की हैं:
- (ए) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी): किसानों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, जिसे एक प्रस्ताव मूल्य माना जाता है, जिस पर सरकार किसानों से किसी भी मात्रा में अनाज खरीदने को तैयार रहती है। (बी) बफर स्टॉक का रखरखाव: भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए खरीद मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदता है। बफर स्टॉक आपूर्ति में नियमितता और कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करता है। (सी) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस): पीडीएस राशन की दुकानों और उचित मूल्य की दुकानों के एक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुएं कमजोर वर्ग को बाजार मूल्य से कम कीमत पर दी जाती हैं। समाज।

अध्याय 7

रोजगार: विकास, सूचनाकरण और अन्य मुद्दे

महत्वपूर्ण शर्तें:-

- आर्थिक गतिविधियाँ उन सभी गतिविधियों को संदर्भित करती हैं जो बदले में कुछ मौद्रिक पुरस्कार अर्जित करने के लिए की जाती हैं, उदाहरण के लिए, एक कक्षा में शिक्षक पढ़ाना।
- श्रमिक वह व्यक्ति है जो जीविकोपार्जन के लिए रोजगार में है।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात श्रमिकों की कुल संख्या को जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यह प्रतिशत रूप में है।
- स्व-रोजगार वे लोग हैं जो अपने स्वयं के व्यवसाय/पेशे में लगे हुए हैं।
- आकस्मिक-मजदूरी करने वाले श्रमिक, वे व्यक्ति जो आकस्मिक रूप से दूसरों के कृषि या गैर-कृषि उद्यमों में लगे हुए हैं और उन्हें कार्य अनुबंध के अनुसार (दैनिक/समय-समय पर) मजदूरी मिलती है।
- नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों को "वेतनभोगी कर्मचारी" भी कहा जाता है। वे श्रमिक जो नियमित आधार पर मजदूरी या वेतन पर दूसरों के उद्यमों (खेत या गैर-कृषि) में काम करते हैं।
- जब कोई अर्थव्यवस्था रोजगार के अवसर पैदा किए बिना अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, तो यह रोजगार रहित विकास है।
- कार्यबल का आकस्मिककरण उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कुल कार्यबल में आकस्मिक रूप से काम पर रखे गए श्रमिकों का प्रतिशत समय के साथ बढ़ने लगता है।
- जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार और इच्छुक होता है, लेकिन उसे करने के लिए काम नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगार कहा जाता है।
- प्रच्छन्न बेरोजगारी उस स्थिति को संदर्भित करती है जब किसी उत्पादन गतिविधि में वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, यानी इसमें अधिशेष लोग शामिल होते हैं।
- रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए कुछ अभियान कौशल भारत, मेक इन इंडिया और स्टार्ट-अप हैं।

बहुवैकल्पिक प्रश्न:

1. औपचारिक क्षेत्र में वे सभी उद्यम शामिल हैं जो रोजगार देते हैं

a) 10 से अधिक श्रमिक b) 10 श्रमिक c) दोनों (a) और (b) d) कोई नहीं (a) और (b)

2. स्व-रोजगार सृजन का लक्ष्य रखने वाले विशिष्ट प्रोग्रामर:

ए) ग्रामीण रोजगार सृजन प्रोग्रामर

बी) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

सी) मनरेगा

डी) इनमें से कोई नहीं

3. जो लोग अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके अपने जीते गए प्रतिष्ठान में काम करते हैं उन्हें _____ कहा जाता है

ए) किराए पर काम करने वाले कर्मचारी बी) कैजुअल कर्मचारी सी) नियमित कर्मचारी डी) स्व-रोजगार

3 अंक वाले प्रश्न

1. कैजुअल (आकस्मिक) मजदूरों को क्या अधिक असुरक्षित बनाता है?

उत्तर. आकस्मिक मजदूरों को नियमित आय नहीं मिलती; उनके पास सरकार से कोई सुरक्षा या विनियमन नहीं है और नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। उनके पास स्थायी श्रमिकों को मिलने वाले सामाजिक लाभों का भी अभाव है। इससे कैजुअल कर्मचारी असुरक्षित हो जाते हैं।

3. रोजगारहीन विकास कैसे होता है?

उत्तर. बेरोजगार विकास से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में समग्र तेजी से है जो रोजगार के अवसरों के अनुरूप विस्तार के साथ नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हम बिना रोजगार पैदा किये भी अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम हो गये हैं।

1991 में सुधारों के बाद सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर और रोजगार के बीच का अंतर विशेष रूप से बढ़ गया है।

5. "यद्यपि भारत में रोजगार की धीमी वृद्धि देखी गई है, फिर भी भारत में लोग बहुत लंबे समय तक पूरी तरह से बेरोजगार नहीं रह सकते हैं।" व्याख्या करना।

उत्तर. भारत में लोग बहुत लंबे समय तक बेरोजगार नहीं रह सकते क्योंकि उनकी खराब आर्थिक स्थिति उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। वे वह काम स्वीकार करते हैं जो कोई और नहीं करेगा, अशुद्ध, अस्वास्थ्यकर परिवेश में अप्रिय या खतरनाक काम।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए आप कौन सी गतिविधियाँ सुझाएँगे?

उत्तर. रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु सुझाव:

गैर-कृषि गतिविधियों जैसे पुनर्ग्रहण कार्य, मशीन की मरम्मत, ग्रामीण परिवहन सेवाएं, कुछ सार्वजनिक संपत्ति, निर्माण आदि के विकास से रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है।

गतिविधियों का विविधीकरण

ग्रामीण हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का विकास क्योंकि इनमें श्रम शक्ति को अवशोषित करने की बड़ी क्षमता है।

अनौपचारिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।

8. संक्षेप में बताएं:

(ए) प्रच्छन्न बेरोजगारी

(बी) मौसमी बेरोजगारी

उत्तर (ए) प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी भारतीय कृषि की विशिष्ट घटना है, जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग भूमि के एक टुकड़े पर काम कर रहे हैं। वे उत्पादक कार्य में योगदान नहीं देते हैं और जब वापस ले लिया जाता है, तो उत्पादन में गिरावट नहीं होती है।

(बी) मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ कृषि के मौसमी चरित्र के कारण लोगों को वर्ष के सभी महीनों में काम नहीं मिलता है। इस दौरान, वे आकस्मिक रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर जा सकते हैं।

10. भारत में रोजगार पर उपलब्ध आंकड़ों के स्रोत कौन से हैं?

उत्तर. बेरोजगारी पर डेटा के तीन स्रोत हैं:

i) भारत की जनगणना की रिपोर्ट

ii) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन - यह रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति की रिपोर्ट करता है

iii) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, यह रोजगार कार्यालयों के साथ पंजीकरण का डेटा प्रदान करता है।

6 अंक के प्रश्न

1. "भारत में रोजगार की प्रकृति बहुआयामी है।" विस्तार में बताना।

उत्तर. भारत में रोजगार के बारे में उपरोक्त कथन बिल्कुल सही है।

इसका मुख्य कारण रोजगार की अवधि में भिन्नता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें साल भर नौकरी मिलती है, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल कुछ महीनों के लिए ही नौकरी मिलती है और कुछ को साल में बहुत कम दिनों के लिए ही काम मिलता है।

हमारे पास ग्रामीण श्रमिक और शहरी श्रमिक हैं। भारत में अधिकांश श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए कार्यबल में उनका अनुपात उनके शहरी समकक्षों की तुलना में अधिक है। 2004-2005 में कुल 460 मिलियन कार्यबल में से लगभग 3/4 ग्रामीण श्रमिक थे।

एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि 70% श्रमिक पुरुष हैं और बाकी महिलाएँ हैं।

महिला श्रमिक ग्रामीण कार्यबल का 1/3 हिस्सा हैं और शहरी क्षेत्रों में वे शहरी कार्यबल का 1/5 वां हिस्सा हैं।

कई श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए काम के लिए उचित वेतन या भुगतान नहीं मिलता है यानी, उन्हें कम भुगतान किया जाता है और इस तरह उनके नियोक्ताओं द्वारा उनका शोषण किया जाता है।

कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को न तो नकद/वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता है, इसलिए उन्हें श्रमिकों के रूप में नहीं माना जाता है, खासकर अपने घरेलू काम करने में। लेकिन अर्थशास्त्रियों की राय है कि उनके साथ 'श्रमिक' जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

2. भारत में 'कार्यबल के अनौपचारिकीकरण' की अवधारणा पर संक्षेप में चर्चा करें।

उत्तर: कार्यबल का अनौपचारिकीकरण उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें औपचारिक क्षेत्र में कार्यबल के प्रतिशत में लगातार गिरावट हो रही है और साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यबल के प्रतिशत में वृद्धि हो रही है।

भारत में, कार्यबल का अनौपचारिकीकरण एक हालिया घटना है। वृद्धि और विकास से आम तौर पर औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती है और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में गिरावट आती है। हालाँकि, भारत में यह प्रवृत्ति उलट गई है। अनुमान से पता चलता है कि भारत में लगभग 93% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, जबकि केवल 7% औपचारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि अनौपचारिकता की सीमा में यह वृद्धि 1991 के सुधारों का परिणाम है जिसने भारत को "समाजवादी" अर्थव्यवस्था से "बाज़ार" अर्थव्यवस्था में बदल दिया।

अंत में, हम कह सकते हैं कि भारत में कार्यबल तेजी से अनौपचारिक होता जा रहा है।

3. बेरोजगारी क्या है? भारत में बेरोजगारी के कोई तीन परिणाम बताइये।

उत्तर. बेरोजगारी उन सभी लोगों की स्थिति को संदर्भित करती है, जो काम की कमी के कारण काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन या तो रोजगार कार्यालय, मध्यस्थों, दोस्तों या रिश्तेदारों के माध्यम से या भावी नियोक्ताओं को आवेदन करके काम की तलाश करते हैं या मौजूदा स्थिति के तहत काम के लिए अपनी इच्छा या उपलब्धता व्यक्त करते हैं। काम और पारिश्रमिक का.

भारत में बेरोजगारी के परिणाम हैं:

बेरोजगार अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। तो, इससे उनके जीवन स्तर में गिरावट आ सकती है।

बेरोजगारी समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है। बेरोजगारी में बर्बाद हुए अमूल्य समय की भरपाई कभी नहीं हो सकती।

अल्परोज़गारी बेरोज़गारी के गंभीर परिणामों में से एक है। नौकरियाँ खोने पर लोग ऐसी नौकरियाँ लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो उनके कौशल, अनुभव और योग्यता के अनुरूप नहीं होती हैं।

4. औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यबल भागीदारी दर में वृद्धि और बदलाव पर चर्चा करें।

उत्तर. जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, अधिक से अधिक श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र का श्रमिक बनना चाहिए और अनौपचारिक क्षेत्र में लगे श्रमिकों का अनुपात कम होना चाहिए। लेकिन भारत में स्थिति बेहद निराशाजनक है।

2011-12 से 2017-18 तक औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यबल में परिवर्तन (%)

सेक्टर्स	2011-12	2017-18
अनौपचारिक क्षेत्र	94	90.7
औपचारिक क्षेत्र	6	9.3
कुल	100	100

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि केवल 6% लोग औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं और शेष 94% लोग अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। लेकिन 2017-18 में 9.3% लोग औपचारिक क्षेत्र में और 90.7% लोग अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं।

इसका कारण रोजगार पैदा करने में औपचारिक क्षेत्र की विफलता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रयासों से भारत ने अनौपचारिक क्षेत्रों के उद्यमों और श्रमिकों पर ध्यान देना शुरू किया। भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के आधुनिकीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रावधान की शुरुआत की है।

5. रोजगार की अवधारणा को समझाइये। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से।

उत्तर. 'रोजगार' की अवधारणा को विभिन्न कोणों से देखा जा सकता है।

स्व-रोजगार उन श्रमिकों से संबंधित एक घटना है जो अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने उद्यम का मालिक होते हैं और उसका संचालन करते हैं।

आकस्मिक वेतन रोजगार एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जहां श्रमिक आकस्मिक रूप से किसी और के खेत या परियोजना में लगे होते हैं, दैनिक वेतन भोगी।

नियमित रोजगार एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जहां श्रमिकों को किसी व्यक्ति या उद्यम (सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र) द्वारा नियुक्त किया जाता है और उन्हें नियमित आधार पर उनका वेतन/वेतन दिया जाता है। उदाहरण के लिए, लोग किसी उद्यम/स्कूल आदि में स्थायी आधार पर काम कर रहे हैं।

6. बेरोजगारी को परिभाषित करें। बेरोजगारी के कम से कम तीन रूपों की व्याख्या करें। बेरोजगारी के आर्थिक परिणामों की भी व्याख्या करें।

उत्तर. एनएसएसओ बेरोजगारी को उस स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जिसमें वे सभी लोग, जो काम की कमी के कारण काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, दोस्तों या रिश्तेदारों के माध्यम से या संभावित नियोजकों को आवेदन करके या काम के लिए अपनी इच्छा या उपलब्धता व्यक्त करके काम की तलाश करते हैं। काम और पारिश्रमिक की मौजूदा स्थिति के तहत। बेरोजगारी के रूप:

खुली बेरोजगारी से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें यद्यपि श्रमिक काम करने को तैयार है और उसके पास काम करने की आवश्यक क्षमता भी है फिर भी उसे काम नहीं मिलता है। वह पूरे समय बेरोजगार रहता है और उसे आकस्मिक या पूर्णकालिक कोई भी काम नहीं मिल पाता है।

प्रच्छन्न बेरोजगारी भारतीय कृषि की विशिष्ट विशेषता है जहाँ खेत के एक टुकड़े पर आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं। वे उत्पादक कार्यों में योगदान नहीं देते हैं और जब वापस ले लिए जाते हैं, तो उत्पादन में गिरावट नहीं होती है।

मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है जहां कृषि के मौसमी चरित्र के कारण लोगों को वर्ष के सभी महीनों में काम नहीं मिलता है। इस दौरान, वे आकस्मिक रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर जा सकते हैं।

बेरोजगारी के आर्थिक परिणाम:

बेरोजगार व्यक्ति को कड़ी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। वे अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हैं। इससे उनके जीवन स्तर में गिरावट आ सकती है। बेरोजगारी लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है। बेरोजगारी में बर्बाद हुए समय की भरपाई कभी नहीं की जा सकती।

अल्परोजगारी बेरोजगारी के गंभीर परिणामों में से एक है। नौकरी छूटने पर लोग ऐसी नौकरियां करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो उनके कौशल, अनुभव और शैक्षिक योग्यता के अनुरूप नहीं होती हैं।

7. भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण बताइये।

उत्तर. भारत में बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण हैं:

अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक प्रमुख कारण रही है। वास्तव में बेरोजगारों की संख्या वास्तव में घटने के बजाय बढ़ी है।

आर्थिक विकास की दर अनुमान से काफी धीमी रही है, इसका मुख्य कारण दोषपूर्ण योजना है।

वित्तीय संसाधनों की कमी रोजगार सृजन में बड़ी बाधा रही है। इसके अलावा कई वर्षों से सरकार के बढ़ते नियंत्रण से इसमें और वृद्धि हुई है।

8. हमारी अर्थव्यवस्था में प्रचलित किन्हीं तीन विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी की व्याख्या करें।

उत्तर. हमारी अर्थव्यवस्था में प्रचलित बेरोजगारी के मुख्य प्रकार हैं:

खुली बेरोजगारी उस घटना को संदर्भित करती है जब लोग नौकरियों की तलाश में रोजगार कार्यालयों, कार्यालयों, कारखानों, स्कूलों आदि में जाते हैं और अपना बायोडाटा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी मांगने नहीं जाते बल्कि काम नहीं होने पर घर पर ही रहते हैं।

ग्रामीण भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी आम बेरोजगारी है। अब इस अवधारणा को एक उदाहरण की सहायता से समझाते हैं। मान लीजिए कि 5 एकड़ के खेत में 2 मजदूर और किसान के 4 बेटे कार्यरत हैं। लेकिन असल जरूरत तो 2 भाड़े के मजदूरों और 2 किसान बेटों की ही है। इस प्रकार दिए गए किसान के शेष 2 बेटे वास्तव में उत्पादक रूप से योगदान नहीं देते हैं इसलिए खेत पर उनकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वे प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं।

मौसमी बेरोजगारी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है क्योंकि कृषि कार्य 'मौसमी' होता है।

जब खेतों पर करने के लिए कोई काम नहीं होता यानी ऑफ-सीज़न होता है, तो ग्रामीण लोग नौकरियों की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। यह भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी का सबसे सामान्य रूप है।

केस-आधारित प्रश्न

9. निम्नलिखित केस अध्ययन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें।

भारत में कार्यबल की संरचना में बदलाव आया है। नई उभरती नौकरियाँ अधिकतर सेवा क्षेत्र में पाई जाती हैं। सेवा क्षेत्र का विस्तार और उच्च प्रौद्योगिकी का आगमन अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ कुशल छोटे पैमाने और व्यक्तिगत उद्यमों या विशेषज्ञ श्रमिकों के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी अस्तित्व की अनुमति देता है। 'आउटसोर्सिंग' कार्य एक आम बात बनती जा रही है।

'कार्यबल' शब्द को परिभाषित करें।

उत्तर. कार्यबल वास्तव में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या को संदर्भित करता है और इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया जाता है जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन कोई काम पाने में सक्षम नहीं हैं।

कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से आगे है और क्यों?

उत्तर. तृतीयक या सेवा क्षेत्र क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोग अपने जीवन की गुणवत्ता के प्रति तेजी से जागरूक हो रहे हैं, अपनी आय का बड़ा हिस्सा विभिन्न सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं।

बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए श्रम शक्ति से क्या घटाना होगा?

उत्तर. कार्यबल.

10. निम्नलिखित केस स्टडी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें।

श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) देश की आबादी के उस अनुपात का माप है जो श्रम बाजार में सक्रिय रूप से कार्यरत है, या तो काम करके या काम की तलाश में। यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में संलग्न होने के लिए उपलब्ध श्रम की आपूर्ति के आकार का संकेत प्रदान करता है। श्रम बल की औसत वार्षिक वृद्धि और रोजगार वृद्धि के बीच का अंतर बेरोजगारी वाले लोगों के मौजूदा स्टॉक में वृद्धि/कमी की ओर संकेत देता है। कार्य भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) देश की श्रम शक्ति के अनुपात का एक माप है जो काम में लगी हुई है। यह अर्थव्यवस्था की रोजगार पैदा करने की क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

श्रम बल भागीदारी दर और कार्य भागीदारी दर के बीच मुख्य अंतर क्या है?

उत्तर. श्रम बल भागीदारी दर उन लोगों के लिए है जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं, जबकि कार्य भागीदारी दर उन लोगों के लिए नहीं है जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं।

भागीदारी दर की गणना करने का सूत्र बताएं?

उत्तर. भागीदारी दर = $(\text{कुल कार्यबल}) / (\text{कुल जनसंख्या}) \times 100$

बताएं कि क्या दिया गया कथन सत्य/असत्य है।

"जो लोग मौजूदा मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक नहीं हैं उन्हें बेरोजगार माना जाता है।"

उत्तर-असत्य .

पर्यावरण और सतत विकास

अवधारणा

पर्यावरण में जल, वायु और भूमि और जल, वायु, भूमि और मनुष्य और अन्य प्राणियों के बीच मौजूद अंतरसंबंध, सूक्ष्मजीव और गुण शामिल हैं।

पर्यावरण का महत्व

- पर्यावरण उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करता है।
- पर्यावरण जीवन को कायम रखता है।
- पर्यावरण अपशिष्ट को आत्मसात करता है।
- पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है

पर्यावरण संकट के कारण

- इसकी वहन क्षमता से तात्पर्य उस दर के बीच संतुलन की स्थिति से है जिस दर पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है और जिस दर पर इन संसाधनों का पुनरुद्धार किया जाता है।
- पर्यावरण की अवशोषण क्षमता यह अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग गतिविधियों के कारण होने वाले अपशिष्ट को अवशोषित करने की पर्यावरण की क्षमता को संदर्भित करती है।
- पर्यावरणीय संकट तब उत्पन्न होता है जब प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण की वहन क्षमता को चुनौती मिलती है या जब अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता से अधिक हो जाता है।

पर्यावरण संकट के कारण

- जनसंख्या विस्फोट

- व्यापक गरीबी
- बढ़ता शहरीकरण.
- कीटनाशकों, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता उपयोग।
- तीव्र औद्योगीकरण.
- परिवहन वाहनों की बहुलता.
- नागरिक मानदंडों की अवहेलना.

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के प्रमुख कारण हैं: (i) कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद का जलना (जिससे CO_2 , मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होता है), (ii) वनों की कटाई से वातावरण में CO_2 की मात्रा में वृद्धि होती है, (iii) पशु उत्पादन और पशु अपशिष्ट में वृद्धि।

क्योटो प्रोटोकॉल पर 1997 में जापान के क्योटो में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती पर केंद्रित है।

ओजोन रिक्तीकरण

इसका तात्पर्य समताप मंडल में ओजोन (एक सुरक्षात्मक परत) में कमी से है। ऐसा क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिकों की अत्यधिक उपस्थिति के कारण होता है। जैसे-जैसे ओजोन घटता है, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पराबैंगनी विकिरण पहुंचता है जो जीवित जीवों के लिए खतरनाक है।

भारत में पर्यावरण की स्थिति

भारत निश्चित रूप से पर्यावरण संकट से जूझ रहा है।

- प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जो इसके पुनर्जनन की दर से भी अधिक हो रहा है।
- उत्पादन और गर्भाधान अपशिष्ट पर्यावरण की अवलोकन क्षमता से परे उत्पन्न हो रहे हैं
- वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण चिंताजनक सीमा तक बढ़ रहा है।
- भारत में पर्यावरण क्षरण की प्रमुख चिंताएँ
 - भूमि का निम्नीकरण,
 - वायु प्रदूषण (विशेषकर शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण के रूप में),
 - जल प्रदूषण और ताजे पानी का प्रबंधन,
 - जैव विविधता की हानि, और
 - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

सतत विकास

ब्रंटलैंड आयोग (1987 में) के अनुसार, "सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को कम/कम किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है"।

वृद्धि और विकास की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया ने पर्यावरणीय क्षरण और पर्यावरण प्रदूषण को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है।

सतत विकास के लिए रणनीतियाँ

सतत विकास का मतलब आर्थिक विकास की मौजूदा गति पर रोक लगाना नहीं है।

इसका मतलब केवल संसाधनों का विवेकपूर्ण या इष्टतम उपयोग इस तरह से है कि विकास की गति भावी पीढ़ी की बढ़ने और समृद्ध होने की क्षमता को चुनौती दिए बिना बनी रहे।

ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर निर्भरता

ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी, गोबर गैस: भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को सब्सिडी वाली एलपीजी उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उज्ज्वला योजना शुरू की है। इसके अलावा, गोबर गैस संयंत्र आसान ऋण और सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों में सी.एन.जी

पवन ऊर्जा: पवन ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना किया जा सकता है।

फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा: सौर ऊर्जा और इसका बिजली में रूपांतरण न केवल आर्थिक विकास की समस्या का बल्कि सतत विकास की समस्या का भी एक प्रभावी उत्तर है।

मिनी पनबिजली संयंत्र: मिनी पनबिजली संयंत्र विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में बिजली पैदा करने का एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है।

पारंपरिक ज्ञान और प्रथाएँ

पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ

भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली

बायोक्वॉलिटी: त्वचा योजना के एक भाग के रूप में जैवउर्वरकों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

बायोपेस्ट नियंत्रण: नीम और उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कीटों के हमले को कम करने के लिए मिश्रित फसल और फसल चक्र को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोइथेन (मिथाइल क्लोरोफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है), और ब्रोमीन यौगिकों जैसे हेलोन्स जिन्हें ओजोन घटने वाले पदार्थ कहा जाता है, जैसे रसायनों के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करता है।

महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम

1. 1974: सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की स्थापना की।
2. 1986: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
3. 1992: भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये
4. 2016: प्रधानमंत्री उज्वला योजना (PMUY) की शुरुआत की गई

बहुवैकल्पिक प्रश्न

1. उज्वला योजना निम्नलिखित के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है:

- ए) एलपीजी बी) सीएनजी सी) गोबर गैस डी) सौर ऊर्जा
उत्तर: (ए)

2. मिनी-पनबिजली पौधे पर्यावरण के लिए अच्छे हैं क्योंकि:

- वे केवल स्थानीय क्षेत्रों के लिए बिजली पैदा करते हैं
- भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव न करें
- वे बारहमासी जलधाराओं पर निर्भर रहते हैं
- दोनों (ए) और (सी)

उत्तर: (ए)

3. जैव खाद पर केन्द्रित योजना है:

- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन
- जैविक खेती पर राष्ट्रीय मिशन
- जैव खाद पर राष्ट्रीय मिशन
- पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर राष्ट्रीय मिशन

उत्तर: (ए)

4. निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास की रणनीति है

(1)

- शहरी क्षेत्रों में सी.एन.जी
- ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता
- आउटपुट कुशल प्रौद्योगिकी
- दोनों (ए) और (बी)

उत्तर: (डी)

5. सतत विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

- सतत विकास का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतें पूरी हों।
- यदि समग्र पूंजीगत संपत्ति का स्टॉक समय के साथ गिरता है तो एक विकास पथ टिकाऊ होता है
- सतत विकास शब्द की उत्पत्ति iucn 1980 विश्व आयोग रणनीति रिपोर्ट में हुई है
- सतत विकास वह विकास है जो इन जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की वृद्धि सुनिश्चित करता है

उत्तर: (बी)

6. वहन क्षमता का तात्पर्य है...

- संसाधन निष्कर्षण संसाधन पुनर्जनन की दर से नीचे रहना चाहिए
- संसाधन निष्कर्षण संसाधन पुनर्जनन की दर से ऊपर रहना चाहिए
- अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए

iv) कचरे का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता से अधिक होना चाहिए

a) (i) और (iv)

b) (i) और (iii)

c) (ii) और (iii)

d) (ii) और (iv)

उत्तर: (बी)

7. अभिकथन तर्क प्रश्न:

निम्नलिखित कथन हत्यारा (ए) और कारण (आर) पढ़ें। नीचे दिए गए सही विकल्पों में से एक चुनें:

विकल्प:

(ए) कथन (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण है।

(बी) कथन (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(सी) कथन (ए) सच है लेकिन कारण (आर) गलत है।

(डी) कथन (ए) गलत है लेकिन कारण (आर) सच है।

(i) कथन (ए): भारत दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र के केवल 2.5 प्रतिशत पर दुनिया की लगभग 17 प्रतिशत मानव और 20 प्रतिशत पशुधन आबादी का समर्थन करता है।

कारण (आर): भूमि के प्रतिस्पर्धी और विविध उपयोग के साथ-साथ जनसंख्या और पशुधन का उच्च घनत्व, देश के सीमित और संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डालता है। (1)

(ii) दावा कथन (ए): दुनिया भर में लोग पर्यावरणीय चुनौतियों की एक श्रृंखला का सामना कर रहे हैं और यह आशंका है कि यह भविष्य की पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कारण (आर): हाल के दिनों में, आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और अत्यधिक कचरे का उत्पादन हुआ है। (1)

8. 'सतत विकास' को परिभाषित करें।

9. 'पर्यावरण की वहन क्षमता' को परिभाषित करें।

10. 'पर्यावरण की अवशोषण क्षमता' को परिभाषित करें।

11. 'जैव-सम्मिश्रण' को परिभाषित करें।

12. हाल ही में भारतीय पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं से दूर हो गए हैं और पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। बताएं कि पारंपरिक प्रथाओं को अपनाकर सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में कैसे सहायक हो सकता है?

13. सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड रिपोर्ट (2021) के अनुसार भारत 165 देशों में से 120वें स्थान पर है। सतत विकास के मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कोई चार उपाय सुझाएं।

14. चित्र को विस्तृत करें:



विकास अनुभव - एक तुलनात्मक अध्ययन

(1) जीडीपी ग्रोथ:- चीन की ग्रोथ स्टोरी:-

I. 2017 में चीन में जीडीपी 12.40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था

- II. चीन को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का गौरव प्राप्त हुआ
- III. चीन ने 1980 के दशक की शुरुआत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में एक सफलता हासिल की, यह 4% प्रति वर्ष से बढ़कर 10% प्रति वर्ष हो गई, जिसके कारण :- (ए) एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से नियंत्रित बाजार अर्थव्यवस्था में बदलाव (बी) निर्यात-संबंधित पर ध्यान केंद्रित करना घरेलू उत्पादन (सी) ग्रेट लीप फॉरवर्ड (जीएलएफ) अभियान (डी) सस्ते श्रम बल की उपलब्धता।
- IV. एफडीआई में क्रांति उछाल निम्नलिखित के माध्यम से हासिल किया गया: (ए) चीन ने एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) की स्थापना की (बी) 100% एफडीआई (सी) जीएलएफ के माध्यम से घरेलू निवेश में वृद्धि (व) वैश्विक बाजार में सबसे बड़ा निर्यातक।

चीन में हाल ही में जीडीपी वृद्धि धीमी होने के कारण:-

- I. वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी
- II. चीन की घरेलू मांग में वृद्धि धीमी
- III. समय के साथ भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध बढ़े हैं
- IV. चीनी सरकार पर्यावरण क्षरण की समस्या से जूझ रही है।

भारत की विकास गाथा:-

- (i) 2017 में भारत की जीडीपी 2.43 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था
- (ii) भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का गौरव प्राप्त हुआ
- (iii) **उदारीकरण** की ओर एक परिवर्तन (सी) पर अधिक निर्भरता आयात प्रतिस्थापन के बजाय निर्यात प्रोत्साहन (डी) घरेलू निवेश के बजाय एफडीआई पर अधिक निर्भरता
- (iv) 1991-2017 की अवधि में, भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बढ़कर लगभग 7% प्रति वर्ष हो गई। हाल ही में भारत में जीडीपी वृद्धि धीमी होने के कारण: (ए) मुद्रास्फीति की उच्च दर (बी) भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध समय के साथ बढ़े हैं नीति (सी) राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकार की निष्क्रियता (डी) सूखा भारतीय अर्थव्यवस्था की खराब क्रेडिट रेटिंग के कारण एफडीआई।

पाकिस्तान:

पाकिस्तान: पाकिस्तान ने विभिन्न आर्थिक नीतियां अपनाईं और भारत के साथ ये कई समानताएं हैं। पाकिस्तान सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सह-अस्तित्व के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का भी पालन करता है।

पाकिस्तान की विकास गाथा:-

- I. 1950 और 1960 के दशक के अंत में, पाकिस्तान ने विभिन्न प्रकार के विनियमित नीति ढांचे (आयात प्रतिस्थापन-आधारित औद्योगीकरण के लिए) की शुरुआत की।
- II. 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तु उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ।
- III. इसके बाद पाकिस्तान ने 1970 और 1980 के दशक के अंत में अपनी नीति दिशा बदल दी, जब प्रमुख जोर क्षेत्र अराष्ट्रीयकरण और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना था।
- IV. 1988 में देश में सुधारों की शुरुआत हुई।
- V. 2017 में पाकिस्तान की जीडीपी 27.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था
- VI. पाकिस्तान ने 80 के दशक के मध्य में जीडीपी वृद्धि में सफलता हासिल की, यह एफडीआई पर ध्यान केंद्रित करने वाले आर्थिक सुधारों का परिणाम था।

पाकिस्तान में आर्थिक परिदृश्य निराशाजनक होने के कारण:-

- (ए) पाकिस्तान आतंक के युद्ध की चपेट में आ गया है
(बी) भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता अन्य कारक हैं।

निष्कर्ष:-

- (i) जीडीपी के मामले में चीन ने भारत और पाकिस्तान दोनों को पीछे छोड़ दिया है
- (ii) भारत ने पाकिस्तान से बेहतर प्रदर्शन किया है
- (iii) चीन की सापेक्ष सफलता का श्रेय चीन में राजनीतिक स्थिरता को दिया जाता है।

(2) जनसांख्यिकी संकेतक:-

अगर हम वैश्विक आबादी पर नजर डालें तो इस दुनिया में रहने वाले हर छह लोगों में से एक भारतीय और दूसरा चीनी है। हम भारत, चीन और पाकिस्तान के कुछ जनसांख्यिकीय संकेतकों की तुलना करेंगे।

(i) जनसंख्या का आकार:- (ए) जनसंख्या वृद्धि पाकिस्तान में सबसे अधिक है, इसके बाद भारत और चीन का स्थान है। (बी) भारत और चीन मिलकर दुनिया की 38% आबादी का निवास स्थान हैं (सी) लगभग 1371 मिलियन लोगों के साथ चीन (2015 में) दुनिया की लगभग 20% आबादी का निवास स्थान है (डी) भारत 89 लगभग 1311 मिलियन लोग (2015 में) दुनिया की लगभग 18% आबादी का निवास स्थान है (ई) विद्वान 1970 के दशक के अंत में चीन में शुरू किए गए एक-बच्चे के मानदंड को कम जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण बताते हैं।

(ii) जनसंख्या की वृद्धि दर:- 2015 में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर - भारत 1.2, पाकिस्तान 2.1 और चीन 0.5%, भारत में जनसंख्या का आकार जल्द ही चीन से अधिक हो सकता है। (iii) जनसंख्या का घनत्व:- चीन में 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पाकिस्तान में 245 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत में 441 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने का अनुमान है। (iv) लिंग अनुपात:- प्रति हजार 929 होने का अनुमान है भारत में 941, चीन में 941 और पाकिस्तान में 947 प्रति हजार है। (v) शहरीकरण:- भारत में, 33% आबादी शहरीकृत है, जबकि पाकिस्तान में 39% और चीन में 56% है।

(3) उत्पादन का क्षेत्रीय वितरण (सकल घरेलू उत्पाद और क्षेत्र):

इन देशों में उत्पादन और रोजगार के क्षेत्रीय वितरण का अवलोकन:

1. भारत और पाकिस्तान दोनों में, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान क्रमशः 17 और 25 प्रतिशत था, लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वाले कार्यबल का अनुपात भारत में अधिक है। में पाकिस्तान में लगभग 42 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि भारत में यह 43 प्रतिशत है।
2. उत्पादन और रोजगार की क्षेत्रीय हिस्सेदारी से यह भी पता चलता है कि तीनों अर्थव्यवस्थाओं में, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कार्यबल का अनुपात कम है लेकिन उत्पादन के मामले में उनका योगदान अधिक है।
3. चीन में, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में क्रमशः 43 और 48 प्रतिशत का सबसे अधिक योगदान करते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान में, यह सेवा क्षेत्र है जो सकल घरेलू उत्पाद का 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है।
4. सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान भारत में 30 प्रतिशत और पाकिस्तान में 21 प्रतिशत है।

मानव विकास के सूचक:-

मानव विकास के महत्वपूर्ण संकेतक इस प्रकार हैं: (ए) जीवन प्रत्याशा - जितना अधिक उतना बेहतर (बी) वयस्क साक्षरता दर - जितना अधिक उतना बेहतर (सी) गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत - जितना कम उतना बेहतर (डी) शिशु मृत्यु दर - जितना कम उतना बेहतर (ई) मातृ मृत्यु दर - जितना कम उतना बेहतर (एफ) बेहतर स्वच्छता तक पहुंच रखने वाली आबादी का प्रतिशत जितना अधिक उतना बेहतर (जी) बेहतर जल स्रोतों तक पहुंच रखने वाली आबादी का प्रतिशत - जितना अधिक उतना बेहतर (जे) प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद - जितना अधिक उतना बेहतर . संकेतकों के आधार पर, एक समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है, जिसे मानव विकास सूचकांक कहा जाता है - एचडीआई का उच्च मूल्य किसी देश के लिए उच्च रैंक और उच्च स्तर की वृद्धि और विकास की ओर इशारा करता है।

चीन भारत और पाकिस्तान से आगे निकल रहा है. यह कई संकेतकों के लिए सच है -

1. आय संकेतक जैसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, या गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का अनुपात या स्वास्थ्य संकेतक जैसे मृत्यु दर, स्वच्छता तक पहुंच, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा या कुपोषण।
2. पाकिस्तान गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के अनुपात को कम करने और स्वच्छता में अपने प्रदर्शन में भारत से आगे है।
3. मातृ मृत्यु दर: चीन में प्रति एक लाख जन्मों पर केवल 27 महिलाओं की मृत्यु होती है जबकि भारत और पाकिस्तान में क्रमशः लगभग 174 और 178 महिलाओं की मृत्यु होती है।
4. प्रतिदिन 3.20 डॉलर की अंतरराष्ट्रीय गरीबी दर से नीचे लोगों का अनुपात, तीनों देशों में भारत में गरीबों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है।
5. आश्चर्यजनक रूप से तीनों देशों ने अपनी अधिकांश आबादी के लिए बेहतर पेयजल स्रोत उपलब्ध कराने की रिपोर्ट दी है।
6. चीन की उच्च एचडीआई रैंकिंग ने भारत और पाकिस्तान की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। चीन में एचडीआई रैंक 2016-17 86 रैंक थी, भारत - 130 रैंक थी और दुनिया के 189 देशों में से पाकिस्तान 150 रैंक था।

विकास रणनीतियाँ - एक मूल्यांकन

भारत और पाकिस्तान की आम सफलता की कहानी:-

- (i) भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक करने में सफल रहे हैं
- (ii) खाद्य उत्पादन ने जनसंख्या में वृद्धि के साथ सफलतापूर्वक तालमेल बनाए रखा है

- (iii) खाद्य आत्मनिर्भरता के साथ-साथ पोषण संबंधी स्थिति में भी सुधार हुआ है
- (iv) एक सुविकसित आधुनिक क्षेत्र
- (v) पूर्ण गरीबी कम हो गई है।

भारत और पाकिस्तान की आम विफलताओं की कहानी:-

- (i) अपेक्षाकृत अंतर्मुखी आर्थिक नीतियां
- (ii) राजनेताओं और नौकरशाहों की मानसिकता में कोई प्रगतिशील परिवर्तन नहीं दिखा है
- (iii) राजकोषीय प्रबंधन बेहद निराशाजनक है
- (iv) कर राजस्व का बड़ा हिस्सा रक्षा व्यय पर खर्च किया जाता है
- (v) अपर्याप्त शहरी सेवा (पानी, बिजली और परिवहन)
- (vi) एक ओर नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन के बीच व्यापक अंतराल।

वे क्षेत्र जहां भारत को पाकिस्तान पर बढ़त हासिल है:-

- I. कुशल जनशक्ति, अनुसंधान और विकास संस्थानों के क्षेत्र में भारत पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में है
- II. मानव पूंजी निर्माण (iii) भारत ने सॉफ्टवेयर के निर्यात में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है
- III. शिक्षा में निवेश का भी भारत का रिकॉर्ड बेहतर है
- IV. जनसंख्या वृद्धि दर (प्रजनन दर) में तेजी से गिरावट के कारण
- V. स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सामान्य तौर पर भारत पाकिस्तान से बेहतर है।

वे क्षेत्र जहां पाकिस्तान को भारत पर बढ़त हासिल है:-

- I. पाकिस्तान ने कृषि से उद्योग की ओर कार्यबल के प्रवास के संबंध में बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं
- II. पाकिस्तान की विकास रणनीति पाकिस्तान से बेहतर है
- III. (iii) भारत की तुलना में पाकिस्तान में बाहरी व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है
- IV. (iv) पाकिस्तान ने बेहतर जल संसाधनों तक पहुंच के संबंध में बेहतर परिणाम हासिल किए हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बीच तुलना:-

- (i) दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मिश्रित है
- (ii) (ii) 1988 में पाकिस्तान में आर्थिक सुधारों पर रोक लगा दी गई और भारत ने 1991 से सुधार शुरू किए
- (iii) दूरसंचार, सूचना, प्रौद्योगिकी, मानव पूंजी निर्माण के क्षेत्र में भारत पाकिस्तान से आगे है
- (iv) शहरीकरण और स्वच्छता सुविधाओं के क्षेत्र में पाकिस्तान भारत से आगे है।

भारत पर चीन की बढ़त:-

हम जानते हैं कि चीन में सुधारों की शुरुआत 1978 में हुई थी।

- (i) चीनी सुधार प्रक्रिया 80 के दशक के दौरान अधिक व्यापक रूप से शुरू हुई
- (ii) अर्थव्यवस्था का वैश्विक प्रदर्शन भारत की तुलना में चीन में कहीं अधिक व्यापक है, इस प्रकार: - (ए) चीन खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देने में उदार था (बी) चीन ने निवेशकों को 100% इक्विटी निवेश की अनुमति दी (सी) एसईजेड की स्थापना
- (iv) चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है (v) चीनी कृषि खेती की एक सामुदायिक प्रणाली (सामूहिक खेती) है।

निष्कर्ष:-

1970 के दशक के अंत तक भारत, चीन और पाकिस्तान, ये सभी निम्न विकास के समान स्तर को बनाए हुए थे।

भारत :

- (i) लोकतांत्रिक संस्थाओं वाले भारत का प्रदर्शन सामान्य रहा, लेकिन इसके अधिकांश लोग अभी भी कृषि पर निर्भर हैं।
- (ii) देश के कई हिस्सों में बुनियादी ढांचे की कमी है।
- (iii) इसे अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अपनी एक-चौथाई से अधिक आबादी के जीवन स्तर को ऊपर उठाना बाकी है।

पाकिस्तान:-

विद्वानों का मानना है कि राजनीतिक अस्थिरता, प्रेषण पर अत्यधिक निर्भरता आदि विदेशी सहायता के साथ-साथ कृषि क्षेत्र का अस्थिर प्रदर्शन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की मंदी का कारण है।

चीन:-

- (i) चीन ने 'अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक अवसर पैदा करने' के लिए बाजार तंत्र का उपयोग किया है।
(ii) भूमि का सामूहिक स्वामित्व बरकरार रखकर और व्यक्तियों को भूमि पर खेती करने की अनुमति देकर, चीन ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है।
(iii) सामाजिक सहायता प्रदान करने में सार्वजनिक हस्तक्षेप सुधारों से पहले भी बुनियादी ढांचे ने चीन में मानव विकास संकेतकों में सकारात्मक परिणाम लाए हैं।

एमसीक्यू (बहु विकल्पीय प्रश्न)

प्रश्न 1: निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

- (i) पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना
(ii) पाकिस्तान का निर्माण
(iii) भारत की पहली पंचवर्षीय योजना (iv) चीन की पहली पंचवर्षीय योजना विकल्प:

(ए) (i), (iv), (ii), (iii)

(बी) (iii), (ii), (i), (iv)

(सी) (ii), (i), (iii), (iv)

(डी) (iv), (iii), (ii), (i)

उत्तर: (सी) (ii), (i), (iii), (iv)

Q2. 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' का मुख्य उद्देश्य चीन में (प्राथमिक/माध्यमिक/तृतीयक) क्षेत्र में तेजी से वृद्धि सुनिश्चित करना था। (सही विकल्प का चयन करें)

उत्तर: द्वितीयक

Q3- माओ ने चीन/पाकिस्तान में वर्ष ___ में 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' की शुरुआत की

(ए) 1951 (बी) 1955 (सी) 1958 (डी) 1962

उत्तर: 1958, चीन

Q4. वह प्रणाली जिसमें लोग सामूहिक रूप से चीन में भूमि पर खेती करते हैं, कहलाती है।

उत्तर: कम्यून प्रणाली

Q5. निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है?

(ए) भारत (बी) चीन (सी) पाकिस्तान (डी) ये सभी:

उत्तर: (सी) पाकिस्तान

Q6. चीन ने किस वर्ष अपनी पहली पंचवर्षीय योजना की घोषणा की?

(A) 1950 (बी) 1951 (सी) 1953 (डी) 1954

उत्तर : 1953

Q7. भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की।

(A) 1990 (बी) 1991 (सी) 1992 (डी) 1995

उत्तर: 1991

Q8. चीन की महान छलांग इसी वर्ष थी।

(A) 1953 (बी) 1955 (सी) 1958 (डी) 1990

उत्तर: 1958

Q9. कम्यून प्रणाली की विशेषता है (ए) भारत (बी) चीन (सी) पाकिस्तान (डी) उपरोक्त सभी

उत्तर: चीन

Q10. में सुधार 1978 में शुरू किये गये थे।

(A) चीन, (बी) पाकिस्तान, (सी) भारत (डी) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: चीन,

लघु उत्तरीय प्रश्न

Q1. "भारत, चीन और पाकिस्तान ने विभिन्न परिणामों के साथ सात दशकों से अधिक विकास पथ की यात्रा की है।" दिए गए कथन को वैध तर्कों के साथ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- (i) 1970 के दशक के अंत तक, तीनों देश निम्न विकास के समान स्तर को बनाए हुए थे।

(ii) पिछले तीन दशकों में, तीनों देशों ने विकास के विभिन्न स्तरों को आगे बढ़ाया है

पिछले कुछ वर्षों में भारत का प्रदर्शन सामान्य रहा है। यहां के अधिकांश लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। बुनियादी ढांचे की कमी है और इसकी एक चौथाई से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। राजनीतिक अस्थिरता, प्रेषण और विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता के साथ-साथ कृषि के अस्थिर प्रदर्शन के कारण पाकिस्तान का प्रदर्शन कम रहा। चीन ने गरीबी उन्मूलन पर जोर देने के साथ अर्थव्यवस्था में विकास दर बढ़ाने में सफलता के लिए बाजार प्रणाली का उपयोग किया है।

Q2. भारत और पाकिस्तान ने अपने-अपने विकास पथों के लिए कौन सी समान विकासात्मक रणनीतियों का पालन किया है?

उत्तर: भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक समान विकासात्मक रणनीति अपनाई है। विकासात्मक रणनीतियों के बीच मुख्य समानताओं को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:

- (i) भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1947 में अपनी आज़ादी के तुरंत बाद आर्थिक योजना पर आधारित अपने विकास कार्यक्रम शुरू कर दिए थे।
- (ii) दोनों देश वृद्धि और विकास की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर थे।
- (iii) दोनों ने मिश्रित आर्थिक संरचना का मार्ग अपनाया है जिसमें राज्य और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी शामिल है।
- (iv) दोनों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए एक ही समय में आर्थिक सुधार पेश किए।

Q3. चीन, पाकिस्तान और भारत के प्रमुख जनसांख्यिकीय संकेतकों का उल्लेख करें।

उत्तर: चीन, पाकिस्तान और भारत के प्रमुख जनसांख्यिकीय संकेतक निम्नलिखित हैं:

i) जनसंख्या: पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और यह चीन और भारत का लगभग दसवां हिस्सा है।

ii) जनसंख्या घनत्व: हालांकि चीन भौगोलिक दृष्टि से तीनों में सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसका घनत्व सबसे कम है।

iii) जनसंख्या वृद्धि: जनसंख्या वृद्धि पाकिस्तान में सबसे अधिक है, उसके बाद भारत और चीन का स्थान है। 1970 के दशक के अंत में चीन में शुरू की गई एक-बच्चे की नीति कम जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। लेकिन इस उपाय से लिंगानुपात में गिरावट आई।

iv) लिंगानुपात: तीनों देशों में लिंगानुपात कम और महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण है। इन सभी देशों में इसका कारण प्रबल पुत्र-वरीयता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. सकल घरेलू उत्पाद में भारत और चीन के क्षेत्रीय योगदान की तुलना करें और तुलना करें। यह क्या दर्शाता है?

उत्तर- उत्पादन और रोजगार का क्षेत्रीय वितरण:

- (i) कृषि क्षेत्र। चीन में शहरी लोगों का अनुपात भारत से अधिक है। वर्ष 2009 में चीन में, जहाँ 54 प्रतिशत कार्यबल कृषि में लगा हुआ था, सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 10 प्रतिशत है। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 17 फीसदी है।
- (ii) उद्योग और सेवा क्षेत्र। भारत और चीन दोनों में, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कार्यबल का अनुपात कम है लेकिन उत्पादन के मामले में उनका योगदान अधिक है। चीन में, विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक 46 प्रतिशत योगदान देता है जबकि भारत में यह सेवा क्षेत्र है जो सबसे अधिक योगदान देता है। इस प्रकार, चीन की वृद्धि में मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है और भारत की वृद्धि में सेवा क्षेत्र का योगदान है।

Q2. चीन की तीव्र औद्योगिक वृद्धि का पता 1978 में उसके सुधारों से लगाया जा सकता है। क्या आप सहमत हैं? स्पष्ट करें।

उत्तर: हां, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चीन की तीव्र औद्योगिक वृद्धि 1978 के बाद से चरणों में शुरू किए गए विभिन्न आर्थिक सुधारों का समग्र परिणाम है।

प्रारंभिक चरण में कृषि, विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्रों में सुधार शुरू किये गये। सामूहिक खेती की प्रणाली जिसे कम्यून प्रणाली के नाम से जाना जाता है, लागू की गई। इस प्रणाली के तहत, भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित किया गया था जिन्हें व्यक्तिगत परिवारों को आवंटित किया गया था। इन परिवारों को सरकार को कर चुकाने के बाद ज़मीन से होने वाली शेष आय अपने पास रखने की अनुमति थी। बाद के चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार प्रारम्भ किये गये। इस चरण के दौरान, निजी फर्मों और गाँव और टाउनशिप उद्यमों को वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी। सुधारों में दोहरी मूल्य निर्धारण भी शामिल था। दोहरे मूल्य निर्धारण का तात्पर्य यह है कि किसानों और औद्योगिक इकाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर एक निश्चित मात्रा में इनपुट और आउटपुट खरीदने और बेचने की आवश्यकता होती थी और शेष मात्रा का बाजार मूल्य पर व्यापार किया जाता था। धीरे-धीरे, बाद के वर्षों में कुल उत्पादन में तेजी से वृद्धि के साथ, बाजार में कारोबार की मात्रा कई गुना बढ़ गई।

सुधारों में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना भी शामिल है। इसलिए, चीन की तीव्र औद्योगिक वृद्धि उसके आर्थिक सुधारों के विभिन्न चरणों की सफलता के कारण है।

Q3. चीन, पाकिस्तान और भारत के प्रमुख जनसांख्यिकीय संकेतकों का उल्लेख करें।

उत्तर: चीन, पाकिस्तान और भारत के प्रमुख जनसांख्यिकीय संकेतक निम्नलिखित हैं:

i) जनसंख्या: पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और यह चीन और भारत का लगभग दसवां हिस्सा है।

ii) जनसंख्या घनत्व: हालाँकि चीन भौगोलिक दृष्टि से तीनों में सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसका घनत्व सबसे कम है।

iii) जनसंख्या वृद्धि: जनसंख्या वृद्धि पाकिस्तान में सबसे अधिक है, उसके बाद भारत और चीन का स्थान है। 1970 के दशक के अंत में चीन में शुरू की गई एक-बच्चे की नीति कम जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। लेकिन इस उपाय से लिंगानुपात में गिरावट आई।

iv) लिंगानुपात: तीनों देशों में लिंगानुपात कम और महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण है। इन सभी देशों में इसका कारण प्रबल पुत्र-वरीयता है।

केस आधारित प्रश्न

1. निम्नलिखित पाठ को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 का उत्तर दें:

चीन-पाक मैत्री गलियारा

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) ने दोनों देशों के बीच रिश्ते को मजबूत किया है। लेकिन इसने पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ डालने और चीन को पाकिस्तान की ऋण रणनीतिक संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए आलोचना भी शुरू कर दी है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा सीपीईसी की नींव मई 2013 में रखी गई थी। उस समय, पाकिस्तान कमजोर आर्थिक विकास से जूझ रहा था। चीन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में अभिन्न भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान और चीन के बीच रणनीतिक संबंध दशकों पुराने हैं। पाकिस्तान ने ऐसे समय में चीन की ओर रुख किया जब उसे कठिन बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से बिजली संयंत्रों और राजमार्गों में महत्वपूर्ण निवेश को पूरा करने के लिए बाहरी वित्तपोषण में तेजी से वृद्धि की आवश्यकता थी। सीपीईसी की प्रारंभिक फसल परियोजनाओं ने इस आवश्यकता को पूरा किया, जिससे पाकिस्तान की बिजली उत्पादन क्षमता में नाटकीय वृद्धि हुई, जिससे आपूर्ति पक्ष की बाधाएं समाप्त हो गईं, जिससे देश भर में ब्लैकआउट एक नियमित घटना बन गई थी।

पाकिस्तान के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में चीन: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने की चीन की क्षमता हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है, मुख्यतः इस तथ्य के कारण कि बीजिंग अब इस्लामाबाद का सबसे बड़ा ऋणदाता है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दस्तावेजों के अनुसार, जून 2013 में पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत विदेशी ऋण 44.35 बिलियन डॉलर था, जिसका केवल 9.3 प्रतिशत चीन पर बकाया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, अप्रैल 2021 तक, यह विदेशी ऋण बढ़कर 90.12 बिलियन डॉलर हो गया था, जिसमें पाकिस्तान को अपने कुल विदेशी ऋण का 27.4 प्रतिशत - \$ 24.7 बिलियन - चीन को देना था।

Q.1 चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को होने वाले किन्हीं दो आर्थिक लाभों की रूपरेखा और चर्चा करें।

Q2 चीनी अर्थव्यवस्था की तुलना में पाकिस्तान की द्विपक्षीय 'ऋण-जाल' स्थिति के निहितार्थ का विश्लेषण करें।

उत्तर 1 . पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के आर्थिक लाभ हैं:

मैं। चीन ने पाकिस्तान को सड़क बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करने, अर्थव्यवस्था में रोजगार और आय का समर्थन करने के लिए वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की

द्वितीय. सीपीईसी के कारण पाकिस्तान की बिजली उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि हुई है। इसने देश में आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को समाप्त कर दिया है, जिसने देश भर में ब्लैकआउट को एक नियमित घटना बना दिया था।

उत्तर 2: चीन हाल के दिनों में अपनी 'डेट ट्रेप डिप्लोमेसी' के लिए प्रसिद्ध हो गया है। इसके तहत चीन विभिन्न देशों को अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव में लाने में मदद करने के लिए वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञता/सहायता प्रदान करता है।

कूटनीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि बीजिंग अब इस्लामाबाद का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है।

पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दस्तावेजों के अनुसार, अप्रैल 2021 तक विदेशी कर्ज बढ़ गया था

\$90.12 बिलियन, जिसमें पाकिस्तान को अपने कुल विदेशी ऋण का 27.4 प्रतिशत - \$24.7 बिलियन - चीन को देना है,

केस स्टडी आधारित प्रश्न-2

चीन में तेज़ औद्योगिक विकास का मूल कारण 1978 में चरणों में शुरू किए गए सुधारों में खोजा जा सकता है। प्रारंभिक चरण में, कृषि, विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्रों में सुधार शुरू किए गए थे। कृषि में, सामुदायिक भूमि को छोटे भूखंडों में विभाजित किया गया था जिन्हें व्यक्तिगत परिवारों को आवंटित किया गया था। उन्हें निर्धारित करों का भुगतान करने के बाद भूमि से होने वाली सारी आय अपने पास रखने की अनुमति थी। बाद के चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार प्रारम्भ किये गये। निजी क्षेत्र की फर्मों और टाउनशिप

और ग्रामीण उद्यमों को सामान का उत्पादन करने की अनुमति दी गई। इस स्तर पर, सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों (जिन्हें राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम या एसओई के रूप में जाना जाता है) को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। सुधार के दौरान दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली अपनाई गई। इसका मतलब है दो तरह से कीमतें तय करना। एक तो किसानों और औद्योगिक इकाइयों के लिए, जिन्हें सरकार द्वारा तय कीमतों के आधार पर इनपुट और आउटपुट की निश्चित मात्रा खरीदने और बेचने की आवश्यकता होती है और दूसरी, बाजार में खरीदे और बेचे जाने वाले इनपुट और आउटपुट की कीमत के आधार पर। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापित किए गए।

- उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनमें चीन में प्रारंभिक चरण में सुधार शुरू किए गए थे।
उत्तर: कृषि, विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्र
- चीन द्वारा अपनाई गई दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली से आप क्या समझते हैं?
उत्तर: इसका अर्थ है दो तरीकों से कीमतें तय करना। एक तो किसानों और औद्योगिक इकाइयों के लिए, जिन्हें सरकार द्वारा तय कीमतों के आधार पर इनपुट और आउटपुट की निश्चित मात्रा खरीदने और बेचने की आवश्यकता होती है और दूसरा, बाजार में खरीदे और बेचे जाने वाले इनपुट और आउटपुट के लिए मूल्य।
- SEZ क्या है?
उत्तर: एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) एक ऐसा क्षेत्र है जो एक ही देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में भिन्न आर्थिक नियमों के अधीन है। विदेशी निवेश और तकनीकी प्रगति को आकर्षित करने के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करके तेजी से आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) बनाए गए हैं। जबकि कई देशों ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित किए हैं, चीन विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए एसईजेड का उपयोग करने में सबसे सफल रहा है।

केस स्टडी आधारित प्रश्न-3

पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और यह चीन या भारत का लगभग दसवां हिस्सा है। चीन की जनसंख्या विश्व में भारत के बाद सबसे अधिक है और भौगोलिक दृष्टि से इसका क्षेत्रफल तीनों देशों में सबसे बड़ा है; इसलिए इसका घनत्व सबसे कम है। भारत में घनत्व जनसंख्या सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर पाकिस्तान में सबसे अधिक है, उसके बाद भारत और चीन का स्थान है। तीनों देशों में लिंगानुपात कम है और महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण है। विद्वान इन सभी देशों में प्रचलित पुत्र वरीयता को इसका कारण बताते हैं। चीन में भी प्रजनन दर कम है और पाकिस्तान में बहुत अधिक है। चीन में शहरीकरण अधिक है और भारत में 33 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।

नीचे दी गई तालिका में दिए गए चुनिंदा जनसांख्यिकी संकेतकों के आधार पर तालिका के अंत में प्रश्न का उत्तर दें।

देश	अनुमानित जनसंख्या (में लाखों)	वार्षिक की वृद्धि जनसंख्या(2018)	घनत्व (प्रति वर्ग. किमी) (2018)	लिंग अनुपात (2018)	उपजाऊपन दर (2017)	शहरीकरण (2018)
भारत	1352	1.03	455	924	2.2	34
चीन	1393	0.46	148	249	1.7	59
पाकिस्तान	212	2.05	275	943	3.6	37

- उस देश का उल्लेख करें जिसकी वार्षिक वृद्धि दर और प्रजनन दर सबसे अधिक है:
उत्तर: पाकिस्तान
- तीनों देशों में कम लिंगानुपात के लिए विद्वानों द्वारा उद्धृत प्रचलित कारण क्या हैं?
उत्तर: विद्वान इन सभी देशों में प्रचलित पुत्र वरीयता को इसका कारण बताते हैं।
- चीन में जनसंख्या की कम वृद्धि दर का क्या कारण है?
उत्तर: एक बच्चा नीति मानदंड।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
रांची संभाग
सैपल पेपर (2023-24)

सामान्य निर्देश:

1. दोनों खंडों में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं
2. प्रश्न संख्या 1-10 और 18-27 अति लघु उत्तरीय या बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। उनका उत्तर एक-एक वाक्य/एक-एक शब्द में देना होगा।
3. प्रश्न संख्या 11-12 और 28-29 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर 3 अंक का है, प्रत्येक का उत्तर सामान्यतः 60 - 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
4. प्रश्न संख्या 13-15 और 30-32 भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इनका उत्तर सामान्यतः 80-100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. प्रश्न संख्या 16-17 और 33-34 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक 6 अंक का है। इनका उत्तर सामान्यतः 100-150 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
6. उत्तर संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए और जहां तक संभव हो उपरोक्त शब्द सीमा का पालन करना चाहिए।

खंड - A		
क्र.	प्रश्न	अंक
1	वे वस्तुएँ जो मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे संतुष्ट करती हैं, कहलाती हैं। a) मध्यवर्ती वस्तुएँ (b) उपभोक्ता वस्तुएँ (c) पूंजीगत वस्तुएँ (d) इनमें से कोई नहीं	1
2	चालू खाते का अधिशेष है:- ए) निर्यात की तुलना में आयात की अधिकता बी) आयात की तुलना में निर्यात की अधिकता सी) भुगतान से अधिक चालू खाता रसीद डी) भुगतान की तुलना में चालू खाता प्राप्तियों की कमी	1
3	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी का विनिवेश एक नीति है ए) मौद्रिक बी) राजकोषीय ग) ए और बी दोनों डी) न तो ए और न ही बी	1
4	यदि घरेलू बाजार में ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं तो इसका BOP पर क्या प्रभाव पड़ेगा:- क) विदेशी मुद्रा प्रवाह में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार ख) विदेशी मुद्रा प्रवाह में कमी और भुगतान संतुलन में सुधार ग) विदेशी मुद्रा प्रवाह में वृद्धि और बीओपी का खराब होना घ) विदेशी मुद्रा प्रवाह में कमी और भुगतान संतुलन में सुधार	1
5	यदि चालू खाता असंतुलित है तो इसे कैसे संतुलित किया जा सकता है:- (ए) उधार और उधार के माध्यम से (बी) कारक सेवाओं के आयात और निर्यात के माध्यम से (सी) प्रेषण के माध्यम से (डी) माल के आयात और निर्यात के माध्यम से	1
6	मुद्रा आपूर्ति कौन सी अवधारणा है? (ए) स्टॉक (बी) प्रवाह (सी) मौद्रिक (डी) उपरोक्त में से कोई नहीं	1
7	मुद्रा आपूर्ति के एम1 में शामिल नहीं है। (ए) जनता द्वारा रखी गई मुद्रा (बी) आरबीआई में अन्य जमा (सी) वाणिज्यिक बैंक के साथ मांग जमा (डी) वाणिज्यिक बैंक के साथ शुद्ध सावधि जमा	1

8	<p>अभिकथन (ए) : वह बिंदु जिस पर बचत वक्र एक्स अक्ष को काटता है उसे ब्रेक ईवन बिंदु के रूप में जाना जाता है। कारण (R): इस बिंदु पर, $S=0$ और $C=Y$ (ए) अभिकथन (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं, और कारण (आर) अभिकथन (ए) का सही स्पष्टीकरण है (बी) अभिकथन (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण (आर) अभिकथन (ए) का सही स्पष्टीकरण नहीं है (सी) अभिकथन (ए) सच है, लेकिन कारण (आर) गलत है। (डी) अभिकथन (ए) सच है, लेकिन कारण (आर) गलत है</p>	1
9	<p>अभिकथन (ए) : APS कभी भी एक या एक से अधिक नहीं हो सकता। कारण (आर) : घटती दर के साथ आय में वृद्धि के साथ APC में वृद्धि। (ए) अभिकथन (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं, और कारण (आर) अभिकथन (ए) का सही स्पष्टीकरण है (बी) अभिकथन (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण (आर) अभिकथन (ए) का सही स्पष्टीकरण नहीं है (सी) अभिकथन (ए) सच है, लेकिन कारण (आर) गलत है। (डी) अभिकथन (ए) सच है, लेकिन कारण (आर) गलत है।</p>	1
10	जब निवेश गुणक 1 होता है, तो MPC का मूल्य भी 1 होता है। सत्य/ असत्य	1
11	राजकोषीय घाटा क्या है? इसके निहितार्थ स्पष्ट करें।	3
12	मुद्रास्फीति अंतराल क्या है? इस अंतराल को दूर करने में नकद आरक्षित अनुपात की भूमिका स्पष्ट करें।	3
13	<p>a) जब विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ती है, तो इसकी मांग कम हो जाती है। समझाइए क्यों ? b) विदेशी मुद्रा की मांग के स्रोतों का उल्लेख करें।</p>	4
14	<p>एक अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय रु. 600 और उपभोग फलन $C = 90 + 0.7Y$ है। क्या अर्थव्यवस्था 2,000 आय स्तर पर संतुलन में है? या समग्र मांग क्या है? इसके घटक बताइये।</p>	4
Case based questions		
15	<p>निम्नलिखित केस स्टडी पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें और उसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। भारत का केंद्रीय बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) सर्वोच्च संस्था है जो संपूर्ण वित्तीय बाज़ार को नियंत्रित करती है। इसका एक प्रमुख कार्य विदेशी मुद्रा का भंडार बनाए रखना है। साथ ही, यह विदेशी विनिमय दर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है। दूसरे शब्दों में, मौद्रिक नीति के माध्यम से किसी देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना केंद्रीय बैंक का काम है। यदि अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है या पीछे जा रही है, तो केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठा सकता है। ये कदम, चाहे वे परिसंपत्ति खरीद हों या अधिक पैसा छापना, सभी में अर्थव्यवस्था में अधिक नकदी डालना शामिल है। सरल आपूर्ति और मांग आर्थिक प्रक्षेपण होता है और मुद्रा का अवमूल्यन होगा। जब विपरीत होता है, और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो केंद्रीय बैंक उस वृद्धि को स्थिर रखने और मजदूरी और कीमतों जैसे अन्य आर्थिक कारकों के अनुरूप रखने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करेगा। केंद्रीय बैंक जो कुछ भी करता है या वास्तव में नहीं करता है, उसका उस देश की मुद्रा पर असर पड़ेगा। कभी-कभी, किसी मुद्रा के मूल्य को जानबूझकर प्रभावित करना केंद्रीय बैंक के हित में होता है। उदाहरण के लिए, यदि अर्थव्यवस्था निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है और उनकी मुद्रा का मूल्य बहुत अधिक हो जाता है, तो उस देश के वस्तुओं के आयातक सस्ती आपूर्ति की तलाश करेंगे; इसलिए इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।</p>	4
15 A	<p>घरेलू अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? (ए) राजकोषीय उपकरण (बी) मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण (सी) गुणात्मक मौद्रिक उपकरण (डी) दोनों (बी) और (सी)</p>	

15 B	मुद्रा आपूर्ति एक ----- अवधारणा है। (क) प्रवाह (ख) स्टॉक (ग) स्टॉक और प्रवाह का अनुपात (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं	
15 C	विदेशी विनिमय दर में अत्यधिक वृद्धि होने पर केंद्रीय बैंक को निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाना चाहिए? a) अपने स्टॉक से विदेशी मुद्रा की आपूर्ति करना ख) अन्य विदेशी मुद्रा की अधिक मांग करना ग) वाणिज्यिक बैंकों को कम सख्त माहौल में काम करने की अनुमति दें घ) दोनों (बी) और (सी)	
15 D	केंद्रीय बैंक की प्रिय मुद्रा नीति, जिसका उपयोग विकास को स्थिर और अन्य आर्थिक कारकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए किया जाता है, को संदर्भित करता है a) अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को मजबूत करना b) अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को आसान बनाना c) वाणिज्यिक बैंकों को कम सख्त माहौल में काम करने की अनुमति दें d) (बी) और (सी) दोनों	
16	निम्नलिखित आंकड़ों से (ए) आय विधि और (बी) व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करें: आइटम i. कर्मचारियों का मुआवजा 1,000 ii. विदेश से शुद्ध कारक आय (-) 20 iii. शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 120 iv. लाभ 800 v. निजी अंतिम उपभोग व्यय 2,000 vi. शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण 770 vii. स्थायी पूंजी की खपत 130 viii. किराया 600 ix. ब्याज 620 x. स्व-रोज़गार की मिश्रित आय 700 xi. शुद्ध निर्यात (-) 30 xii. सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 1,100	6
	अथवा राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित को कैसे ध्यान में रखा जाएगा? कारण दे। (ए) घर की बिक्री पर पूंजीगत लाभ (बी) लॉटरी पर पुरस्कार (सी) सार्वजनिक ऋण पर ब्याज	
17	स्पष्ट करें कि उपभोग और निवेश (C+I) दृष्टिकोण का उपयोग करके अर्थव्यवस्था आय का संतुलन स्तर कैसे प्राप्त करती है।	6
	खंड - B	
18	अभिकथन (ए) : ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प का पतन हुआ था। कारण (आर) : भारत दुनिया में कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक था। ए) अभिकथन (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) अभिकथन (ए) का सही स्पष्टीकरण है बी) अभिकथन (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) अभिकथन (ए) का सही स्पष्टीकरण नहीं है सी) अभिकथन (ए) सत्य है लेकिन कारण (आर) गलत है। डी) अभिकथन (ए) गलत है लेकिन कारण (आर) सच है।	1
19	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी :- ए) 1857 (बी) 1907 (सी) 1921 (डी) 1951	1
20	योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? (ए) 2014 (बी) 2015 (सी) 2016 (डी) 2017	1

21	RIO शिखर सम्मेलन 1992 का 'एजेंडा' 21 संबंधित है - (ए) सतत विकास। (बी) प्रदूषक - भुगतान सिद्धांत (सी) पर्यावरण शिक्षा। (डी) ओजोन परत का संरक्षण	1
22	चीन में आर्थिक सुधार कब लागू किये गये? [ए] 1979 [बी] 1977 [सी] 1978 [डी] 1980	1
23	1956 की औद्योगिक नीति में, उद्योगों को विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था। (ए) 2 (बी) 7 (सी) 15 (डी) 17	1
24	वस्तु एवं सेवा (जीएसटी) एक कर है। (ए) प्रत्यक्ष (बी) अप्रत्यक्ष (सी) दोनों (ए) और (बी) (डी) इनमें से कोई नहीं	1
25	दावा (ए) : भारतीय कृषि रोजगार का प्राथमिक स्रोत थी। कारण (आर) : भारतीय उद्योगों में विकास नहीं हो रहा था। (ए) दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण है। (बी) दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण नहीं है। (सी) दावा (ए) सत्य है लेकिन कारण (आर) गलत है। (डी) दावा (ए) गलत है लेकिन कारण (आर) सच है।	1
26	MRTTP एक्ट के स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया है? (ए) प्रतिस्पर्धा अधिनियम (बी) एकाधिकार अधिनियम (सी) लाइसेंसिंग अधिनियम (डी) विदेशी मुद्रा अधिनियम	1
27	भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या कौन सी है? (ए) घटती जनसंख्या (बी) उच्च शैक्षणिक स्तर (सी) ब्रेन ड्रेन (डी) लैंगिक समानता	1
28	नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और प्रश्न संख्या के उत्तर दें। हालाँकि ब्रिटिश शासन से पहले भारत एक बहुत ही स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अंत में यह समाप्त हो गई। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था विकास का मार्ग खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नीतियां केवल उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए थीं, भारत समृद्धि के रास्ते से भटक रहा था। हम अंग्रेजों के लिए केवल कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता थे। उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किये बिना ही हमारे श्रम का उपयोग किया। 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने ज्ञान और जागरूकता हासिल करने की हमारी इच्छाशक्ति को भी छीन लिया। चूँकि हम उनके गुलाम थे इसलिए हमें उचित शिक्षा का अधिकार कभी नहीं मिला। और इन कार्यों के परिणामस्वरूप, उनके शासनकाल के अंत में, हम निरक्षर थे। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे लोगों से भरी हुई थी जिनके पास देश की मदद करने की कोई योजना नहीं थी।	3
28	स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी। (a) (ए) विकसित (बी) अविकसित (सी) पिछड़ा (डी) दोनों (बी) और (सी)	
28	निम्नलिखित में से कौन सा भारत के व्यापार उपभोग के लिए सही है? (b) ए) भारत कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक था। बी) भारत तैयार माल के लिए आसान बाजार था। सी) दोनों (ए) और (बी) डी) इनमें से कोई नहीं	
28	ब्रिटिश शासन के वर्षों ने ज्ञान और जागरूकता प्राप्त करने की हमारी इच्छाशक्ति को भी छीन लिया। (c) (ए) 100 (बी) 200 (सी) 300 (डी) 400	
29	मानव पूंजी में निवेश विकास में कैसे योगदान देता है?	3
30	भारत में विकास योजनाओं के चार सामान्य लक्ष्यों (या उद्देश्यों) की व्याख्या करें। या भारत ने नियोजन का विकल्प क्यों चुना? स्पष्ट करें।	4
31	सतत विकास एक दैनिक जीवन गतिविधि के रूप में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। अपने अवलोकन लिखें.	4
32	भारत में सुधार क्यों लागू किये गये? व्याख्या करना	4

33	क्या आपको लगता है कि आउटसोर्सिंग भारत के लिए अच्छा है? विकसित देश इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?	6
34	मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या हैं? (किन्हीं दो स्रोतों की व्याख्या करें) या सामाजिक न्याय और कल्याण के आलोक में भारत में आर्थिक सुधारों पर चर्चा करें।	6

केन्द्रीय विद्यालय संगठन उत्तरकुंजी		
विषय- अर्थशास्त्र	उत्तर	कक्षा-बारहवीं
क्र .	उत्तर	अंक
1	b	1
2	C	1
3	d	1
4	a	1
5	a	1
6	(a)	
7	D)	1
8	(A)	1
9	A)	1
10	गलत	1
11	राजकोषीय घाटा सरकार की उधारी को छोड़कर राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के योग पर सभी व्यय (पूंजी और राजस्व) की अधिकता के बराबर है। आशय: (1) यह अपने बजट व्यय को पूरा करने के लिए उधार पर सरकार की निर्भरता की सीमा को दर्शाता है। (2) यह सरकार की ओर से फिजूलखर्ची और अनावश्यक खर्च को बढ़ावा देता है। (3) इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव पैदा होता है। (4) उधार की पूरी राशि व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसका एक हिस्सा ब्याज भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है।	3
12	सही स्पष्टीकरण के लिए 3 अंक दें	1+2
13	जब विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ती है तो इसका तात्पर्य यह है कि देश के घरेलू निवासियों के लिए विदेशी वस्तुएं महंगी हो गई हैं। इसके परिणामस्वरूप घरेलू निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं की मांग में गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा की मांग गिर जाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि रुपया-डॉलर विनिमय दर (रुपये के संदर्भ में डॉलर की कीमत) \$1= 50 रुपये से बढ़कर \$1=52 रुपये हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि एक डॉलर मूल्य का विदेशी सामान खरीदने के लिए घरेलू निवासियों को अब 50 रुपये के बजाय 52 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। जिससे विदेशी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। नतीजतन, डॉलर की मांग कम हो जाती है। विदेशी मुद्रा की मांग या बहिर्प्रवाह के तीन स्रोत हैं: 1) आयात: इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है क्योंकि आयात के लिए भुगतान केवल विदेशी मुद्रा में किया जाता है। 2) विदेशी निवेश: शेष विश्व में निवेश एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि है। हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है जिसमें निवेश करना हो। 3) विदेश में सीधी खरीदारी: विदेश से वस्तुओं और सेवाओं की सीधी खरीदारी करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है।	2+2
14	सही सूत्र के लिए 1 अंक, गणना के लिए 1 अंक, सही उत्तर के लिए 1 अंक कारण लिखने पर 1 अंक Y = 2300 या सही परिभाषा के लिए 1 अंक, इसके घटकों की व्याख्या के लिए 3 अंक	4
15	(A)d (B) b (C) d (d)d	1+1+ 1+1

16	<p>राष्ट्रीय आय (आय विधि) (i)+(viii)+(ix)+(iv)+(x)+(ii) = 3700 करोड़। 3 अंक</p> <p>राष्ट्रीय आय (व्यय विधि) (v)+(xii)+(vi)+(xi) –(iii)+(ii) = 3700 करोड़ 3 अंक</p> <p>या (ए) शामिल नहीं है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि नहीं करता है। 2 निशान (बी) शामिल नहीं है, क्योंकि यह अप्रत्याशित लाभ है और इसलिए इसे हस्तांतरण भुगतान के रूप में माना जाता है। 2 अंक (सी) शामिल नहीं है, क्योंकि इसे हस्तांतरण भुगतान माना जाता है। 2 निशान</p>	3+3
17	<p>सही स्पष्टीकरण के लिए 3 अंक सही डायग्राम बनाने पर 1 अंक रेखाचित्रों की सही व्याख्या के लिए 2 अंक</p>	3+1+ 2
18	B)	1
19	(b)1907	1
20	(b) 2015	1
21	a	1
22	C	1
23	(d) 17	1
24	b)	1
25	(B)	1
26	a)	1
27	c)	1
28	28 (a) (d) 28(b) (C) 28(c) (b)	
29	सही स्पष्टीकरण के लिए 3 अंक दें।	3
30	सही व्याख्या के लिए 4 अंक दें	1+1+ 1+1
31	सही व्याख्या के लिए 4 अंक दें	4
32	सही व्याख्या के लिए 4 अंक दें	4
33	<p>हाँ, यह भारत के लिए अच्छा है। नीचे दिए गए ये बिंदु इसे उचित ठहराने में और मदद करते हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत जैसे विकासशील देश के लिए, रोजगार सृजन एक चिंता का विषय है और आउटसोर्सिंग रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समाधान प्रदान करता है। 2. यह विकसित देशों से विकासशील देशों तक प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के बारे में ज्ञान के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। 3. आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करके भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में खुद को विश्वसनीय बनाता है, इससे भारत में अंतरराष्ट्रीय निवेश लाने में मदद मिलेगी। 4. आउटसोर्सिंग सेवा क्षेत्रों में रास्ते खोलती है और शिक्षित युवाओं को कौशल प्राप्त करने में मदद करती है जिसके परिणामस्वरूप मानव पूंजी निर्माण होगा 	1.5+ 1.5+ 1.5+ 1.5

34	<p>सही परिभाषा के लिए 2 अंक किन्हीं दो स्रोतों की सही व्याख्या के लिए 4 अंक या उत्तर. आर्थिक सुधारों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक सक्षम प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया। यहां अन्य सकारात्मक बिंदु हैं जो सुधारों के परिणामस्वरूप हुए</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. दुनिया भर में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही। 2. विदेशी पूंजी के प्रवाह से निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी 3. सेवा क्षेत्र में तेजी से ईको टूरिज्म को बढ़ावा मिला 4. जीडीपी कई गुना बढ़ी 5. रोजगार के अवसर <p>नकारात्मक बिंदु</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि उद्योग के लिए कोई लाभ नहीं 2. सुधारों से उच्च आय वर्ग को लाभ हुआ और निम्न एवं मध्यम वर्ग के लिए जीवन कठिन हो गया 3. महानगरों के निकटवर्ती क्षेत्रों के विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों को अविकसित बना दिया। <p>इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आर्थिक सुधार सामाजिक न्याय प्रदान नहीं कर सके और आम जनता के कल्याण के लिए कार्य करने में असमर्थ रहे।</p>	2+2+ 2
----	---	-----------

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
रांची संभाग
सैम्पल पेपर -2
सत्र: 2023-24

कक्षा: बारहवीं
अवधि: 3 घंटे

विषय: अर्थशास्त्र
अधिकतम अंक: 80

सामान्य निर्देश:

1	इस प्रश्न पत्र में दो भाग हैं: भाग ए - मैक्रो इकोनॉमिक्स (40 अंक) भाग बी - भारतीय आर्थिक विकास (40 अंक)।	
2	प्रश्न संख्या 1-10 और प्रश्न संख्या 18 - 27 (दो केस आधारित प्रश्नों सहित) 1-अंक वाले प्रश्न हैं और इनका उत्तर एक शब्द/वाक्य में दिया जाना है।	
3	केस आधारित प्रश्न (सीबीक्यू) प्रश्न संख्या 7-10 और प्रश्न संख्या 24-27 हैं।	
4	प्रश्न संख्या 11-12 और प्रश्न संख्या 28 - 29 3 अंक के प्रश्न हैं और प्रत्येक का उत्तर 60 - 80 शब्दों में दिया जाना है।	
5	प्रश्न संख्या 13-15 और प्रश्न संख्या 30 - 32 4 अंक के प्रश्न हैं और प्रत्येक का उत्तर 80-100 शब्दों में दिया जाना है।	
6	प्रश्न संख्या 16-17 और प्रश्न संख्या 33-34 6 अंकों के प्रश्न हैं और प्रत्येक का उत्तर 100-150 शब्दों में दिया जाना है।	
PART A - MACRO ECONOMICS		
1)	यदि किसी अर्थव्यवस्था में विदेश से शुद्ध साधन आय का मूल्य ₹200 करोड़ है और विदेश से आने वाली साधन आय का मूल्य ₹40 करोड़ है। विदेश से कारक आय के मूल्य की पहचान करें। (सही विकल्प चुनें) (ए) 200 करोड़ (बी) 160 करोड़ (सी) 240 करोड़ (डी) 180 करोड़ या मध्यवर्ती वस्तु को परिभाषित करें।	1
2)	_____ गैर-कर राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है।	1
3)	रोजगार सृजन की प्रक्रिया में सरकारी बजट को एक प्रभावी उपकरण के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है?	1

4)	<p>निम्नलिखित कथन पढ़ें - दावा (ए) और कारण (आर)। नीचे दिए गए सही विकल्पों में से एक चुनें: दावा (ए) : साख निर्माण निवेश के उद्देश्य के लिए ऋण की उपलब्धता का विस्तार करके विकास की प्रक्रिया को तेज करता है। कारण (आर) : साख निर्माण बाजार/कुल मांग के आकार का विस्तार करके विकास की प्रक्रिया में योगदान देता है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की मांग बढ़ती है। विकल्प: ए) दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण है बी) दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण नहीं है सी) दावा (ए) सत्य है लेकिन कारण (आर) गलत है। डी) दावा (ए) गलत है लेकिन कारण (आर) सच है।</p>	1
5)	<p>पहचानें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? (सही विकल्प का चयन करें) ए। लचीली विनिमय दर प्रणाली सरकार को विदेशी मुद्रा भंडार के बड़े स्टॉक को बनाए रखने के लिए अधिक लचीलापन देती है। बी। प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली में, सरकार विदेशी मुद्राओं को खरीदने और बेचने में हस्तक्षेप करती है। सी। प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली में, केंद्रीय बैंक विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करता है। डी। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में, बाज़ार की शक्तियाँ विनिमय दर तय करती हैं।</p>	1
6)	<p>चालू खाता अधिशेष को परिभाषित करें।</p>	1
	<p>निम्नलिखित समाचार रिपोर्ट पढ़ें और उसके आधार पर प्रश्न 7-10 का उत्तर दें: आरबीआई मौद्रिक नीति 2021: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने कम से कम चालू वित्तीय वर्ष से लेकर अगले वर्ष तक जब तक आवश्यक हो 'समायोजनात्मक रुख' बनाए रखते हुए अपनी रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। , आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को घोषणा की। आरबीआई गवर्नर ने घोषणा की कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है और रिवर्स रेपो दर को भी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है। केंद्रीय बैंक ने विकास को समर्थन देने के लिए मार्च 2020 के अंत से रेपो दर में 115 आधार अंकों की कटौती की थी। यह लगातार चौथी बार है जब एमपीसी ने नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है।</p> <p style="text-align: center;">- द इंडियन एक्सप्रेस; फरवरी 5, 2021</p>	
7)	<p>आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती से अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग ----- ----- (वृद्धि/कमी) होने की संभावना है।</p>	1
8)	<p>आपको क्या लगता है कि एमपीसी ने यह उदार रुख अपनाने और ब्याज दरों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का फैसला क्यों किया?</p>	1
9)	<p>RBI का रिवर्स रेपो रेट क्या है?</p>	1
10)	<p>वह अंतर जिसके द्वारा वास्तविक समग्र मांग पूर्ण रोजगार संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक समग्र मांग से अधिक हो जाती है, उसे ----- के रूप में जाना जाता है। (मुद्रास्फीति अंतर/अपस्फीति अंतर)</p>	1
11)	<p>(ए) संक्षेप में चर्चा करें कि सेकेंड-हैंड कार की बिक्री से प्राप्त धन को राष्ट्रीय आय के आकलन में कैसे शामिल किया जाएगा (बी) 'वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद' और 'नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद' के बीच अंतर करें। या नीचे उल्लेख किए गए परिभाषित करें: ए) पूंजीगत सामान बी) संपत्ति और उद्यमिता से आया। ग) प्रवाह चर</p>	1 2
12)	<p>एक काल्पनिक संख्यात्मक उदाहरण का उपयोग करते हुए, एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा ऋण निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या करें।</p>	3

13)	'माना जाता है कि 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा बढ़कर 18.49 ट्रिलियन या सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% हो जाएगा, जबकि बजट में यह 3.5% था।' (ए) वर्तमान बजट 2021 में राजकोषीय घाटे को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार दो कारण बताएं (a) (बी) सरकारी बजट में राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के बीच अंतर करें।	4										
14)	किसी अर्थव्यवस्था में, ब्रेक-ईवन बिंदु और संतुलन बिंदु आय के एक ही स्तर पर हो सकते हैं, यदि प्रत्याशित निवेश (भरें) सही उत्तर वाला रिक्त स्थान) सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (एमपीसी) के मूल्य की गणना करें, यदि किसी अर्थव्यवस्था में स्वायत्त खपत ₹ 500 करोड़ है, प्रत्याशित निवेश ₹ 4000 करोड़ है और अर्थव्यवस्था की आय का संतुलन स्तर ₹ 18,000 करोड़ है। या निवेश गुणक को परिभाषित करें मान लीजिए कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में, राष्ट्रीय आय ₹ 100 करोड़ बढ़ने पर बचत ₹ 20 करोड़ बढ़ जाती है। राष्ट्रीय आय में ₹ 6,000 करोड़ की वृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त निवेश की गणना करें?	4										
15)	"एक देश प्रबंधित फ्लोटिंग सिस्टम के तहत जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य कम रखता है।" संक्षेप में चर्चा करें कि यह देश के निर्यात को कैसे प्रभावित करेगा।	4										
16)	1. किसी महिला द्वारा की जाने वाली घरेलू/घरेलू सेवाओं को आर्थिक गतिविधि नहीं माना जा सकता है।' 2. दिए गए कथन का वैध कारण सहित बचाव या खंडन करें। 3. 'चक्रवात के पीड़ितों को मुआवजा सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपाय का एक उदाहरण है।' 4. वैध कारण सहित बताएं कि क्या इसे भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किया जाना चाहिए/नहीं शामिल किया जाना चाहिए। या मान लीजिए कि 2018-19 में नेशन X का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ₹ 2,000 करोड़ था, जबकि उसी वर्ष नेशन Y का सकल घरेलू उत्पाद ₹ 120,000 करोड़ था। यदि राष्ट्र X का सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 में बढ़कर ₹ 4,000 करोड़ हो जाता है और राष्ट्र Y का सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 में बढ़कर ₹ 200,000 करोड़ हो जाता है। 2018-19 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्र X और Y के सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर की तुलना करें।	3 3										
17)	आय निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत के 'AD = AS' दृष्टिकोण की व्याख्या करें। आरेख का प्रयोग करें.	6										
PART B - INDIAN ECONOMIC DEVELOPMENT												
18)	_____ नहर के खुलने से ब्रिटेन और भारत के बीच माल के परिवहन की लागत में काफी कमी आई। (रिक्त स्थान को भरें)	1										
19)	कॉलम I में संबंधित शब्दों के साथ मिलान करके कॉलम II में दिए गए विकल्पों के सही क्रम को पहचानें: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">COLUMN I</th> <th style="width: 50%;">COLUMN II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. गरीबी के लिए योजना आयोग द्वारा अध्ययन समूह का गठन</td> <td>i. 2005</td> </tr> <tr> <td>B. 'न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमान पर कार्य बल'</td> <td>ii. 1962</td> </tr> <tr> <td>C. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण</td> <td>iii. 2014</td> </tr> <tr> <td>D. रोजगार गारंटी अधिनियम</td> <td>iv. 1979</td> </tr> </tbody> </table> Choose the correct alternative: a) ii, ii, iv, i b) iii, ii, i, iv c) i, ii, iii, iv d) ii, iv, i, iii	COLUMN I	COLUMN II	A. गरीबी के लिए योजना आयोग द्वारा अध्ययन समूह का गठन	i. 2005	B. 'न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमान पर कार्य बल'	ii. 1962	C. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण	iii. 2014	D. रोजगार गारंटी अधिनियम	iv. 1979	1
COLUMN I	COLUMN II											
A. गरीबी के लिए योजना आयोग द्वारा अध्ययन समूह का गठन	i. 2005											
B. 'न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमान पर कार्य बल'	ii. 1962											
C. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण	iii. 2014											
D. रोजगार गारंटी अधिनियम	iv. 1979											

20)	ग्रेट लीप फॉरवर्ड (जीएलएफ) माओ द्वारा वर्ष _____ में शुरू किया गया अभियान था। (सही विकल्प का चयन करें) (ए) 1952 (बी) 1958 (सी) 1960 (डी) 1968	1
21)	चीन में, कम्यून प्रणाली _____ क्षेत्र से संबंधित है। (रिक्त स्थान में सही विकल्प भरें) (ए) कृषि (बी) उद्योग (सी) सेवा (डी) अनौपचारिक	1
22)	निम्नलिखित कथन पढ़ें - दावा (ए) और कारण (आर) नीचे दिए गए सही विकल्पों में से एक चुनें: दावा (ए) : डब्ल्यूटीओ की स्थापना अंतरराष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को प्रशासित करने के लिए की गई थी। कारण (आर) : इस उद्देश्य से, इसने एक नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित की है जिसमें राष्ट्र व्यापार पर मनमाने प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। विकल्प: ए) दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण है बी) दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण नहीं है सी) दावा (ए) सत्य है लेकिन कारण (आर) गलत है। घ) दावा (ए) गलत है लेकिन कारण (आर) सच है। या निम्नलिखित कथन पढ़ें - दावा (ए) और कारण (आर) नीचे दिए गए सही विकल्पों में से एक चुनें: दावा (ए) : भूमि सीमा सुधार ने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। कारण (आर) : योजनाकारों को सुधारों को लागू करने में बहुत समय लगा। विकल्प: ए) दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण है बी) दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण नहीं है सी) दावा (ए) सत्य है लेकिन कारण (आर) गलत है। घ) दावा (ए) गलत है लेकिन कारण (आर) सच है।	1
23)	निम्नलिखित कथन पढ़ें - दावा (ए) और कारण (आर) नीचे दिए गए सही विकल्पों में से एक चुनें: दावा (ए) : विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता का उद्देश्य उस तरह के जीवन में सुधार नहीं कर सकता है जो लोग जी रहे हैं जब तक कि जनता के बीच समानता सुनिश्चित नहीं की जाती है। कारण (आर) : आर्थिक विकास का लाभ सबसे गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। विकल्प: ए) दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावा (ए) का सही स्पष्टीकरण है बी) दावा (ए) और कारण (आर) दोनों सत्य हैं और कारण (आर) दावे (ए) का सही स्पष्टीकरण नहीं है सी) दावा (ए) सत्य है लेकिन कारण (आर) गलत है। डी) दावा (ए) गलत है लेकिन कारण (आर) सच है।	1
	निम्नलिखित काल्पनिक केस स्टडी को ध्यान से पढ़ें और उसी के आधार पर प्रश्न संख्या 24-27 का उत्तर दें। कृषि ऋण समीक्षा समिति (1989) की रिपोर्ट, जिसे खुसरो समिति के नाम से जाना जाता है, कृषि ऋण के क्षेत्र में आरबीआई द्वारा किए गए व्यापक अध्ययनों में से एक थी। कृषि क्षेत्र में, खेतों के लगातार घटते आकार, हरित क्रांति क्षेत्रों में पानी के अत्यधिक दोहन और ऊर्जा की कमी को मौजूदा उत्पादन पर बाधाओं के रूप में पहचाना गया। यह भी देखा गया कि भारतीय कृषि की अधिक वृद्धि के लिए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को अधिक व्यवहार्य, उत्पादक, प्रगतिशील और लाभदायक बनाने के लिए वितीय संस्थानों द्वारा समर्थित विभिन्न राज्यों में कृषि विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी। हालाँकि, कमजोर वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने का उद्देश्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है। ----- गायकवाड (2018), पीएच.डी. थीसिस, सोलापुर विश्वविद्यालय।	
24)	_____ (न्यूनतम समर्थन मूल्य/न्यूनतम खुदरा मूल्य) कृषि को उत्पादक बनाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरणों में से एक है। (रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें)	1

25)	----- (नाबार्ड/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) ग्रामीण ऋण के विस्तार के लिए कार्य करने वाला शीर्ष बैंक है। (रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें)	1
26)	भारत में कृषि विपणन में सुधार के लिए एक उपाय बताएं	1
27)	औपचारिक ऋण प्रणाली की अपर्याप्तताओं को दूर करने के लिए स्वयं सहायता समूह उभरे हैं। (सही या गलत)	1
28)	केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार, सरकार उज्वला योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है, जिससे 80 मिलियन परिवारों को लाभ हुआ है, ताकि 10 मिलियन अधिक लाभार्थियों को कवर किया जा सके। (ए) यह उज्वला योजना क्या थी? (बी) जबकि उज्वला योजना का विस्तार किया गया, ग्रामीण अकुशल श्रमिकों के लिए एक और महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम का परिव्यय कम कर दिया गया। योजना का नाम बताएं। (सी) 'सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया के माध्यम से गरीबी को प्रभावी ढंग से समाप्त किया जा सकता है।' स्पष्ट करें।	3
29)	निम्नलिखित को परिभाषित करें: (ए) पर्यावरण की अवशोषण क्षमता (बी) पर्यावरण की वहन क्षमता या पर्यावरणीय क्षरण के कोई दो प्रमुख कारण बताइये और चर्चा कीजिये।	3
30)	'हरित क्रांति की सफलता दो चरणों में अनुभव की गई।' विस्तार से बताएं। इससे भारत में किसानों को क्या लाभ हुआ? या नई आर्थिक नीति के तहत शुरू किए गए औद्योगिक क्षेत्र के सुधारों की व्याख्या करें।	1 3
31)	जनसांख्यिकी के आधार पर भारत और पाकिस्तान की तुलना करें।	4
32)	(ए) संक्षेप में चर्चा करें कि कैसे संस्थागत सुधारों (भूमि सुधार) ने भारतीय कृषि को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। (बी) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन उद्देश्यों के रूप में "विकास के साथ समानता" के पीछे के तर्क पर संक्षेप में चर्चा करें।	2 2
33)	(ए) 'हरित क्रांति' और 'स्वर्ण क्रांति' के बीच अंतर बताएं। (बी) भारत में महिलाओं का स्वास्थ्य किस प्रकार बढ़ी चिंता का विषय बन गया है? व्याख्या करना।	2 4
34)	(a) (ए) भारत में श्रम बल के अनौपचारिकीकरण पर टिप्पणी करें। (b) (बी) श्रमिक-जनसंख्या अनुपात को परिभाषित करें। (c) या स्वतंत्रता के बाद से भारत में लागू गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के परिणामों की आलोचनात्मक जाँच करें।	4 2